www.navpradesh.com

दैनिक
नव प्रदेश
आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्
प्रदेश के साथ पूरा देश...

अंदर के पृष्ठों पर ◆◆ | 2 | छत्तीसगढ़ | 4 | अभिव्यक्ति | 11 | कारोबार/खेल

बिलासपुर, बुधवार, 29 अप्रैल 2026 | शुक्ल पक्ष-त्रयोदशी, | विक्रम संवत -2083 / वर्ष-12 अंक- 17 | पृष्ठ-12 मूल्य-5 रुपए | रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, जबलपुर व रांची से एक साथ प्रकाशित

श्रमिकों के सशक्तीकरण को मिली डिजिटल उड़ान, मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया 'ई-श्रम साथी' एप

■ प्रदेश के लाखों श्रमिकों को मिलेगा 'डिजिटल लेबर चौक' का सहारा, अब घर बैठे मिलेगी रोजगार की जानकारी

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज छत्तीसगढ़ के श्रम इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए ई-श्रम साथी मोबाइल एप (छत्तीसगढ़ डिजिटल लेबर चौक) का शुभारंभ किया। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का लक्ष्य ■ शेष पृष्ठ 8 पर

आंकड़ों में श्रमिक कल्याण

33.14 लाख
पंजीकृत श्रमिक

315 करोड़
उपकर संग्रहण: वर्ष 2025-26 में

2,558 करोड़
अब तक कुल व्यय

श्रमिक सीधे काम और योजनाओं से जुड़ सकेंगे

■ **डिजिटल क्रांति:** 'ई-श्रम साथी' एप के जरिए अब श्रमिक सीधे काम और योजनाओं से जुड़ सकेंगे।

■ **शून्य भ्रष्टाचार:** ई-केवाईसी के माध्यम से 55% सत्यापन पूरा, सीधे बैंक खातों में पहुँचेगा लाभ।

■ **सख्त प्रशासन:** औद्योगिक इकाइयों का होगा तकनीकी माध्यम से औचक निरीक्षण।

■ **शिक्षा पर जोर:** अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना में सीटें 100 से बढ़ाकर 200 की गई।

प्रमुख संचालित योजनाएं

- मिनीमाता महतारी जतन योजना (गर्भवती महिलाओं हेतु)
- दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना (स्वरोजगार हेतु)
- मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना (बेटियों हेतु)
- शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना (सुलभ भोजन)

मैदानी स्तर पर दिखे योजनाओं का प्रभाव: मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ केवल कागजों तक सीमित न रहे। उन्होंने कहा, फ्रयोजनाओं का वास्तविक प्रभाव तभी दिखाई देगा, जब लाभ कतार के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। उन्होंने प्रदेश में केंद्र सरकार की चार नई श्रम संहिताओं (मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा) के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया ताकि श्रमिकों को सम्मानजनक कार्य वातावरण मिल सके।

शिक्षा और भविष्य पर निवेश

सरकार ने श्रमिकों के बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत इस सत्र से सीटों की संख्या दोगुनी कर 200 कर दी है। वर्तमान में 31 जिलों के प्रतिभावान छात्र प्रदेश के नामी विद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ ही 'मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र' जैसे नवाचारों को और अधिक विस्तार देने के निर्देश दिए गए हैं बैठक में उपस्थित बैठक में मुख्य सचिव विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, श्रम सचिव हिमशिखर गुप्ता और विशेष सचिव रजत बंसल सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

आज बेबाक

पंजाब को उड़ता पंजाब बनाने वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान को यह डर सता रहा है कि मैंगो मेन पार्टी में उठी बगावत की आंधी उनके नीचे से सीएम की कुर्सी ही न उड़ा दे। आधा दर्जन सांसदों की तरह पंजाब के कई विधायक भी पाला बदलने के लिए पर तौल रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो मान साहब जल्द ही मेहमान बनकर रह जाएंगे। इसी टेंशन में वे कुछ भी बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा में दम है तो उन्हें खरीद कर दिखाए। अब उन्हें कौन समझाए कि खरीदा उसे जाता है जिसकी कुछ कीमत होती है।

तापमान

अधिकतम 45° | न्यूनतम 29°

बाजार भाव

गोल्ड	सिल्वर
1,55,830	2,64,900

शेयर बाजार

सेंसेक्स	निफ्टी
77,303.63	24,892.70

विश्व जनसंख्या	भारत जनसंख्या
8,289,644,926	1,474,583,419

न्यूज गैलरी

बालोद के तांदुला नहर में बाप-बेटी सहित तीन बहे, एक की मौत

बालोद/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में तांदुला नहर में नहाते समय पिता, बेटी और एक रिश्तेदार बच्ची तेज बहाव में बह गए। यह घटना मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे ग्राम पीपरछेड़ी में हुई। गोताखोरों ने पिता का शव बरामद कर लिया है, जबकि 12 साल की बेटी की तलाश अभी भी जारी है। वहीं, रिश्तेदार बच्ची को मौके पर मौजूद लोगों ने कूदकर बचा लिया। यह मामला बालोद थाना क्षेत्र का है। युवक अपने ससुराल पीपरछेड़ी गांव में शादी समारोह में शामिल होने आया था। यह मामला बालोद थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, ग्राम धोबनपुरी के यमन गंजीर अपनी बेटी पल्लवी गंजीर के साथ अपने ससुराल पीपरछेड़ी गांव में शादी समारोह में आए थे। मंगलवार को वे अपनी बेटी और रिश्तेदार बच्ची दामिनी साहू के साथ पास की तांदुला नहर में नहाने गए।

गरमा-गरम

कारोबारी गोपाल गांधी के भाइयों पर एफआईआर, भारतमाला मुआवजा घोटाले में 8 ठिकानों पड़ी थी रेड

66.9 लाख कैश और 37 किलो चांदी जब्त, अफसरों से बदसलूकी

धमतरी/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के चर्चित भारतमाला घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के चचेरे भाई भूपेंद्र चंद्राकर के ठिकानों पर देर रात तक छापेमारी की। साथ ही कुरूद में ही राइस मिलर रौशन चंद्राकर के यहां भी छापा मारा। इसके अलावा अभनपुर में भी ईडी की टीम ने कारोबारी गोपाल गांधी और उसके भाइयों के घर दबिश दी थी। यहां रेड के दौरान अफसरों से बदसलूकी और धक्का-मुक्की की गई। डिप्टी डायरेक्टर की शिकायत पर अभनपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अभनपुर टीआई सत्येंद्र श्याम ने एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की है।

अजय चंद्राकर के भाई के घर कार्रवाई की बात करें तो ईडी की टीम सोमवार सुबह करीब 6 बजे भूपेंद्र चंद्राकर के घर पहुंची थी। करीब 15 घंटे तक टीम जांच करती रही। करीब 1 बजे तक टीम कार्रवाई में जुटी रही, जिसके बाद वापस लौट गई। जांच के दौरान टीम अपने साथ दो थैलों में महत्वपूर्ण दस्तावेज, जमीन से जुड़े कागजात, एक मोबाइल और लगभग 8 से 9 लाख रुपये कैश लेकर गई है। ■ शेष पृष्ठ 8 पर

शिकायतों के आधार पर ईडी की जांच

भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में करीब 500 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले की आशंका जताई जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि कृषि भूमि को बैकडेट में गैर-कृषि घोषित कर उसका मुआवजा कई गुना बढ़ाया गया। साथ ही एक ही खसरे की जमीन को कागजों में अलग-अलग हिस्सों में बांटकर अलग-अलग लोगों के नाम पर भुगतान किया गया। ईडी इससे पहले भी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में छापेमारी कर करोड़ों की संपत्ति अटैच कर चुकी है।

पूर्व मंत्री के भाई के घर 15 घंटे जांच

अजय चंद्राकर के भाई के घर कार्रवाई की बात करें तो सुबह की टीम सोमवार सुबह करीब 6 बजे भूपेंद्र चंद्राकर के घर पहुंची थी। करीब 15 घंटे तक टीम जांच करती रही। करीब 1 बजे तक टीम कार्रवाई में जुटी रही, जिसके बाद वापस लौट गई। जांच के दौरान टीम अपने साथ दो बैलों में महत्वपूर्ण दस्तावेज, जमीन से जुड़े कागजात, एक मोबाइल और लगभग 8 से 9 लाख रुपये कैश लेकर गई है।

66.9 लाख कैश, चांदी की ईंटें जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 28 अप्रैल को छत्तीसगढ़ राज्य के अभनपुर, रायपुर, धमतरी और कुरूद स्थित 8 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई भारतमाला योजना के अंतर्गत रायपुर-विशाखापत्तनम हाईवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में मुआवजा राशि के अवैध प्राप्ति के मामले में की गई। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, 66.9 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा, 37.13 किलोग्राम वजनी चांदी की ईंटें तथा अन्य चांदी के सामान जब्त किए गए।

500 करोड़ रुपये का घोटाला

भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में करीब 500 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले की आशंका जताई जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि कृषि भूमि को बैकडेट में गैर-कृषि घोषित कर उसका मुआवजा कई गुना बढ़ाया गया।

बदसलूकी पर एफआईआर

अभनपुर में ईडी की टीम जब दस्तावेज और अन्य सबूत जुटाने की कार्रवाई कर रही थी, तभी सत्यनारायण गांधी और जय प्रकाश गांधी ने टीम को रोकने की कोशिश की। आरोप है कि दोनों ने ईडी के डिप्टी डायरेक्टर नीरज कुमार सिंह और टीम के अन्य सदस्यों के साथ धक्का-मुक्की की और कार्रवाई में बाधा डाली।

आतंकवाद के गढ़ अब नहीं बचेंगे: राजनाथ सिंह

शंघाई/ए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के इस दृढ़ संकल्प को दिखाया है कि आतंकवाद के गढ़ अब न्यायोचित दंड से अछूते नहीं रहेंगे।

आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील: राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने के लिए सभी देशों को एकजुट होकर काम करना होगा। इसमें आतंकवादियों को शरण देने वाले सुरक्षित ठिकानों को ■ शेष पृष्ठ 8 पर

'आतंकवाद की कोई राष्ट्रीयता नहीं'

रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि आतंकवाद की कोई राष्ट्रीयता या विचारधारा नहीं होती और इसके खिलाफ वैश्विक स्तर पर समूहिक व दृढ़ रुख अपनाना समय की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एससीओ को आतंकवादियों को उकसाने, आश्रय देने और सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराने वालों के खिलाफकार्रवाई करने में हिचकियाना नहीं चाहिए।

होर्मुज खोलने को तैयार, ईरान बोला- ट्रम्प का दबाव नहीं सहेंगे

■ अमेरिका अब दूसरे देशों पर फैसले थोपने की स्थिति में नहीं

तेहरान/वॉशिंगटन डीसी। ईरान ने मंगलवार को कहा कि अब अमेरिका उस स्थिति में नहीं है कि वह दूसरे देशों को बताए कि उन्हें क्या करना चाहिए। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रेजा तलाएई-निक ने सरकारी टीवी से कहा कि वे ट्रम्प का दबाव नहीं सहन करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपनी गलत मांगों को छोड़ना ही होगा।यह बयान उस समय आया है जब अमेरिका, होर्मुज को खोलने से जुड़े ईरान के नए प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच फिलहाल युद्धविराम लागू है, लेकिन इस संघर्ष को पूरी तरह खत्म करने के लिए जो बातचीत चल रही है, उसमें अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। इस बीच ईरान पहली बार होर्मुज खोलने को तैयार हो गया है। ईरान ने अमेरिका से समुद्री नाकेबंदी हटाने की भी अपील की है।

चौथिया से लौट रहे परिवार पर मौत का कहर

■ तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, 3 की मौके पर मौत, मासूम भी नहीं बचा

कोरबा/नवप्रदेश। चांपा-कोरबा मार्ग सोमवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे का गवाह बना, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। ग्राम कोथारी और टोल प्लाजा के बीच तेज रफ्तार कार अचानक डिवाइडर से जा भिड़ी और कुछ ही सेकंड में कबाड़ में तब्दील हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे

उड़ गए और मौके पर ही तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें एक ढाई साल का मासूम भी शामिल है।

जानकारी के मुताबिक, कोरबा के बुधवारी काशीनगर बस्ती निवासी सोनी परिवार शादी समारोह में शामिल होने चांपा गया था। चौथिया की रस्म निभाने के बाद देर रात करीब 2 बजे सभी कार से वापस लौट रहे थे। तभी टोल नाके के पास अचानक कार अनियंत्रित हो गई, पहले डिवाइडर से टकराई और फिर पलटते हुए सड़क किनारे खड़ी हाइवा में जा घुसी। हादसे ■ शेष पृष्ठ 8 पर

पंजाब-रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट करने वाले चार आतंकी गिरफ्तार

राजपुरा(पटियाला)। पंजाब में पटियाला के राजपुरा में अंबाला-अमृतसर रेल ट्रेक कॉरिडोर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और खालिस्तानी आतंकियों ने कराया था। यह दावा पटियाला पुलिस ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद किया। पटियाला रेंज के डीआईजी कुलदीप चहल ने बताया कि धमाके के बाद कार्रवाई करते हुए प्रदीप सिंह खालसा, कुलविंदर सिंह बंगा, सतनाम सिंह सत्ता और गुरप्रीत सिंह गोपी को गिरफ्तार किया है।

दूसरे चरण का महासंग्राम आज ममता-मोदी की साख दांव पर

कोलकाता/वार्ता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण का रण सज चुका है। बुधवार, 29 अप्रैल को 8 जिलों की 142 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में हुए 93अ के रिकॉर्ड मतदान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। जहाँ तृणमूल कांग्रेस अपने इस अभेद्य किले को बचाने की जद्दोजहद में है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तूफानी प्रचार के दम पर भाजपा इस बार दक्षिण बंगाल के समीकरण बदलने के लिए बेताब है।

भवानीपुर का संग्राम: इस

चरण की सबसे हॉट सीट भवानीपुर है, जहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला सीधे नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी से है। यहाँ 21% मतदाताओं के नाम कटने (एसआईआर प्रक्रिया) को लेकर विवाद गहराया हुआ है।

मतुआ और नागरिकता का मुद्दा: नदिया और उत्तर 24 परगना में ■ शेष पृष्ठ 8 पर

गुजरात निकाय चुनाव- सभी 15 नगर निगमों में भाजपा की जीत

अहमदाबाद/ए। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों के मंगलवार को वोटों की गिनती जारी है। बीजेपी ने सभी 15 नगर निगमों पर जीत दर्ज कर ली है। इनमें मेहसाणा, मोरबी, नाडियाड और वापी ऐसे नगर निगम है, जहां पहली बार चुनाव हुए थे। मेहसाणा, मोरबी और नडियाद में कांग्रेस को अब तक एक भी सीट नहीं मिली है। अहमदाबाद में गिनती के दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। वहीं, क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की बहन नयनाबा कांग्रेस की टिकट पर राजकोट से हार गईं है।

विडंबना : बैंक कर्मचारियों ने कहा था- जिसका खाता उसे लेकर आओ, दफन शव को खोदकर बाहर निकाला

बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंचा शख्स, 3 किमी पैदल चला

क्योंझर/ए। ओडिशा के क्योंझर में सोमवार को हैरान करने वाला मामला सामने आया। आदिवासी जीतू मुंडा अपनी मरी हुई बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया। कंकाल देख बैंक में अफरा-तफरी मच गई।

दरअसल, जीतू अपनी बहन कलारा मुंडा के खाते से 20 हजार रुपए निकालना चाहता था, इसके लिए वह कई बार बैंक भी गया। लेकिन कर्मचारियों ने खाता धारक को लाने को कहा। जीतू बैंक में पहले ही कलारा की मौत की जानकारी दे चुका था। फिर भी उसे कोई मदद नहीं मिली, इससे परेशान होकर उसने कब्र से कंकाल निकालकर बैंक में पेश किया। बहन का कंकाल कंधे पर लेकर जीतू करीब 3 किमी पैदल चला। फिर मक्षिपसी में बने ओडिशा ग्रामीण बैंक बांच के बरामदे में कंकाल को रख दिया। इसे देख वहां मौजूद लोग हैरान रह गए।

पुलिस के अनुसार, जीतू अनपढ़ है और कानूनी प्रक्रिया से अनजान था। प्रशासन ने उसे नियम समझाए और जल्द पैसे दिलाने का भरोसा दिया। इसके बाद शव को दोबारा कब्रिस्तान में दफना दिया गया।

कंकाल देखकर बैंक कर्मचारियों ने पुलिस बुलाई

पुलिस के अनुसार, जीतू पढ़ा-लिखा नहीं है। आदिवासी है और कानूनी प्रक्रिया से पूरी तरह अनजान है। थाने के प्रभारी निरीक्षक किरण प्रसाद साहू ने कहा, जीतू को नहीं पता कि कानूनी वारिस या नॉमिनी क्या होता है। बैंक अधिकारी भी उसे मृतक के खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया नहीं समझा पाए। पुलिस ने जीतू मुंडा को आश्वासन दिया कि वे उसकी मृत बहन के बैंक खाते से पैसे निकलवाने में मदद करेंगे। बाद में पुलिस की मौजूदगी में शव को दोबारा कब्रिस्तान में दफना दिया गया।

जीतू को बहन के खाते में जमा रुपए चाहिए

डियानाली गांव का रहने वाला जीतू मुंडा जिस महिला का कंकाल लेकर बैंक पहुंचा, वह उसकी बड़ी बहन कालारा मुंडा थी। कालरा की मौत 26 जनवरी 2026 को हो गई थी। कालरा मुंडा के बैंक खाते में नॉमिनेट पति और बेटे की भी मौत हो चुकी है। इसलिए उनके नाम पर जमा पैसे का जीतू मुंडा ही एकमात्र दावेदार है। आर्थिक स्थित ठीक नहीं होने के कारण उनके लिए यह रह पैसा रकम अहम थी और जीवनयापन का सहारा मानी जा रही थी।

इंतजार खत्म, आज जारी होंगे सीजी बोर्ड के नतीजे

■ 10वीं और 12वीं में 5.66 लाख छात्र-छात्राओं ने दी है परीक्षा

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के नतीजे 29 अप्रैल को दोपहर ढाई बजे जारी होंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के परिणाम औपचारिक रूप से घोषित करेगा।

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी। बता दें कि इस साल 10वीं-12वीं के टोटल 5.66 स्टूडेंट्स ने बोर्ड एग्जाम दिया था। छात्र अपना रिजल्ट मंडल की वेबसाइट पर

रोल नंबर डालकर सीधे देख सकते हैं। छात्रों की साल भर की मेहनत, तैयारी और उम्मीदों का परिणाम आज सामने होगा।

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने स्टूडेंट्स से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें और रिजल्ट को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करें। अच्छे नंबर आने पर आगे की तैयारी में जुटें, वहीं अपेक्षा के अनुरूप ■ शेष पृष्ठ 8 पर

संक्षिप्त खबरें

संगीत विश्वविद्यालय को मिली 55 सीटर बस, राज्यपाल ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

खैरागढ़/नवप्रदेश। इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को स्वीकृत 55 सीटर एसी बस को राज्यपाल एवं विवि के कुलाधिपति रमेन डेका ने रायपुर स्थित लोकभवन में हरी झंडी दिखाकर संगीत विवि के लिए रवाना किया । विश्वविद्यालय कुलपति डॉ. लवली शर्मा ने विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन से एसी बस एवं एम्बुलेंस की मांग की थी। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए शासन ने 55 सीटर एसी बस एवं एम्बुलेंस दोनों की स्वीकृति प्रदान की। स्वीकृति के उपरांत बस विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दी गई है, एम्बुलेंस सुविधा भी शीघ्र ही उपलब्ध होने वाली है। बस के विश्वविद्यालय पहुंचते ही कुलपति द्वारा पूजा अर्चना की गई। इस दौरान विश्वविद्यालय के अधिकारी कर्मचारियों ने बस सुविधा मिलने पर खुशी जाहिर की और विश्वविद्यालय के लिए इसे बड़ी उपलब्धि बताई। इस नई बस सुविधा के शुरू होने से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों एवं राज्य के बाहर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति देने जाने वाले छात्रों के लिए आवागमन अब अधिक सुगम और सुविधाजनक हो जाएगा।

ठेकेदार ने पेयजल पाईप लाइन को कर दिया ध्वस्त, जलापूर्ति ठप

जगदलपुर/नवप्रदेश। सड़क निर्माण करा रहे ठेकेदार के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते कमिश्नर ऑफिस के बाजू गली में कल दोपहर से पेयजल की पाईप लाइन फूट गई है। इस कारण नयामुंडा वार्ड और आसपास के वार्डों में जलापूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो गई है। हालांकि नगर निगम का जल कार्य विभाग सक्रियता के साथ पाईप लाइन की मरम्मत में जुट गया है, मगर सवाल यह है कि उस लापरवाह ठेकेदार पर क्या कार्रवाई की जाएगी, जिसने सैकड़ों परिवारों को पानी के लिए तरसा दिया है। बताया गया है कि आयुक्त कार्यालय के बाजू गली आईडीबीआई बैंक के सामने सड़क का निर्माण एक ठेकेदार के माध्यम से कराया जा रहा है। ठेकेदार ने नगर निगम से पाईप लाइनों की जानकारी प्राप्त किए बगैर 7सी खोदाई शुरू करवा दी कि पेयजल की पाईप लाइन ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसके चलते नया मुंडा क्षेत्र के बड़े भाग में पेयजल की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है। नगर निगम का जल कार्य विभाग पाईप लाइन की मरम्मत में जुटा हुआ है और आज रात्रि तक काम पूरा हो जाने की उम्मीद है। वैसे भी ग्रीष्म ऋतु आने के साथ ही नगर के कई वार्डों पानी की परेशानी हो रही है। ऊपर से कल ही कमिश्नर कार्यालय के समीप एक बड़ी पाइप टूटने से वार्डवासियों को पानी की किल्लत हो गई है। वहीं नगर निगम के जल विभाग सभापति सुरेश गुप्ता के अनुसार पाईप लाइन की मरम्मत कार्य शुरू है आज शाम तक बनने की संभावना है।

अकाल पुरख की फौज के शहर अध्यक्ष बने राजा चावला

भाटापारा /नवप्रदेश। अकाल पुरख की फौज राष्ट्रीय कोर कमेटी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश की संपूर्ण टीम की विधिवत घोषणा रविवार कर दी,जिसमें अमरजीत सिंह दत्ता को प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश सलाहकार के रूप मे अमरजीत सिंह सलूजा तथा भाटापारा शहर अध्यक्ष के रूप में रविंद्र सिंह चावला (राजा चावला) को नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में प्रदेश टीम को नई दिशा और नई ऊर्जा प्रदान की गई। राष्ट्रीय कोर कमेटी में प्रमुख रूप से ज्ञानी केवल सिंह जी ङ्ग साबका जत्थेदार, दमदमा साहिब सरदार जसविंदर सिंह एडवोकेट ङ्ग संस्थापक, अकाल पुरख की फौज सरदार बलविंदर सिंह जोड़ा ङ्ग सचिव, सिख विधायक बोर्ड तथा प्रमुख रूप से सरदार रणजीत सिंह,राज्य प्रमुख, उड़ीसा सरदार खुशकंवल सिंह ,राज्य प्रमुख, महाराष्ट्र सरदार सुखदर्शन सिंह , वरिष्ठ पदाधिकारी, बैतूल (मध्यप्रदेश) के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष एवं संपूर्ण टीम की नियुक्ति संपन्न हुई। इस नियुक्ति में अमरजीत सिंह दत्ता को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया,वही संगठन के अध्यक्ष मंडल के रूप में बलदेव सिंह भाटिया , गुरमुख सिंह होरा , जगजीत सिंह खनूजा , अमरजीत सिंह छाबड़ा एवं प्रीतपाल सिंह होराको दायित्व सौंपा गया।

91 दर्शनार्थी 29 अप्रैल को विशेष ट्रेन से होंगे रवाना

राजनांदगांव/नवप्रदेश। श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत जिले के 91 श्रद्धालु 29 अप्रैल को विशेष ट्रेन के माध्यम से अयोध्या धाम के लिए रवाना होंगे। इस संबंध में अपर कलेक्टर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। जिसमें यात्रा के दौरान यात्रियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की व्यवस्था पर विस्तृत से समीक्षा की गई। अपर कलेक्टर ने यात्रा के दौरान यात्रियों के ठहरने, भोजन, पेयजल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ-साथ गर्मी से बचाव के विशेष उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने कहा। उप संचालक समाज कल्याण श्रीमती वैशाली मरडवार ने बताया कि यात्रा 29 अप्रैल से 2 मई 2026 तक संचालित होगी। यात्रा से पूर्व सभी दर्शनार्थियों के लिए राजनांदगांव शहर में स्थानीय उदयाचल भवन में ठहरने की व्यवस्था की गई है। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

ग्राम सभाओं में देगे जनगणना 2027 को लेकर ग्रामीणों को जानकारी

महासमुंद / नवप्रदेश। जिले भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर आगामी जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर जागरूकता बढ़ाई जा रही है। इसी क्रम में ग्राम अचरीडीह में आयोजित विशेष ग्राम सभा में ग्रामीण जनगणना चार्ज अधिकारी एवं तहसीलदार जुगल किशोर पटेल मुख्य रूप से उपस्थित रहेसभा को संबोधित करते हुए तहसीलदार ने जनगणना 2027 के महत्व और इसकी प्रक्रिया के बारे में ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार जनगणना को अधिक पारदर्शी, सरल और प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल प्रणाली को अपनाया जा रहा है, जिसमें स्वगणना की सुविधा भी प्रमुख रूप से शामिल है।उन्होंने ग्रामीणों को स्वगणना के महत्व को समझाते हुए अधिक से अधिक लोगों को इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। साथ ही जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जनगणना को लेकर जागरूकता फैलाएं, ताकि कोई भी व्यक्ति इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया से वंचित न रहे। ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए जनगणना कार्य में पूर्ण सहयोग देने का भरोसा दिलाया।

लालबगीचा में बन रहे आंगनबाड़ी केंद्र में भ्रष्टाचार की लाल ईंटें

■ **गुणवत्ता की अनदेखी से बच्चों के भविष्य पर मंडराया खतरा, युवा कांग्रेस ने किया निगम के बाहर प्रदर्शन**

धमतरी/नवप्रदेश। शहर के लालबगीचा वार्ड में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। शासन के स्पष्ट निर्देशों और वर्कऑर्डर की शर्तों को दरकिनार कर ठेकेदार द्वारा न केवल प्रतिबंधित सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, बल्कि निर्माण की गुणवत्ता से भी गंभीर समझौता किया जा रहा है। वार्डवासियों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने सुध नहीं ली, तो भविष्य में यहाँ कोई बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है।

प्रतिबंधित लाल ईंटों का धड़ल्ले से उपयोग: शासकीय नियमों और वर्कऑर्डर के अनुसार, सरकारी निर्माण कार्यों में लाल ईंटों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। पर्यावरण संरक्षण और मजबूती के लिहाज से फ्लाई ऐश ईंटों का प्रावधान है, लेकिन लालबगीचा में बन रहे इस आंगनबाड़ी केंद्र में ठेकेदार द्वारा खुलेआम लाल ईंटों का उपयोग किया गया है। यह न केवल शासकीय नियमों का उल्लंघन है, बल्कि विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगाता है।

तकनीकी खामियां और सुरक्षा से खिलवाड़: मौके पर देखने से स्पष्ट होता है कि निर्माण कार्य में तकनीकी मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है। कॉलम वर्क में लापरवाही कॉलम की ढलाई और उसकी सेटिंग (सब्लिंग) का कार्य अत्यंत निम्न स्तर का है, जिससे इमारत की नींव कमजोर होने का अंदेशा है।कंक्रीट और ईंटों की जुड़ाई के बाद पर्याप्त तराई नहीं की जा रही है, जिससे निर्माण की मजबूती प्रभावित हो रही है। यह भवन नन्हे बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। ऐसे में गुणवत्ताहीन कार्य भविष्य में किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है।

सामुदायिक संपदा का दुरूपयोग- ठेकेदार की मनमानी यहीं नहीं रुकती। निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार द्वारा पास ही स्थित सामुदायिक भवन के पानी का अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा है।

प्रशासन से जांच की मांग

लालबगीचा वार्ड के जागरूक नागरिकों ने कलेक्टर और संबंधित विभागीय अधिकारियों से मांग की है कि तत्काल निर्माण स्थल का निरीक्षण कर घटिया सामग्री के उपयोग पर रोक लगाई जाए। साथ ही, नियमों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य को मानक स्तर पर सुनिश्चित कराया जाए। इस प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष नरेंद्र सोनवानी,जिलाउपाध्यक्ष प्रवीणसाहू, गीतराम सिन्हा,नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर, उपनेता प्रतिपक्ष विशु देवांगन,विकास साहू,अनिल पटवा,देवा ,अनस रजा व युवा कांग्रेस के अन्य साथी सहित वार्डवासी उपस्थित रहें।

पहली बार शुरू हुआ संगठित संग्रहण, जिले में 35 हजार से अधिक बोरा तेंदूपत्ता जुटा

बंदूक की गूंज से निकला गोगुंडा तेंदूपत्ता बना ग्रामीणों के आजीविका का सहारा

सुकमा/नवप्रदेश। कभी नक्सल प्रभाव के कारण भय और बंदूक की गूंज से पहचाने जाने वाले गोगुंडा की पहाड़ियां अब बदलती तस्वीर पेश कर रही हैं। दुर्गम वनांचल में अब तेंदूपत्ता संग्रहण के जरिए रोजगार और विकास की नई राह खुली है। वन विभाग ने यहां पहली बार व्यवस्थित रूप से संग्रहण कार्य शुरू कर स्थानीय आदिवासी समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की पहल की है।

गोगुंडा और मिचिगुडा में दो नए पद्द स्थापित किए गए हैं, जहां इस सीजन में 200 से अधिक मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण का अनुमान है। इससे क्षेत्र के वनवासियों को सीधे आय का लाभ मिलने लगा है और गांवों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है।

इस बदलाव के पीछे सुरक्षा बलों की लगातार मौजूदगी और शांति बहाली के प्रयासों की अहम भूमिका रही है। सुरक्षित माहौल बनने से अब शासकीय योजनाएं दूरस्थ इलाकों तक पहुंच रही हैं और वन विभाग को भी रोजगार आधारित गतिविधियां शुरू करने का अवसर मिला है।

वर्षों तक नक्सल प्रभाव के चलते यह इलाका विकास से अछूता रहा। ग्रामीणों को वनोपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, लेकिन अब सरकारी पहल और बाजार व्यवस्था से उनकी आमदनी में बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है। तेंदूपत्ता संग्रहण न केवल रोजगार का माध्यम बन रहा है, बल्कि शासन और ग्रामीणों के बीच भरोसे को भी मजबूत कर रहा है।

इधर, पूरे जिले में तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य तेजी से जारी है। वन विभाग के अनुसार सुकमा में 727 पद्द संचालित हैं, जिनमें से करीब 350 में संग्रहण और खरीदी शुरू हो चुकी है। अब तक 35 हजार से अधिक मानक बोरा तेंदूपत्ता एकत्र किया जा चुका है, जबकि शेष केंद्रों में भी जल्द काम शुरू होने वाला है।

डीएफओ अक्षय भोंसले ने स्पष्ट किया कि संग्रहण कार्य पूरी तरह जारी है और इसे बंद किए जाने की खबरें भ्रामक हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र संग्राहक से तेंदूपत्ता खरीदा जाएगा और प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित हो रही है।

किस्तराम, गोलापल्ली, कोंटा और जगरगुंडा जैसे क्षेत्रों में भौगोलिक कारणों से पत्ते देर से तैयार होते हैं, इसलिए वहां आगामी दिनों में संग्रहण शुरू किया जाएगा। वहीं हालिया ओलावृष्टि के चलते कुछ जगहों पर गुणवत्ता प्रभावित हुई है, लेकिन मानक के अनुरूप पत्तों की खरीदी लगातार जारी है।

अब गोगुंडा की पहाड़ियों पर जहां कभी असुरक्षा का माहौल था, वहीं आज तेंदूपत्ता संग्राहकों की चहल-पहल और विकास की नई आहट सुनाई दे रही है। यह बदलाव संकेत दे रहा है कि समन्वित प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं।

जगदलपुर के संजय मार्केट में वन्यजीव तस्करी पर वन विभाग की टीम ने की छापेमारी

टीम ने 13 तोते के बच्चों को बरामद किया

जगदलपुर/नवप्रदेश। जगदलपुर के संजय मार्केट में वन्यजीव तस्करी का मामला सामने आने पर वन विभाग की टीम ने छापेमारी की। मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई में टीम ने 13 तोते के बच्चों को बरामद किया, जिन्हें अवैध रूप से बेचा जा रहा था। वन अमले ने तुरंत उन्हें अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित किया।छापेमारी के दौरान माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। मौके पर मौजूद तस्करों ने विरोध करते हुए वन विभाग की टीम पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई और टीम के सदस्यों के साथ हाथापाई शुरू हो गई।हमले के दौरान तस्करों ने वन विभाग के दो अधिकारियों को पकड़ लिया और उन्हें रस्सी से बिजली के खंभे से बांध दिया। इसके बाद उनके साथ मारपीट की गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए।

घटना के बाद वन विभाग ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। यह घटना वन्यजीव संरक्षण कानूनों की खुलेआम अनदेखी को दर्शाती है। साथ ही यह भी साफ करता है कि तस्करों के हौसले कितने बुलंद हैं। ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई और अधिकारियों की सुरक्षा के मजबूत इंतजाम जरूरी हो गए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।लीलाधर राठौर टीआई कोतवाली ने बताया कि रेंजर अक्षय कश्यप अपनी टीम के साथ संजय मार्केट पहुंचे थे, तोते को लेने पहुंचे थे, 2 लोग इसका विरोध करने लगे।

गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने राष्ट्रपति एवं पीएम के नाम एसडीएम को सौंपा प्रार्थना पत्र

भाटापारा/ नवप्रदेश। गौ सम्मान आवाहन अभियान के तहत भारतवर्ष के 5000 तहसीलों के साथ भाटापारा में भी सोमवार को भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम प्रार्थना पत्र तहसील कार्यलय जा कर एस डी एम को सौपा गया।पत्र में

गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो ,गौ रक्षा मंत्रालय का निर्माण हो,अखिल गोवंश की हत्या बंद हो की प्रमुख मांग रखी गई। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत भारत माता चौक से सुबह 10 बजे पैदल यात्रा प्रारंभ हुई। यात्रा को दिव्य बनाने के लिए यात्रा की

अगुवाई स्वयं गौ माता कर रही थी। छोटे छोटे बछड़े भी सज धज कर यात्रा के साक्षी बन रहे थे। वही कुछ गौ भक्तों ने पैदल यात्रा के आगे दंडवती यात्रा भी की। यात्रा में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष के साथ युवा वर्ग शामिल हुआ। भगवत संकीर्तन,भगवा झंडे और जयकारों के साथ यात्रा निकली। जिसका जगह जगह सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों ने स्वागत किया।तहसील कार्यलय में राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन महिला वर्ग, प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन पुरुष वर्ग एवं मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम का ज्ञापन युवा वर्ग ने अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार को सौपा। इस अवसर पर समिति के सदस्य अभिषेक उपाध्याय(बंटी) ने कहा कि भारतीय सनातनी परंपरा संस्कृति में गौ माता का विशिष्ट स्थान है। 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता मे होता है।

गरीबों के लिए संबल बने जनपद अध्यक्ष संजय सिन्हा

छुरिया/नवप्रदेश। जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत टीपनगढ़ में ईसानियत और जनसेवा की एक मार्मिक तस्वीर सामने आई, जहां जनपद अध्यक्ष संजय सिन्हा ने एक जरूरतमंद वृद्ध महिला की मदद कर समाज के सामने संवेदनशील नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया। गांव की वृद्ध महिला फुलेश्वरी बाई साहू बीते तीन महीनों से पेंशन न मिलने के कारण गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही थीं। दो वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष कर रही इस महिला की हालत की जानकारी मिलते ही संजय सिन्हा बिना देर किए सीधे उनके घर पहुंचे। वृद्धा के कच्चे घर और अभावों से घिरी जिंदगी को देखकर वे भावुक हो उठे। महिला ने बताया कि वह मात्र 7 किलो राशन और बंद पड़ी पेंशन के सहारे जीवन गुजारने को मजबूर हैं। घर में बिजली जैसी मूलभूत सुविधा भी नहीं है, जिससे उनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए संजय सिन्हा ने मौके पर ही संबंधित कार्यकर्ताओं को आवश्यक दस्तावेज तैयार कराने के निर्देश दिए, ताकि शीघ्र ही बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सके और पेंशन बहाली की प्रक्रिया तेज हो। साथ ही उन्होंने वृद्ध महिला को तत्काल आर्थिक सहायता देकर राहत पहुंचाई। इस मानवीय पहल ने यह साबित कर दिया कि संजय सिन्हा सिर्फ पद तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन से जुड़े जनप्रतिनिधि हैं, जो हर जरूरतमंद के साथ खड़े रहते हैं।

ग्रामीणों ने उनकी इस संवेदनशीलता की खुलकर सराहना की और कहा कि ऐसे जनप्रतिनिधि ही वास्तव में समाज की उम्मीद होते हैं। क्षेत्र में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि संजय सिन्हा हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे रहते हैं और जमीनी स्तर पर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। इस दौरान डोमन पटेल, मोनू गुप्ता, टीकम साहू, दरबार साहू, अशोक साहू और अमृत लाल साहू सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।

महतारी वंदन योजना में ई-केवाईसी अभियान तेज

■ **1.57 लाख हितग्राहियों का सत्यापन पूरा**

महासमुंद / नवप्रदेश। जिले में महतारी वंदन योजना के तहत हितग्राहियों का ई-केवाईसी कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी टिकेन्द्र जटवार ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुए इस विशेष अभियान के अंतर्गत कुल 3 लाख 3 हजार 808 हितग्राहियों का ई-केवाईसी 30 जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

1 लाख 57 हजार 359 हितग्राहियों का ई-केवाईसी सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है, जबकि शेष 1 लाख 46 हजार 449 हितग्राहियों का ई-केवाईसी 30 जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

वंदे मातरम् संघर्ष, त्याग और बलिदान की प्रेरणा

भाटापारा/नवप्रदेश। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भाटापारा इकाई द्वारा आईटीआई महाविद्यालय परिसर में राष्ट्रभावना एवं देशभक्ति को जागृत करने हेतु परिसर-परिसर वंदे मातरम् अभियान का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय परिसर देशभक्ति के नारों एवं वंदे मातरम् के जयघोष से गूंज उठा। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य अजय गरहेवाल एवं सभी प्राध्यापकगण और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कुल 50 विद्यार्थियों की सहभागिता रही, जिसमें 32 छात्र एवं 18 छात्राएं सम्मिलित हुए। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक अभियान में भाग लेकर राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा एवं समर्पण का परिचय दिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एसएफडी प्रमुख दीपेश शर्मा ने कहा कि वंदे मातरम् केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत माता के प्रति श्रद्धा, सम्मान और समर्पण का प्रतीक है। यह गीत अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान की प्रेरणा रहा है। आज पूरे देश में 'परिसर-परिसर वंदे मातरम् अभियान' इसलिए चलाया जा रहा है। क्योंकि वंदे मातरम् के 150वें वर्ष पूर्ण होने का यह ऐतिहासिक अवसर है। यह हम सभी युवाओं के लिए गर्व का विषय है कि हम इस गौरवशाली धरोहर को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि "विद्यार्थी परिषद सदैव राष्ट्रहित, छात्रहित और समाजहित के कार्यों में अग्रणी रही है। हमारा उद्देश्य केवल शैक्षणिक विकास नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में राष्ट्रीय चेतना, अनुशासन और संस्कारों का विकास करना भी है। आज का युवा यदि अपने इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रगौरव को समझेगा, तभी भारत सशक्त और आत्मनिर्भर बनेगा। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर कार्यकारिणी सदस्य सार्थक मिश्रा ने भी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा शक्ति ही राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। हमें अपने महापुरुषों के आदर्शों पर चलकर राष्ट्रहित के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। वंदे मातरम् हम सभी के भीतर देशभक्ति की भावना जागृत करता है और हमें अपने कर्तव्यों का स्मरण कराता है।»

ताम्रकार समाज का सामूहिक विवाह समारोह बना मिशाल

22 वर्षों से निरंतर जारी, 7 जोड़े बंधे वैवाहिक बंधन में

धमधा / नवप्रदेश। ताम्रकार समाज द्वारा आयोजित आदर्श सामूहिक विवाह समारोह का भव्य आयोजन रविवार को तमेर पारा, धमधा में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम हैहयवंशी क्षत्रिय ताम्रकार समाज कल्याण समिति के तत्वावधान में आयोजित किया गया, जिसमें 7 नवदंपति जोड़ों का विधि-विधान से विवाह कराया गया।

उल्लेखनीय है कि यह आयोजन विगत 22 वर्षों से लगातार किया जा रहा है और अपनी सादगी, सामाजिक एकता एवं सुव्यवस्थित व्यवस्था के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में विशेष पहचान बना चुका है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में विवाह के अनावश्यक खर्चों को कम करना तथा जरूरतमंद परिवारों को सहयोग प्रदान करना है।

समारोह में हजारों की संख्या में समाजजन उपस्थित रहे और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विजय बघेल (सांसद, दुर्ग लोकसभा), विशिष्ट अतिथि ईश्वर साहू (विधायक, साजा), जितेंद्र साहू (अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड), श्रेता प्रशांत अग्रवाल (अध्यक्ष, नगर पंचायत धमधा) तथा पवन शर्मा (उपाध्यक्ष, जिला पंचायत) उपस्थित रहे।

इस अवसर पर सांसद विजय बघेल ने समाज के भवन निर्माण एवं बाउंड्रीवॉल के लिए आर्थिक सहयोग देने की घोषणा की।

कार्यक्रम में समाज के संरक्षक दाऊ मिनेशचंद ताम्रकार, श्रवण ताम्रकार, समाज के अध्यक्ष नीलकमल ताम्रकार (नील्) एवं सचिव विमलचंद ताम्रकार सहित समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे।

समाज के पदाधिकारियों द्वारा सभी नवदंपतियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर समाज के पदाधिकारियों ने सभी सहयोगियों एवं उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया।

पंचायती राज दिवस पर पंचायतों मे ग्राम सभा का आयोजन

खैरागढ/नवप्रदेश। पंचायती राज दिवस पर जिले की सभी 221 ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। पंचायतों मे आयोजित ग्राम सभाओं में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी के बीच विशेष रुप से आगामी जनगणना 26 के संबंध में आम नागरिकों को जागरूक किया गया। ग्राम सभाओं में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा स्वगणना की प्रक्रिया, उसके महत्व एवं इससे होने वाले लाभों की विस्तृत जानकारी दी गई।

मौसम बदला, द्रोणिका सक्रिय, गरज-चमक के साथ आज हल्की बारिश की संभावना

बिलासपुर/नवप्रदेश। *प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने मंगलवार शाम 3 घंटे के लिए थंडरस्टॉर्म का अलर्ट जारी किया है। शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। कुछ इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।*

पश्चिमी विक्षोभ द्रोणिका के रूप में 5.8 किलोमीटर ऊंचाई पर 66 डिग्री पूर्व और 30 डिग्री उत्तर में स्थित है। एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण पूर्वी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। एक पूर्व पश्चिम द्रोणिका हरियाणा से मणिपुर तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। दूसरा द्रोणिका/हवा की अनियमित गति उत्तर तेलंगाना से कोमोरिन क्षेत्र तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। एक प्रति चक्रवात अंदरूनी महाराष्ट्र और उससे लगे कर्नाटक के ऊपर 3.1 किलोमीटर से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। प्रदेश के दक्षिणी भाग में बंगाल की खाड़ी से, वातावरण के निम्न स्तर पर नमी आ रही है, जिसके कारण प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में एक-दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा वज्रपात होने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में गिरावट का दौर प्रारंभ होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, कोरबा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, मुंगेली और कोरिया में गरज-चमक के साथ तूफान का अलर्ट जारी किया है।

वार्म नाइट का भी खतरा

मौसम विभाग ने गर्म रातों को लेकर भी चेतावनी दी है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री ज्यादा होने पर वार्म नाइट और इससे अधिक होने पर वेरी वार्म नाइट माना जाता है। ऐसी स्थिति में रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिलती।

इन जिलों में हल्की आंधी-बारिश की चेतावनी

जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कबीरधाम, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर में 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने, गरज-चमक और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। किसानों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। तेज आंधी और बारिश से कई इलाकों में गर्मी से राहत मिल सकती है। बीते दिनों पड़ रही भीषण गर्मी के बीच इस बदलाव से तापमान में गिरावट की संभावना जताई गई है।

गर्मी से बचाव जरूरी

मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि तेज गर्मी और लू से बचने के लिए दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और धूप में निकलते समय सिर और शरीर को ढककर रखें। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक विदर्भ से लेकर दक्षिण भारत तक ट्रफ लाइन और बंगाल-ओडिशा क्षेत्र में ऊपरी हवा के चक्रवाती प्रभाव के चलते गर्म और शुष्क हवाओं का असर बना हुआ है। इसी वजह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है।

डिजिटल एजुकेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय की बड़ी छलांग

एमबीए, एमकॉम सहित 10 ऑनलाइन कोर्स को सीजी से मिली हरी झंडी

बिलासपुर/नवप्रदेश। *पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा 10 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (02 स्नातक एवं 08 स्नातकोत्तर) के संचालन की मान्यता प्रदान की गई है। यह उपलब्धि विश्वविद्यालय के लिए ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगी, जिससे प्रदेश में डिजिटल शिक्षा को नई गति मिलेगी।*

विद्यार्थी सुविधा अनुसार कर सकेंगे अध्ययन

ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को अनेक व्यावहारिक लाभ मिलेंगे। वे अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी और कभी भी अध्ययन कर सकेंगे, जिससे समय और स्थान की बाधाएं समाप्त होंगी। नौकरीपेशा, गृहिणी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी एवं दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थी भी आसानी से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए रिकॉर्डेड लेक्चर बार-बार देखने की सुविधा, कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तकनीकी दक्षता में वृद्धि तथा आत्मनिर्भर अध्ययन की आदत विकसित होगी।

विश्वविद्यालय द्वारा इन पाठ्यक्रमों का संचालन आगामी शैक्षणिक सत्र जून-जुलाई 2026 से प्रारंभ किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को घर बैठे पढ़ाई, नौकरी या अन्य जिम्मेदारियों के साथ पढ़ाई जारी रखने का अवसर मिलेगा। दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों, महिलाओं व किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ चुके लोगों के लिए यह पहल विशेष रूप से लाभकारी होगी, जहां पारंपरिक शिक्षा तक पहुंच सीमित रहती है। मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में स्नातक स्तर पर बी.ए. (हिन्दी, राजनीति शास्त्र एवं समाजशास्त्र) तीन वर्ष (06 सेमेस्टर) तथा बी.लिब. (पुस्तकालय विज्ञान) एक वर्ष के पाठ्यक्रम शामिल हैं। वहीं स्नातकोत्तर स्तर पर एम.ए. (अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, शिक्षा), एम.एससी. (गणित), एम.कॉम. (वाणिज्य), एवं एम.बी.ए. (बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन) पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं, जिनकी अवधि सामान्यतः दो वर्ष (एम.बी.ए. के लिए 04 सेमेस्टर) निर्धारित की गई है। ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन सामग्री, वर्चुअल क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई-कंटेंट, समेत अन्य आधुनिक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।

मान्यता शैक्षणिक गुणवत्ता व तकनीकी सक्षमता का परिणाम: प्रो. सारस्वत

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. वी. के. सारस्वत ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राप्त यह मान्यता विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, पारदर्शिता और तकनीकी सक्षमता का प्रमाण है। आज के समय में उच्च शिक्षा को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिक सुलभ बनाना अत्यंत आवश्यक हो गया है, और हमारा विश्वविद्यालय इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने आगे कहा कि इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से उन विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा, जो भौगोलिक, आर्थिक या व्यावसायिक कारणों से नियमित कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो पाते। यह पहल 'एजुकेशन फॉर ऑल' की अवधारणा को मजबूत करेगी और प्रदेश के दूरस्थ एवं ग्रामीण अंचलों तक गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करेगी।

कलेक्टर के निर्देश पर जनदर्शन में मेधू को सौंपी गई व्हीलचेयर

बिलासपुर/नवप्रदेश। जनदर्शन कार्यक्रम में आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण जिला प्रशासन द्वारा संवेदनशीलता और तत्परता से किया जा रहा है।

इसी क्रम में आज आयोजित जनदर्शन में कलेक्टर के निर्देश पर दिव्यांग वृद्ध मेधूराम खांडे की समस्या का तत्काल समाधान करते हुए मौके पर ही उन्हें व्हीलचेयर प्रदान की गई। जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में इमलीभाटा अंबेडकर आवास, सरकंडा निवासी श्री मेधू राम खांडे को त्वरित लाभ मिला। वे अपनी समस्या लेकर कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे थे। उन्होंने अपनी शारीरिक स्थिति को देखते हुए व्हीलचेयर की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आवेदन पर तत्काल संज्ञान लिया और बिना किसी देरी के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। निर्देश मिलते ही कलेक्टर संजय अग्रवाल, अपर कलेक्टर शिव कुमार बनर्जी और समाज कल्याण विभाग के संयुक्त संचालक टी.पी. भावे की उपस्थिति में मेधू राम खांडे को व्हीलचेयर प्रदान किया गया। इस सहायता से लाभार्थी मेधू राम खांडे के चेहरे पर संतोष और खुशी के भाव देखे गए।

विद्युत लोड़ की सही जानकारी देकर बिजली संकट से बचें: ईडी अम्बस्थ

बिलासपुर/नवप्रदेश। प्रदेश के साथ ही जिले में गर्मी बढ़ने के कारण घरों तथा विभिन्न संस्थानों में कूलर और एसी का उपयोग बहुत अधिक बढ़ गया है। कई बार उपभोक्ताओं द्वारा बिजली कनेक्शन में जितना लोड रिकार्ड है उससे कई गुना अधिक उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर के डीओ गिर रहे हैं साथ ही बार-बार फ्यूज उड़ने की शिकायत भी प्राप्त हो रही है परिणामस्वरूप लोगों को कई बार बिजली आपूर्ति संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राज्य में बिजली उत्पादन तथा उसकी आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो रही है, परंतु समस्या स्थानीय स्तर पर है विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा घरों के बिजली कनेक्शन में जितना लोड ले रखा है उससे कहीं अधिक खपत किया जा रहा है, जिन घरों में कूलर और पंखे चला करते थे वहां पर अब एक नहीं दो और तीन एसी चल रहे हैं, जहां कूलर हैं वहां पर एक के स्थान पर तीन या उससे अधिक उपयोग किया जा रहा है। इस क्षमता के अनुरूप ट्रांसफार्मर स्थापित नहीं होने के कारण ट्रांसफार्मरों का फ्यूज उड़ने और उनका डीओ गिरने से लोगों को बार-बार विद्युत आपूर्ति में कठिनाईयों का सामना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए विभाग ने प्रत्येक जोन कार्यालय में कर्मचारियों को तैनात रखा है, जैसे ही सूचना मिलती है वे वहां पहुंचकर ट्रांसफार्मर में सुधार कार्य करते हैं।

सुशासन तिहार को लेकर जिपं की सामान्य सभा आयोजित

बिलासपुर/नवप्रदेश। *जिला पंचायत की विशेष सामान्य सभा की बैठक राजेश सूर्यवंशी अध्यक्ष जिला पंचायत की अध्यक्षता में सभी सभापति एवं जिला पंचायत सदस्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप कुमार अग्रवाल एवं जिला स्तर के अधिकारियों की उपस्थिति में हुई।*

'सुशासन तिहार 2026' के विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर के द्वारा विशेष सामान्य सभा में इस विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई। राज्य शासन की प्राथमिकताओं में जन शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी निराकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में इस वर्ष भी शासन द्वारा सुशासन तिहार 2026' संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन 01 मई से 10 जून 2026 के मध्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 15-20 ग्राम पंचायतों के समूह पर जन समस्या निवारण शिविर' आयोजित किया जाना है। दिनांकवार विकासखण्ड बिल्हा में 08 शिविर मस्तूरी 08 शिविर, तखतपुर 08 शिविर एवं कोटा में 07 शिविर आयोजित तिथि अनुसार किया जाना है ' ज्ञान भारतम् पांडुलिपि सर्वेक्षण के तहत् भारत की अमूल्य पांडुलिपि विरासत के संरक्षण संवर्धन और दस्तावेजीकरण के लिए प्रारंभ की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इन पांडुलिपियों में हमारी सभ्यता का ज्ञान परंपराएँ, विज्ञान, दर्शन और सांस्कृतिक स्मृतियों सुरक्षित है। विशेष सामान्य सभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण विधेयक पारित न होने पर सदस्यों द्वारा निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में उपाध्यक्ष ललिता संतोष कश्यप भारती नीरज माली सभापति, अम्बिका विनोद साहू सभापति, सभापति, निरंजन सिंह पैकरा सभापति, राधा खिलावन पटेल, जयकुमारी प्रभु जगत सदस्यगण एवं शिवानी सिंह उप संचालक पंचायत एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुविचार

आपको सिर्फ़ दो लोग ही समझ सकते हैं एक वो जो आपके जैसी परिस्थितियों से गुज़रा हो और दूसरा वो जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हो।

आप के बागी सांसदों के विलय को मंजूरी

आम आदमी पार्टी के सात बागी सांसदों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी और फिर उन्होंने इस बाबत् राज्यसभा के सभापति को पत्र सौंप दिया था। जिसपर विचार करने के बाद राज्यसभा के सभापति ने आम आदमी पार्टी के इन सातों सांसदों के भाजपा में विलय को मंजूरी दे दी है। इन बागी सांसदों की राज्यसभा सदस्यता खत्म कराने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं उनका कहना है कि इन सात बागी सांसदों का भाजपा में जाना दलबदल कानून के तहत आता है इसलिए इन्हें आयोग्य करार देना चाहिए। किन्तु उनका यह तर्क शायद ही सुप्रीम कोर्ट में चल पाये क्योंकि आम आदमी पार्टी के दस राज्यसभा सदस्यों में से 7 ने पार्टी छोडी है और भाजपा का दामन थामा है। दलबदल कानून के तहतह यह मामला आता ही नहीं है क्योंकि तात्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई की सरकार के दौरान संविधान में संसोधन करके यह प्रावधान किया गया था कि यदि किसी पार्टी के दो तिहाई सदस्य दलबदल करते हैं तो उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। इसके पूर्व तो एक तिहाई सदस्यों के पाला बदलने पर भी दलबदल कानून लागू नहीं होता था। इसलिए इन बागी सांसदों के खिलाफ कार्यवाही होना नामुमकीन की हद तक कठिन है। वैसे भी दलबदल करने वाले विधायकों और सांसदों को अयोग्य करा देने या न देने का अधिकार उस सदन के सभापति के हाथों सुरक्षित रहता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता जब तक की मामला बहुत ही जटिल न हो। यहां सात सांसदों का दल बदलना विधि सम्मत है ऐसे में भले ही आम आदमी पार्टी राज्यसभा के सभापति के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दें लेकिन वहां से भी उसके मनमाफिक फैसले की उम्मीद कम ही है। बहरहाल इन सात सांसदों के भाजपा में आ जाने से अब राज्यसभा में भाजपा की ताकत और बढ़ गई है जहां अब एनडीए बहुमत के और करीब पहुंच गई है अब भाजपा को राज्यसभा में अपने महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में और आसानी होगी। वैसे आम आदमी पार्टी के नेता इन बागी सांसदों के खिलाफ कार्यवाही को जो मन बना रहे हैं और इसे लेकर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। उसे देखते हुए अब समय आ गया है कि दल बदल कानून में एक बार फिर संसोधन करने पर विचार किया जाये। जिस राघव चड्ढा के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सदस्यों ने बगावत करके भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया उसी राघव चड्ढा ने संसद के पिछले सत्र में ही यह मांग उठाई थी कि दलबदल करने वाले नेताओं पर अंकुश लगाने के लिए संविधान में संसोधन किया जाये और दो तिहाई जनप्रतिनिधियों की जगह तीन चौथाई जनप्रतिनिधियों के दल बदलने को दलबदल कानून से पृथक रखा जाये। उनकी यह मांग नक्कारखाने में तूती की आवाज बनकर रह गई थी और अब उसी राघव चड्ढा की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के दो तिहाई सांसदों ने दल बदल कर दिया। दरअसल दल बदल कानून की समीक्षा करने तथा इसे और कड़ा बनाने में किसी भी राजनीतिक पार्टी की मंशा ही नहीं है। यही वजह है कि आया राम गया राम की परी पार्टी बदस्तूर चल रही है।

बंगाल में मतदान के दौरान हिंसा की आशंका

बंगाल विधानसभा के दूसरे चरण में 142 सीटों पर आज मतदान होना है। इस दौरान वहां हिंसा की आशंका बनी हुई है। गौरतलब है कि आज जिन सीटों पर मतदान होगा वे सभी टीएमसी का गढ़ मानी जाती है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन 142 सीटों में से 123 सीटें टीएमसी ने जीती थी जबकि भाजपा को सिर्फ 18 सीटें मिली थी। भाजपा इस बार यहां अपना पूरा जोर लगा रही है। वहीं टीएमसी अपना गढ़ बचाने के लिए जद्दो जहद कर रही है। जिससे मतदान के दौरान तनावपूर्ण स्थिति निर्मित हो सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी और 47 लोग मारे गये थे इसलिए आज के मतदान में सुरक्षाबलों को और अधिक सतर्क रहना होगा तभी वहां मतदाता निर्भिक होकर मतदान कर पायेंगे और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो पाएगा। इस स्थिति को देखते हुए ही चुनाव आयोग ने वहां अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती की है और उत्तरप्रदेश में सिंघम कहे जाने वाले एंकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस अधिकारी अजय शर्मा को आब्जरवर बनाकर डॉयमंड हारबर जिले में भेजा गया है। जहां उन्होंने मतदाताओं को धमकी चमकी देने वाले टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर खान के घर के पास जाकर उन्हें चेतावनी भी दी है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि यदि मतदान के दौरान किसी ने गड़बड़ी की कोशिश की तो उसे कड़ा सबक सिखाया जाएगा। हालांकि उक्त आईपीएस अफसर की इस चेतावनी को लेकर भी सियासत गर्मा गई है लेकिन मतदान शांतिपूर्ण कराने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों को इसी तरह का कठोर रूख अख्तियार करना होगा। अन्यथा मतदान के दौरान हिंसा की आशंका को नकारा नहीं जा सकता।

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1661 - चीन के मिंग वंश ने ताइवान पर कब्जा किया। 1639 - दिल्ली में लाल किले की नींव रखी गयी। 1813 - अमेरिका में जेएफहम्पेल ने रबर का पेटेंट कराया। 1848 - सुप्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म। 1903 - महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल हाईकोर्ट में लीगल प्रैक्टिस शुरू की और वहां ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। 1930 - ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेलीफोन सेवा की शुरूआत। 1939 - नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। 1978 - अफ्गानिस्तान के विद्रोही गुट ने सत्ता हासिल की। काबुल रेडियो पर घोषणा की गई कि उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वायुसेना अध्यक्ष लड़ाई में मारे गये हैं। 1991 - बांग्लादेश के चटगांव में आए चक्रवाती तूफान में एक लाख 38 हजार लोग मारे गए और दस लाख लोग बेघर हो गए। 1993 - पहली बार बर्किघम पैलेस को आम जनता के लिए खोला गया और जिसे देखने के लिए आठ पाउंड का टिकट लगा। 1997 - सायथनिक हथियारों पर प्रतिबंध लागू। 1999 - बच्चों के यौन शोषण पर रोक संबंधी विधेयक जापानी संसद में मंजूर। 2005 - सीरिया ने लेबनान से अपनी सेना को वापस बुलाया।

पंजाब से दिल्ली तक सियासी 'सुनामी': संकट में 'आप'

भारत की समकालीन राजनीति में शायद ही कोई घटना इतनी तेजी से राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आई हो, जितनी राघव चड्ढा सहित सात राज्यसभा सांसदों के आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से आई है। राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों का भाजपा में विलय केवल एक खबर नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के 15 साल के इतिहास का सबसे बड़ा 'ब्लैकआउट' है। भारतीय राजनीति के क्षितिज पर यह घटनाक्रम एक बड़े 'पॉलिटिकल अर्थक्वेक' के रूप में दर्ज हो गया है।

योगेश कुमार गोयल

आम आदमी पार्टी (आप) के 'पोस्टर बॉय' माने जाने वाले राघव चड्ढा सहित राज्यसभा के 7 सांसदों का एक साथ पाला बदलकर भाजपा में शामिल होना न केवल 'आप' के लिए एक अस्तित्वगत संकट है बल्कि यह देश की राजनीति की दिशा और दशा बदलने वाला घटनाक्रम भी है। यह सिर्फ दल-बदल नहीं बल्कि सत्ता, विचारधारा और राजनीतिक रणनीति के बीच गहरे संघर्ष का संकेत है। जब राज्यसभा में पार्टी के कुल 10 में से 7 सांसद (दो-तिहाई बहुमत) एक साथ अलग होकर भाजपा में विलय करने का निर्णय लेते हैं तो यह दलबदल नहीं, एक वैचारिक और संगठनात्मक विद्रोह का प्रतीक बन जाता है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब भारतीय राजनीति 2027 के बड़े चुनावी चक्र की ओर बढ़ रही है। ऐसे में इस घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या 'आप' का 'पंजाब विलना' अब ढहने के कगार पर है? क्या 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव की पटकथा अभी से लिखी जा चुकी है? और सबसे बड़ा प्रश्न कि क्या यह 'आप' के पतन की शुरुआत है या फिर एक अस्थायी राजनीतिक झटका?

'आप' के अस्तित्व पर खड़ा सबसे बड़ा सवाल

आम आदमी पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम को केवल राजनीतिक असहमति नहीं बल्कि लोकतंत्र पर सुनियोजित प्रहार करार दिया है। पार्टी नेतृत्व का स्पष्ट आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों के भय, दबाव और राजनीतिक प्रलोभनों के माध्यम से उसके सांसदों को तोड़ा गया, जिसे वह संस्थागत दुरुपयोग की श्रेणी में रखती है। यह आरोप भारतीय राजनीति में सत्ता बनाम विपक्ष की उस पुरानी बहस को फिर जीवित कर देता है, जहां नैतिकता और रणनीति आमने-सामने खड़ी दिखाई देती हैं। संवैधानिक दृष्टि से यह कदम और भी दिलचस्प हो जाता है। दलबदल विरोधी कानून की तकनीकी बारीकी (दो-तिहाई सदस्यों के एक साथ अलग होने की शर्त) का उपयोग करते हुए राघव चड्ढा के नेतृत्व में सात सांसदों का भाजपा में विलय यह संकेत देता है कि यह केवल भावनात्मक निर्णय नहीं बल्कि गहन कानूनी सलाह और रणनीतिक योजना का परिणाम था। सबसे गंभीर आघात वैचारिक स्तर पर है। जब भीतर से ही यह स्वर उठे कि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है तो यह केवल संगठनात्मक संकट नहीं बल्कि पहचान के संकट का संकेत बन जाता है और यही चुनौती 'आप' के लिए सबसे कठिन परीक्षा है।

पंजाब की राजनीति और 2027 का रण

पंजाब की राजनीति में उठी यह हलचल महज दल-बदल नहीं बल्कि सत्ता समीकरणों के पुनर्गठन का संकेत है। इस विद्रोह का सबसे गहरा असर पंजाब की सियासत पर पड़ना तय है। राज्यसभा में पंजाब का प्रतिनिधित्व करने वाले चेहरे (हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, संजीव अरोड़ा और विक्रमजीत सिंह साहनी) का पार्टी से अलग होना 'आप' की उस सामाजिक पकड़ को कमजोर करता है, जो विविध वर्गों के प्रतिनिधित्व से बनी थी। यह बदलाव केवल संख्या का नहीं बल्कि भरोसे

और प्रभाव का क्षरण है। सबसे बड़ी चुनौती भगवंत मान के सामने है। यह उनके नेतृत्व और राजनीतिक संतुलन की सीधी परीक्षा है। राघव चड्ढा को लंबे समय तक सरकार और संगठन के बीच रणनीतिक कड़ी माना जाता रहा, उनके हटने से यह संतुलन डगमगाता दिख रहा है। दूसरी ओर, भाजपा इस घटनाक्रम को अवसर में बदलने की कोशिश में है। भाजपा पंजाब में हमेशा से एक 'छोटा भाई' (अकाली दल के साथ) बनकर रही है लेकिन 7 सांसदों के आने से, जिनमें सिखों और उद्योगपतियों का प्रतिनिधित्व है, भाजपा अब 2027 में 'अकेले दम' पर सरकार बनाने का सपना देख रही है। अब तक सहयोगी राजनीति तक सीमित रही भाजपा अब पंजाब में स्वतंत्र शक्ति बनने की दिशा में आक्रामक कदम बढ़ाती दिख रही है और 2027 का रण अब पहले से कहीं अधिक खुला और अनिश्चित हो गया है।

क्या खत्म हो जाएगी 'आप'?

इतिहास गवाह है कि क्षेत्रीय दल जब ऐसे बड़े विद्रोह का सामना करते हैं तो अक्सर वे या तो बिखर जाते हैं या फिर सिमटकर रह जाते हैं लेकिन आप की स्थिति थोड़ी भिन्न है। इसका सबसे बड़ा कारण है अरविंद केजरीवाल का व्यक्तित्व। आम आदमी पार्टी का आधार अरविंद केजरीवाल की 'व्यक्तिगत ब्रांडिंग' पर टिका है। जब तक दिल्ली और पंजाब जैसे अहम राज्यों में उनका जनाधार सुरक्षित है, तब तक 'आप' का पूर्ण पतन लगभग असंभव प्रतीत होता है। इसके समानांतर, 'आप' की ताकत उसका विकसित कैडर ढांचा है। आप ने पिछले एक दशक में एक मजबूत कैडर तैयार किया है। हालांकि शीर्ष स्तर पर योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और अब राघव चड्ढा जैसे प्रमुख चेहरों का अलग होना पार्टी को बड़ा झटका देता है लेकिन जमीनी कार्यकर्ता अब भी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं। एक वैकल्पिक, जनोन्मुख और व्यवस्था-विरोधी नेता की केजरीवाल की छवि अब भी पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी बनी हुई है।

राष्ट्रीय राजनीति में बदलता खेल

राष्ट्रीय राजनीति के व्यापक परिप्रेक्ष्य में यह घटनाक्रम सत्ता-संतुलन को निर्णायक रूप से प्रभावित करता है। राज्यसभा में सात सांसदों के जुड़ने से भाजपा की स्थिति और सुदृढ़ हुई है, जिससे अब महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने में उसकी छोटे दलों पर निर्भर रहने की बाध्यता कम हो गई है। इसके विपरीत, विपक्षी गठबंधन के लिए यह स्पष्ट झटका है क्योंकि 'आप' इस गठबंधन की मुखर आवाज रही है। सबसे गंभीर आघात 'आप' की वैचारिक विश्वसनीयता पर पड़ा है। जो पार्टी 'ईमानदार राजनीति' को अपनी पहचान मानती रही, उसी के भीतर से वैचारिक विचलन और आरोपों का उठना उसके नैतिक कैद को कमजोर करता है। यह स्थिति नेतृत्व शैली पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है, लगातार बड़े चेहरों का अलग होना इस ओर संकेत करता है कि संवाद की कमी और निर्णय प्रक्रिया का केंद्रीकरण आंतरिक असंतोष को जन्म दे रहा है। राष्ट्रीय विस्तार की महत्वाकांक्षा पर भी इसका प्रभाव पड़ना तय है। दिल्ली और पंजाब से आगे बढ़ने की जो रणनीति थी, वह अब धीमी पड़ती तय है, विशेषकर तब, जब पंजाब, जो 'आप' का सबसे मजबूत गढ़ है, स्वयं इस राजनीतिक भूकंप के केंद्र में आ खड़ा हुआ है।

आप के लिए अग्निपरीक्षा का समय

यह कहना जल्दबाजी होगी कि 7 सांसदों के जाने से आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। राजनीति में रिक्तियां हमेशा भर दी जाती हैं। हालांकि यह निश्चित है कि आप अब अपनी सबसे कठिन अग्निपरीक्षा से गुजर रही है। यदि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान अगले कुछ महीनों में पंजाब और दिल्ली के कैडर को एकजुट रखने में विफल रहे तो 2027 का चुनाव उनके लिए एक राजनीतिक ढलान साबित हो सकता है। दूसरी ओर, भाजपा ने इस 'मास्टरस्ट्रोक' के जरिए यह संदेश दे दिया है कि वह दिल्ली और पंजाब की सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बहरहाल, 'आप' के लिए चुनौती अब केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि अपने अस्तित्व और साख को बचाए रखना है।

नारंगी अर्थव्यवस्था: जनजातीय कला, हस्तशिल्प और आजीविका

रंजना चोपड़ा

वर्शांग खैयर मणिपुर के उखरूल जिले के लॉन्गपी गाँव के निवासी हैं, जो अपने और अपने परिवार की रोजी-रोटी गाँव में उपलब्ध गारे और सर्पेंटीनाइट पत्थर से बर्तन बनाकर कमाते हैं। स्थानीय तांगखुल नागा जनजातियों के अनुसार, यह पारंपरिक शिल्प, देवी पंथोइबी की कृपा है और आज यह उनकी आय का मुख्य स्रोत है और इसने छोटे से गाँव को वैश्विक मानचित्र पर ला दिया है।

इसी तरह, नाँथी कुट्टन, जो तमिलनाडु के उदुहमंडलम जिले के पागलकोड मंड गाँव में रहते हैं, पारंपरिक कढ़ाई कला से अपनी आजीविका कमा रहे हैं। इस कढ़ाई कला का उपयोग नीलगिरी के हरे-भरे जंगलों में बसे टोडा जनजाति समूह द्वारा किया जाता है। जीआई टैग से युक्त यह शिल्प प्रकृति और सामुदायिक बंधन का जश्न मनाता है और इसे बहुत ही सुंदरता के साथ टेबल मैट, रनर, जैकेट आदि पर अंकित किया जाता है और समकालीन उपयोग में इसे लोकप्रियता भी मिली है। खैयर और कुट्टन दोनों अपने पारंपरिक जनजातीय कला रूपों के एक उन्नत रूप का अभ्यास करके सालाना लगभग 6-8 लाख रुपये कमाते हैं। जनजातीय आजीविका लंबे समय से ज्ञान और पारंपरिक प्रथाओं पर आधारित रही है, जहां रचनात्मकता शिल्प, परंपरा, वस्त्र, संगीत, नृत्य, कथा-वाचन और भाषाओं में निहित है। ये केवल उत्पाद या सेवाएं नहीं हैं, बल्कि ज्ञान की जीवित विरासत हैं, जो पीढ़ियों के माध्यम से आगे बढ़ती हैं। जनजातीय समुदायों के पास मौजूद रचनात्मक संपत्तियों का महत्वपूर्ण आर्थिक मूल्य है, जिसे यदि परंपरा के प्रति संवेदनशील रहते हुए सतत तरीके से उपयोग किया जाए, तो यह नारंगी

अर्थव्यवस्था (अरेंज इकोनॉमी) को गति दे सकता है और इस इकोसिस्टम के तहत आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों का सृजन कर सकता है। रचनात्मक अर्थव्यवस्था को दर्शाने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली नारंगी अर्थव्यवस्था, यूएनसीटीएडी के अनुमान के अनुसार 2 ट्रिलियन डॉलर से 2.25 ट्रिलियन डॉलर के बीच है, जो वैश्विक जीडीपी का लगभग 3.1त है। भारत में, जहाँ हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए ठोस डेटा मौजूद है, वहीं जनजातीय शिल्प और आजीविका के लिए डेटा की कमी है। हालांकि, रणनीतिक निहितार्थ स्पष्ट है: जनजातीय कला और शिल्प कुछ ऐसी ग्रामीण आजीविकाएं हैं, जो वैश्विक रचनात्मक वस्तुएँ की मांग से सीधे जुड़ सकती हैं यदि प्रामाणिकता, लॉजिस्टिक्स और गुणवत्ता प्रणाली मौजूद हों। अनुमान है कि भारत की अनुसूचित जनजाति की आबादी 104 मिलियन है और कुल आबादी में इसकी हिस्सेदारी लगभग 8.6त है। लगभग 700 अलग-अलग जनजातीय समुदाय विभिन्न पारिस्थितिक क्षेत्रों में निवास करते हैं: जंगल, पहाड़, मैदान और सीमा क्षेत्र। इस विविधता का प्रत्यक्ष आर्थिक संबंध है। यह पारिस्थितिकी के अनुसार शिल्प विशेषज्ञता को प्रतिबिंबित करता है, जैसे जंगल वाले क्षेत्रों में बांस और छड़ी, खनिज क्षेत्रों में धातु और मिट्टी, और बुनाई गलियारों में वस्त्र परंपराएँ। इसके परिणामस्वरूप, भारत के जनजातीय क्षेत्र: एक जनजातीय शिल्प क्षेत्र के बजाय "विविध अर्थव्यवस्थाओं" से युक्त हैं। इसलिए, नीति निर्माण क्षेत्रीय रूप से भिन्न होना चाहिए और "सभी के लिए उपयुक्त एक ही शिल्प योजना" नहीं होनी चाहिए। नीतियों को कच्चे माल की सीमाओं, डिज़ाइन और गुणवत्ता संबंधी मुद्दों और बाजार संबंधों को ध्यान में रखना चाहिए। वर्तमान में, जनजातीय कला/हस्तशिल्प आजीविका इकोसिस्टम, कई मंत्रालयों और संस्थानों के कार्यदिशों से बना है, जो विभिन्न स्तरों पर एक-जैसे हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय इस इकोसिस्टम का मुख्य स्तंभ है और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक अवसंरचना में सुधार करता है और ट्राइफेड (भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड) के माध्यम से बाजार-जुड़ाव की सुविधा देता है। ट्राइफेड एक प्रमुख बाजार संचालक के रूप में कार्य करता है। ट्राइफेड वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) का समर्थन करता है, जो खरीद और मूल्य संवर्धन के लिए जमीनी स्तर की इकाइयाँ हैं। ट्राइफेड, ट्राइब्स इंडिया आउटलेट और आदि महोत्सव/हाट्स के माध्यम से खुदरा विपणन करता है ताकि उत्पादकों को खरीदारों और संस्थागत भागीदारों से जोड़ा जा सके। वस्त्र मंत्रालय राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के माध्यम से हस्तशिल्प को बढ़ावा देता है और समग्र हथकरघा/हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजनाओं (सीएचसीडीएस) के माध्यम से क्लस्टर अवसंरचना को प्रोत्साहन देता है और कारीगरों के डेटाबेस को अद्यतन करता है।

पाठकों की बात — पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

क भी - कभी यूँ ही यूँ भी..आता है ख्याल तेरा कि झुक जाती हैं नज़र... शर्म से ही जाता है चेहरा गुलाबी-गुलाबी । बिन बात के मुस्कुराने लगती हैं अधरों पे गीत कोई छा जाता है....और सोचने लगती हैं तुझको तो.... दब जाती है उँगली दाँतों तले खुद ब खुद.... आ जाता है पल्लू होठों के बीच... और फिर उड़ने लगती हैं... साथ-साथ हवा के... और सोचती हैं कि.... ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा.... बस....दर्द में भी मुस्कुरा लेती हूँ.... सिर्फ और सिर्फ तेरे लिये ॥

– डॉ.सविता वर्मा ÷गज़ल÷

एक अर्से बाद मिले हो , आज हम तुमसे कुछ नही लेंगे , तुम्हारी रुसवाइयों का जवाब देंगे , तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देंगे , तुम्हारा सुकून जो खो गया है उसे वापिस देंगे , आज तुम जो मिले हो बरसों बाद , तुमे अपने धडकनों का हिसाब देंगे , जो तुम्हारा ही नाम ले कर धडकता रहा , जो मिल न सका तुम्हे कभी वो पैगाम देंगे।। – नमन कुमार मिश्रा

इक इक लम्हे को जीने की इशरत रखा करो, कभी ज्यादा कभी कम बस हसरत रखा करो, उम्र की गिनती में जाया क्यूं करो मुस्कुराहट, कुछ टुकड़े ही सही आँखों में फक्त रखा करो।। – विजय लक्ष्मी राय

इनकम टैक्स ने एक नेताजी को नोटिस भेजा :: आपने पिछले साल क्या कमाई की, उसका हिसाब दीजिए... और उसका टैक्स जुमाने के साथ जमा कीजिए... नेता :: पिछले साल मेरी कमाई हुई 1000 जूते, 5000 सड़े अंडे, 10000 गालियाँ । बताइये इनमें कितनी आपको बतौर टैक्स भेजूँ..? ?? इनकम टैक्स से जवाब आया :: ढाई लाख तक छूट है.... और खाईए.....! – पितांबर श्रीवास्तव

आस अपनी जगह पर अड़ी रह गई फांस सी इक हलक में पड़ी रह गई वक्त को तो गुज़रना था ,गुज़रा मगर हाथ में मेरे बस यह घड़ी रह गई ; मेरी तस्वीर उसने हटाई मगर , कील अपनी जगह पर गड़ी रह गई ; तर्कें ताल्लुक पे दोनों ही नादिम हुये दरम्याँ आँसुओं की झड़ी रह गई रास्ता पर भी दोनों में कायम रहा बीच में दर्द की इक कड़ी ।

– अनु मित्तल

आप लोगो से इज्जत मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद मत करो??आप कितना भी अच्छा व भलाई का काम करो??लोग तो आपको अपने स्वार्थ के हिसाब से ही इज्जत देंगे!???तो क्यो न हम अपना व्यवहार को नियंत्रित कर ले! – रमेश अग्रवाल

अपने आँचल में हौसले का उजास बांधे, टेरेस पर कटरा -दर-कटरा जिंदगी सँजोती, मुस्कुराती हुई खड़ी एक स्त्री। उसके पास उम्मीदों का कनवास था हिम्मत और सूझबूझ के ब्रश-स्ट्रोक्स थे वह तिनका तिनका कर आसमान बुन रही थी कल की स्त्री प्रेम के नाते से जुड़ी थी और सकारात्मक सोच के सहारे एक सुंदर घर, बेहद पवित्र दुनियाँ बनाने को तैयार थी।

– हेमा पांडे

राशि फल

पं. देवव्रत शर्मा

मेष : आज का दिन आपके लिए संतुलित और सकारात्मक संकेत लेकर आया है। आप रिश्तो को सुधारने में पहल करेंगे। जो लोग आपसे नाराज थे, उन्हें मनाने की कोशिश साफल हो सकती है।

वृष: आज का दिन थोड़ा सतर्कता मांगता है। अनावश्यक जोखिम लेने से बचें, खासकर वाहन से जुड़ी लापरवाही भारी पड़ सकती है। टूट रहे किसी प्रियजन की याद आपको भावुक कर सकती है।

मिथुन: आज आपको कुछ खास और प्रभावशाली लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा, जो भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकता है। संतान किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकती है, जिससे घर में उत्साह का माहौल रहेगा।

कर्क: आज का दिन मिला-जुला रहेगा, लेकिन समझदारी से काम लेने पर आप हर परिस्थिति को संभाल लेंगे। नौकरी से जुड़े कामों के लिए आपको यात्रा या भागदौड़ करनी पड़ सकती है।

सिंह: आज आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सार्वों पर नियंत्रण रखें, नहीं तो कर्ज बढ़ सकता है। लालचि सेहत में पहले से सुधार महसूस होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।

कन्या: आज आपकी नेतृत्व क्षमता खुलकर सामने आएगी और साथियों का पूरा सहयोग मिलेगा। काम के प्रति संतुष्टि महसूस करेंगे। माता-पिता की सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें।

तुला: आज आपको छोटे-छोटे लाभ के अवसरों पर ध्यान देना होगा। दिखावे से दूर रहकर सादगी अपनाना ही समझदारी है। बातचीत में संयम रखें, क्योंकि एक गलत शब्द आपके काम बिगाड़ सकता है।

वृश्चिक: आज का दिन नई शुरुआत और बड़े फैसलों का संकेत दे रहा है। प्रॉपर्टी खरीदने या नया वाहन लेने का सपना पूरा हो सकता है। लंबे समय से चली आ रही इच्छा पूरी हो सकती है।

धनु: आज का दिन आपके लिए साधना और संतोष लेकर आएगा। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और आप जिस काम में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता जरूर मिलेगी।

मकर: आज नौकरीपेशा लोगों के लिए शानदार दिन है। मान-सम्मान में वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत होगी। घर-परिवार की समस्याओं को सुलझाने का अवसर मिलेगा।

कुंभ: आज मेहनत और बुद्धिमत्ता से आप सबको प्रभावित करेंगे। कार्यक्षेत्र में रीमवर्क का फायदा मिलेगा और आपकी सास मजबूत होगी। धन-धान्य में वृद्धि के संकेत हैं।

मीन: आज आपको आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है। कोई बड़ा जोखिम न लें। आसपास के लोगों से तालमेल अच्छा रहेगा।

QUIZ TIME

1) सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है?

2) भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था?

3) भारतीय कला महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था?

4) हाल ही में खबरों में रही रुशिकुल्या नदी किस राज्य से होकर बहती है?

5) हाल ही में चर्चा में आया गिल्बर्ट हिल किस राज्य में स्थित है?

Ramaquiz

(1) आंध्रप्रदेश (2) केरल (3) मिजोरम (4) ओडिशा (5) महाराष्ट्र

पहेली

शब्द सामर्थ्य -022

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 021 का हल

लाखों छात्रों का इंतजार खत्म! आज जारी होगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ में 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले लाखों छात्र-छात्राओं को इंतजार खत्म होने वाला है। 29 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा रिजल्ट जारी होगा। इसे लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि इंतजार की घड़ियां अब समाप्ति की ओर है। बुधवार दोपहर 2:30 बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल के हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम औपचारिक रूप से घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि यह केवल अंकों की घोषणा नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, अनुशासन और अभिभावकों व शिक्षकों के सतत मार्गदर्शन का प्रतिफल है। इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों को धैर्य बनाए रखने, परिणाम को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करने और भविष्य की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की शुभकामनाएं। प्रत्येक परिणाम एक नई शुरुआत का संकेत है और हर विद्यार्थी में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं निहित हैं। बता दें कि इस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा में लगभग 3121 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे।

कैसे चेक करें रिजल्ट?

- छात्र नीचे दिए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
- सबसे पहले आप सीजीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं,
- फिर वेबसाइट के होम पेज पर बोर्ड रिजल्ट पर लिंक पर क्लिक करें,
- अब छात्र एडमिट कार्ड पर दिए गए रोल नंबर और कैप्चा कोड को सही से दर्ज करें,
- रिजल्ट देखने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें,
- आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा। इसे चेक करें और पीडीएफ डाउनलोड करें।

न्यूज गैलरी

सदगुरु कबीर आश्रम में मिली 326 वर्ष पुरानी दुर्लभ पाण्डुलिपियाँ

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ की धरती ने एक बार फिर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई है। विकासखंड सिमगा के कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा स्थित सदगुरुदेव कबीर आश्रम में कलेक्टर कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में चल रहे "ज्ञानभारतम" राष्ट्रीय पाण्डुलिपि सर्वेक्षण अभियान के दौरान सन् 1700 ईस्वी की 326 वर्ष पुरानी हस्तलिखित पाण्डुलिपियाँ प्राप्त हुई हैं। ये पाण्डुलिपियाँ न केवल धार्मिक दृष्टि से अमूल्य हैं, बल्कि भारत की ज्ञान परंपरा का जीवंत प्रमाण भी हैं। दामाखेड़ा में कुल चार प्राचीन ग्रंथों – अनुरागसागर, अम्बूसागर, दीपकसागर एवं ज्ञान प्रकाश – का सर्वेक्षण कर सरपंच की उपस्थिति में ज्ञानभारतम अभियान के माध्यम से डिजिटलीकरण पूर्ण किया गया। ये सभी ग्रंथ 9वें आचार्य प्रगट नाम साहब द्वारा लिखित हैं और देवनागरी लिपि में हैं, जो इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। इस अभियान की एक और ऐतिहासिक उपलब्धि यह रही कि सोनाखान संग्रहालय में 10 दिसम्बर 1857 को अंग्रेजी सरकार द्वारा जारी शहीद वीर नारायण सिंह के फाँसी के आदेश की पाण्डुलिपि भी प्राप्त हुई है। यह दस्तावेज़ छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की शहादत का अनमोल ऐतिहासिक साक्ष्य है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने जिलेवासियों से अपील की है कि यदि किसी के पास कोई भी हस्तलिखित प्राचीन ग्रंथ, ताम्रपत्र या ताड़पत्र हो तो वे सर्वे टीम को सूचित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य में मूल प्रति स्वामी के पास ही रहेगी, केवल फोटो लेकर अपलोड किया जाएगा। ज्ञानभारतम अभियान का उद्देश्य भारत की बौद्धिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित करना है। कलेक्टर ने सभी नागरिकों से इस राष्ट्रीय अभियान में सहभागी बनने का आह्वान किया है।

इतिहास के पन्ने हुए डिजिटल – 'ज्ञानभारतम' एप से हुआ संरक्षण

रेगाकठेरा जलाशय योजना के कार्यों के लिए 2.07 करोड़ रूपए स्वीकृत

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग द्वारा मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले के विकासखण्ड-अम्बागढ़ चौकी की रेगाकठेरा जलाशय जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य के लिए 2 करोड़ 7 लाख 82 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। प्रस्तावित कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत रूपांकित सिंचाई क्षमता 80 हेक्टेयर के विरुद्ध 60 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार जल संसाधन विभाग रायपुर को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

सीतारामपुर जलाशय निर्माण कार्य के लिए 6.33 करोड़ रुपये स्वीकृत

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग द्वारा, बलरामपुर रामानुजगंज जिले के विकासखण्ड-बलरामपुर जलाशय (बांध) निर्माण कार्य के लिए 6 करोड़ 33 लाख 89 हजार रुपये की राशि स्वीकृत किये गये हैं। योजना के निर्माण से 150 हेक्टेयर में खरीफ और 50 हेक्टेयर में रबी सहित कुल 200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग अम्बिकापुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

पशुपालन से सुकृता की बदली तस्वीर, मनरेगा बना सहारा

रायपुर/नवप्रदेश। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के माध्यम से ग्रामीणों की आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में जिले में लगातार प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम धुरकोट की निवासी श्रीमती सुकृता बाई कश्यप के जीवन में योजना ने सकारात्मक बदलाव लाया है। मनरेगा के तहत उनके मवेशियों के लिए लगभग 72 हजार रुपये की लागत से एक आधुनिक शेड का निर्माण कराया गया। पहले सुकृता अपने पशुओं को खुले में रखती थीं, जिससे बारिश और बदलते मौसम में उनके बीमार होने का खतरा बना रहता था। शेड निर्माण के बाद अब पशुओं को सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण मिल रहा है, जिससे उनकी देखभाल आसान हुई है और उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि हुई है। वर्तमान में सुकृता के पास कई गाय और बछड़े हैं, जिनका वे व्यवस्थित रूप से पालन कर रही हैं। उन्होंने बताया कि पहले उचित व्यवस्था के अभाव में काफी परेशानियां होती थीं, लेकिन अब शेड बनने से बड़ी राहत मिली है। पशुओं से प्राप्त गोबर का उपयोग वे जैविक खाद बनाने में कर रही हैं, जिससे उनके खेतों की उर्वरता और फसल उत्पादन में भी सुधार हुआ है। पशुपालन से उन्हें प्रतिमाह 10 से 12 हजार रुपये तक की आमदनी हो रही है। वहीं, शेड निर्माण के दौरान स्थानीय मनरेगा मजदूरों को भी रोजगार मिला, जिससे योजना के रोजगार सृजन और स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के उद्देश्य की प्रभावी पूर्ति हुई है। ग्राम धुरकोट में यह पहल अन्य ग्रामीणों के लिए प्रेरणादायक बन रही है।

कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें कराता उपलब्ध

नए शिक्षा सत्र की तैयारीः समय पर किताबें पहुंचाने की कवायद

■ निजी स्कूलों के लिए तय होगा शेड्यूल

रायपुर/नवप्रदेश। आगामी शिक्षा सत्र में विद्यार्थियों को समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम (पापुनि) ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार वितरण व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने के लिए संकुल से लेकर स्कूल स्तर तक सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी, वहीं निजी स्कूलों के लिए किताब वितरण का दिन और समय पहले से तय किया जाएगा। निगम की ओर से सभी निजी स्कूलों को मोबाइल मैसेज के जरिए सूचना दी जाएगी, जिसमें तय समय के अनुसार स्कूल प्रतिनिधि डिपो से किताबें प्राप्त करेंगे। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य वितरण में होने वाली अव्यवस्था और गड़बड़ियों को रोकना है। राज्य शासन हर वर्ष सरकारी, अनुदान प्राप्त और छत्तीसगढ़ बोर्ड से संबद्ध निजी स्कूलों के कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराता है। इन पुस्तकों की आपूर्ति की जिम्मेदारी पापुनि पर होती है।

क्यूआर कोड से होगी निगरानी

पुस्तक वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए पिछले साल से पाठ्य पुस्तकों में क्यूआर कोड सिस्टम लागू किया गया है, जिसे इस बार भी जारी रखा जाएगा। इसके माध्यम से किताबों की ट्रैकिंग और निगरानी की जाएगी ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो।

संकुल से स्कूल तक सख्त मॉनिटरिंग

निगम द्वारा कक्षा 9वीं और 10वीं की किताबें सीधे स्कूलों तक पहुंचाई जाएगी, जबकि कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकें संकुल स्तर पर भेजी जाएंगी। वहां से स्कूलों तक वितरण की निगरानी की जाएगी ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो।

प्रिंटिंग में देरी, फिर भी समय पर आपूर्ति का दावा

हालांकि इस वर्ष टेंडर प्रक्रिया में देरी हुई है और कागज की आपूर्ति भी हाल ही में शुरू हुई है, लेकिन अब पुस्तकों की छपाई शुरू हो चुकी है। पापुनि की एमडी किरण कौशल ने प्रिंटर्स की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि समय पर प्रिंटिंग पूरी की जाए, अन्यथा लापरवाही पर ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई होगी।

वितरण प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी। पिछले साल प्रदेश के 1784 निजी स्कूलों ने पापुनि से किताबें नहीं ली थीं और निजी प्रकाशकों की पुस्तकों से पढ़ाई कराई थी। इस मामले में निगम ने शिक्षा विभाग को कार्रवाई के लिए सूची भेजी थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

अजय चंद्राकर के भाई के घर ईडी जांच या जबान बंद करने की कोशिशः कांग्रेस

रायपुर/नवप्रदेश। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारो से चर्चा करते हुये कहा कि भाजपा नेता अजय चंद्राकर के घर ईडी की छापेमारी हुई है। बताया जाता है भारत माला घोटाले के संदर्भ में छापे मारे गये। बैज का आरोप लगाते हुए पूछा कि क्या इस छापे के पीछे एक मात्र यही कारण है। बड़े-बड़े घोटाले करने के बाद सैकड़ो लोग भाजपा में शामिल हुये उनके खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी गयी, क्लीन चिट दे दिया गया। अजय चंद्राकर तो भाजपा के ही नेता है, फिर उनके घर ईडी क्यों गयी होगी? दरअसल अजय चंद्राकर के विधानसभा में तीखे सवालों से भाजपा नेतृत्व डरा हुआ है। वे अपनी पार्टी की सरकार को आईना दिखाते है। विधानसभा में साय सरकार के 2047 के डाक्यूमेंट को उन्होंने झूठ का पुलिंदा बताया। इसीलिए अजय चंद्राकर के घर ईडी भेजकर जबान बंद करने की कोशिश की जा रही है। पहले विरोधियो के यहां ईडी भेजते थे, अब वे जो अपने है लेकिन असहमत है उनके यहां ईडी भेज रहे है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि खरीफ फसल का सीजन आने वाला है। खरीफ में लगने वाले उर्वरको की उपलब्धता पर सरकार मौन है। बार-बार मांग करने के बाद सरकार कितना स्टाक उपलब्ध है, कुछ बता नही रही है। सोसायटियों में न यूरिया पहुंची है और न डी.ए.पी। पिछले साल भी सरकार कितनो को यूरिया, डीएपी नही दे पाई थी, इस बार भी सरकार की तैयारी पूरी नहीं दिख रही है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार मांग के अनुसार उर्वरको की उपलब्धता सुनिश्चित करावे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अडानी पावर को पानी पहुंचाने किसानों के खेतों में जबरिया पाईप डाल रहे, विरोध करने पर धमकाया जा रहा है। अडानी पावर के लिये पानी सप्लाई करने आरंग ब्लाक के महनदी के चिखली और समोदा घाट से अडानी पावर रायखेड़ा में 45 किलोमीटर पाईप लाइन बिछाई जा रही है।

जेब पर बढ़ा बिजली का बोझः बिना सूचना बढ़ रहा अनुबंध भार, उपभोक्ता परेशान

रायपुरारायपुर/नवप्रदेश। शहर में बिजली उपभोक्ताओं पर इन दिनों अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। वर्षों पहले कम अनुबंध भार पर बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ता अब परेशानी में हैं, क्योंकि बिजली कंपनी उनकी बढ़ती खपत के आधार पर स्वतः ही अनुबंध भार बढ़ाकर बिल में अतिरिक्त शुल्क जोड़ रही है।

दरअसल, गर्मी के मौसम में एसी, कूलर और पंखों के अधिक उपयोग से बिजली खपत तेजी से बढ़ गई है। इसके चलते कई उपभोक्ताओं के बिल अचानक बढ़ गए हैं। खास बात यह है कि

कई मामलों में उपभोक्ताओं को बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध भार में वृद्धि कर दी गई, जिससे बिल में अतिरिक्त राशि जुड़ गई।

एक उपभोक्ता के अनुसार, उनके कनेक्शन का अनुबंध भार पहले 340 वॉट था, जो इस माह बढ़कर 3000 वॉट कर दिया गया। इस बदलाव की जानकारी उन्हें सीधे बिजली बिल मिलने पर ही हुई। बढ़े हुए भार के साथ अतिरिक्त शुल्क भी जोड़ दिया गया, जिससे कुल बिल में भारी इजाफा हो गया।

जानकारी के मुताबिक, स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली खपत और बिलिंग की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन मॉनिटर होने लगी है। यदि किसी उपभोक्ता द्वारा लगातार तीन माह तक स्वीकृत भार से अधिक बिजली उपयोग किया जाता है, तो बिजली कंपनी अधिकतम खपत को आधार मानते हुए स्वतः अनुबंध भार बढ़ा देती है। इसके साथ ही बढ़े हुए भार का शुल्क भी बिल में शामिल कर लिया जाता है।

'प्रोजेक्ट धड़कन' से 2 साल की पारूल को मिला नया जीवन

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित 'प्रोजेक्ट धड़कन' के नारायणपुर के दूरस्थ बेहबहुरा गांव की 2 वर्षीय पारूल दुग्गा को नया जीवन दिया है। जन्मजात हृदय रोग से ग्रस्त पारूल की रायपुर के श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में सफल सर्जरी के बाद वह स्वस्थ होकर घर लौट चुकी है।'प्रोजेक्ट धड़कन' अब नारायणपुर जिले में योजना भर नहीं, बल्कि उन परिवारों के लिए उम्मीद का नाम बन चुका है जिनके लिए हर नन्हीं धड़कन सबसे कीमती है।

अबूझमाड़ अंचल के बेहबेड़ा गांव की पारूल कुछ समय पहले तक जल्दी थक जाती थी और सामान्य बच्चों की तरह खेल नहीं पाती थी। सीमित संसाधनों के बीच माता-पिता को उसकी गंभीर बीमारी का पता ही नहीं था।

नारायणपुर जिले में बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए फरवरी 2026 में 'प्रोजेक्ट धड़कन' की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में बच्चों की हृदय संबंधी जांच कर गंभीर मामलों की शुरुआती पहचान करना है। यह पहल उन सुदूर क्षेत्रों तक पहुंची जहां विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं बेहद सीमित थीं। अभियान के पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने गांव-गांव जाकर 3000 से अधिक बच्चों की स्क्रीनिंग की। तीन बच्चों में हृदय रोग के लक्षण मिले, जिनमें पारूल भी शामिल थी। जानकारी मिलते ही प्रशासन ने तुरंत इलाज की व्यवस्था की।

करेन्सी टावर, रायपुर में लिफ्ट अवरोध की घटना पर त्वरित जाँच

रायपुर/नवप्रदेश। करेन्सी टावर, रायपुर में स्थापित कैप्सूल लिफ्ट क्रमांक-02 के बीच में रुक जाने की घटना दिनांक 20 अप्रैल 2026 के संबंध में की गई जाँच में यह तथ्य सामने आया है कि विद्युत आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में स्टैंडबाय व्यवस्था के रूप में डीजल जनरेटर एवं यूपीएस उपलब्ध है। मुख्य विद्युत निरीक्षकालय द्वारा जाँच रिपोर्ट के आधार पर सभी तकनीकी खामियों को दूर करने हेतु 07 दिवस की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

मुख्य विद्युत निरीक्षक कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि घटना के दिन विद्युत आपूर्ति में व्यवधान आने पर डीजल जनरेटर के ऑटोमैटिक चेंजओवर सिस्टम में तकनीकी खराबी उत्पन्न हो गई, जिसके परिणामस्वरूप यूपीएस भी प्रभावित हुआ और लिफ्ट को निरंतर विद्युत आपूर्ति नहीं मिल सकी। इसी कारण लिफ्ट बीच में रुक गई। उन्होंने बताया कि उक्त लिफ्ट 23 जनवरी 2027 तक वारंटी अवधि में है एवं संबंधित एजेंसी द्वारा इसकी मरम्मत का कार्य किया जा रहा है।

एप डाउनलोड कराई, अश्लील फोटो भेजकर किया ब्लैकमेल

■ कंज्यूमर कोर्ट अधिकारी बनकर 55 हजार की ठगी

रायपुर/नवप्रदेश। राजधानी में साइबर ठगों का जाल तेजी से फैल रहा है। बीते 10 दिनों के भीतर ठगों ने का रोबारी, डॉक्टर और आर्मी स्टाफ समेत कई लोगों को निशाना बनाते हुए 10 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर ली है। ठगों ने लोगों को झांसे में लेकर मोबाइल ऐप डाउनलोड कराई, फोन हैक किया और फिर एआई तकनीक से अश्लील फोटो बनाकर ब्लैकमेल किया।

ऐसे फंसा पीड़ित, 6 लाख की वसूली

टिकरापारा थाना क्षेत्र में रहने वाले 45 वर्षीय विशाल गुप्ता को ठगों ने 40 हजार रुपए का लोन दिलाने का झांसा दिया। इसके लिए उनसे एक मोबाइल एप डाउनलोड कराई गई। जैसे ही एप इंस्टॉल हुआ, ठगों ने फोन का एक्सेस हासिल कर लिया। इसके बाद मोबाइल गैलरी से तस्वीरें चुराकर एआई के जरिए उन्हें अश्लील रूप में एडिट किया गया। इन तस्वीरों को पीड़ित की कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद लोगों को व्हाट्सएप पर भेज दिया गया। इसके बाद बदनामी का डर दिखाकर पीड़ित को ब्लैकमेल किया गया और 10 दिनों के भीतर करीब 6 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए गए।

पुलिस के अनुसार, इस मामले में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबरों और बैंक खातों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ठगों ने मोबाइल से तस्वीरें लेकर उन्हें एआई तकनीक से अश्लील रूप में बदला। यह तरीका हाल के दिनों में तेजी से बढ़ा है, जिसमें निजी डेटा का दुरुपयोग कर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है।

मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में बेहतर भविष्य की उम्मीद जगा रहा है

सुकमा जहाँ सड़कें खत्म होती हैं, वहाँ से शुरू होती है उम्मीद की नई किरण

■ सुकमा जहाँ सड़कें खत्म होती हैं, वहाँ से शुरू होती है उम्मीद की नई किरण

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला, जो कभी अपनी भौगोलिक दुर्गमता के लिए जाना जाता था, आज स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नई इबारत लिख रहा है। "मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान" के तहत वनांचल के उन हिस्सों तक डॉक्टर और दवाइयां पहुँच रही हैं, जहाँ पहुँचना कभी नामुमकिन सा लगता था। यह अभियान केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि बस्तर की पहाड़ियों में बसने वाले आदिवासियों के लिए जीवन का नया उजाला बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान आज सुकमा के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में बेहतर भविष्य की उम्मीद जगा रहा है।

दहलीज पर डॉक्टर- घर-

संकल्प की शक्ति-310 किलोमीटर का जीवन सफर

हाल ही में पुटेपढ़ गांव से एक मरीज को जिला अस्पताल तक पहुँचाने की घटना स्वास्थ्य विभाग के समर्पण का जीवंत उदाहरण है। कलेक्टर सुकमा के मार्गदर्शन में पोटकपल्ली की टीम ने मरीज को किस्टाराम से होते हुए सुकमा जिला अस्पताल पहुँचाया। 310 किलोमीटर की यह चुनौतीपूर्ण यात्रा केवल एक रेफरल नहीं था, बल्कि प्रभावी काउंसलिंग, समय पर निर्णय और मजबूत फॉलो-अप का परिणाम था, जिसने एक अनमोल जीवन बचा लिया।

घर जांच और उपचार

इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता इसकी पहुँच है। स्वास्थ्य कर्मी अब केवल अस्पतालों में मरीजों का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि खुद पैदल चलकर दुर्गम गांवों तक पहुँच रहे हैं। मलेरिया, टीबी और कुष्ठ जैसी बीमारियों की मौके पर जांच कर रहे हैं। जीवनशैली बीमारियां, बीपी, शुगर, सिकलसेल और कैंसर जैसे गंभीर रोगों की पहचान कर उपचार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

आयुष्मान भारत- आर्थिक बेड़ियों से आजादी

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के अनुसार आयुष्मान भारत योजना गरीब परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज अब ग्रामीणों को इलाज के लिए जमीन बेचने या कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हाल ही में किस्टाराम और मर्दगुड़ा के 14 मरीजों के आयुष्मान कार्ड मौके पर ही बनाकर दिए गए, ताकि इलाज में एक क्षण की भी देरी न हो।

छत्तीसगढ़ का 44 प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र औषधीय गुणों का खजाना है। मुख्यमंत्री ने श्री साय ने पद्मश्री हेमचंद मांझी के योगदान को रेखांकित करते हुए बताया कि कैसे पारंपरिक आयुर्वेद से कैंसर जैसी बीमारियों का उपचार संभव हो रहा है।

न्यूज गैलरी

1 मई से अवैध नल कनेक्शनों पर निगम की बड़ी कार्रवाई, 14,200 रुपये जुर्माना तय

जगदलपुर/नवप्रदेश। शहर में जल व्यवस्था को पारदर्शी और अनुशासित बनाने के उद्देश्य से नगर निगम जगदलपुर ने अवैध नल कनेक्शनों के खिलाफअब तक की सबसे बड़ी सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। 17 फरवरी से नगर निगम के पीएचई अमले द्वारा चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान में अब तक 286 अवैध नल कनेक्शन चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 204 उपभोक्ताओं ने निर्धारित शुल्क जमा कर अपने कनेक्शन वैध करा लिए हैं, जबकि 82 अवैध कनेक्शन तत्काल प्रभाव से काट दिए गए हैं।नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 मई 2026 से अवैध नल कनेक्शन पाए जाने पर उसे नियमित कराने के लिए 14,200 रुपये की राशि देनी होगी। वहीं 30 अप्रैल तक यह सुविधा मात्र 5,000 रुपये में उपलब्ध रहेगी। निगम प्रशासन ने इसे अंतिम अवसर बताते हुए नागरिकों से समय रहते लाभ लेने की अपील की है।

जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन खेल बैठक सम्पन्न प्रशिक्षण शिविर 4 से 25 मई तक

कांकेर /नवप्रदेश। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 04 से 25 मई तक सुबह 06 से 08 बजे तक एवं सायंकाल 05 से 07 बजे तक शासकीय नरहरदेव उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांकेर के खेल मैदान एवं जिला खेल परिसर सिंगारभाट कांकेर में आयोजन किया जाएगा। प्रभारी खेल अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष जिला स्तरीय खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन में प्रशिक्षक फुटबॉल, कराटे, खो-खो, एथलेटिक्स, हैण्डबॉल, वालीबॉल और बैडमिंटन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर हेतु व्यवस्थित खेल मैदान, खेल सामग्री, प्रशिक्षक की व्यवस्था, प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ियों को शुद्ध पेयजल, पौष्टिक आहार आदि समस्त व्यवस्था विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश हेतु खिलाड़ियों की आयु सीमा मय दस्तावेज निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र तथा 8 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बालक, बालिकाओं को शामिल किया जाएगा। आयु प्रमाण के लिए प्रवेश लेने वाले खिलाड़ियों से जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड अथवा ऐसी दस्तावेज जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो। प्रशिक्षणार्थी जिस खेल में भाग लेना चाहते हैं, उन खेलों से संबंधित प्रशिक्षण स्थल अथवा कार्यालय खेल अधिकारी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग कांकेर में जाकर सीधे सम्पर्क कर अपना नाम पंजीयन अथवा आवेदन जमा करा सकते हैं।

करोड़ो का राजस्व देने वाले क्षेत्र को मिल रहा है धूल धक्कड

अंतागढ़ / नवप्रदेश। अंतागढ़ से रेल्वे स्टेशन जाने वाली सड़क का जर्जर स्थिति दिनों दिनों। बढ़ती जा रही है करोड़ो की सड़क अब अब धूल फंक रही हैसड़क की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है डामर पूरी तरह से उखड़ कर जैसे सड़क जमीन में समा रही हो वही अब सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुका है तथा लोगो की परेशानी भी बढ़ गई है सिर्फमरम्मत के नाम पर गिट्टी मिट्टी से पाट काम में लिया जा रहा है घटिया स्तर से बने सड़क लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ है। न तो इसमें चला जा सकता है न चलाया जा सकता है वाहन के चक्के गड्ढों में फंसते नजर रहे है सडक को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाहनों का चेचिस भी मानो सड़क को छूने बेकरार है आए दिन गाड़िया खराब हो रही है जिससे छोटी गाड़ियों के मालिक सबसे ज्यादा परेशान है कहा जाये तो सडक अपनी दयनीय स्थिति के लिए आंसू बहा रहा हो किन्तु जवाबदार विभाग आंखे मूंदे बैठा है वही स्थानीय जनप्रतिनिधि तो चश्मा लगाए बैठे है जिन्हें कुछ दिखता ही नहीं । रोज इसी मार्ग से अपनी रोजो रोटी चलाने वाले ऑटो टैक्सी चालकों ने शासन प्रशासन की कार्य शैली को देखते थक हार आज खुद जिम्मा संभाला और तपती धूप में फावड़ा गैती लेकर ऑटो चालक पहुंच मिट्टी गिट्टी से गड्ढा पाटने की कोशिश की लेकिन गड्ढों का आकार विशाल होने के चलते पूरा पाटा नहीं जा सका फिर भी अपने स्तर से कोशिश जारी रही और उसे चलाने लायक बनाया।

गौ-सम्मान के लिए गूंजा फरसगांव, गौ-सेवकों ने रैली निकाल तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

फरसगांव/नवप्रदेश। भारतीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ 'गौ-वंश' के संरक्षण हेतु आज फरसगांव में जन-आक्रोश और समर्पण का अनूठा संगम देखने को मिला। ‘गौ सम्मान आह्वान अभियान’ के अंतर्गत नगर के अस्पताल ग्राउंड पर बड़ी संख्या में गौ-सेवक, संत समाज और जागरूक नागरिक एकत्रित हुए, जहाँ से एक विशाल रैली निकालकर गौ-माता के सम्मान और सुरक्षा की हुंकार भरी गई।

रैली के माध्यम से एकजुटता का प्रदर्शन

अस्पताल ग्राउंड से शुरू हुई यह रैली नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। रैली में शामिल लोग हाथों में तख्तियां लिए और ‘गौ-माता की जय’ के नारे लगाते हुए चल रहे थे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि भारतीय परंपराओं में गाय का स्थान सर्वोपरि है, किंतु वर्तमान में उनकी स्थिति दयनीय होती जा रही है। विषमुक्त खेती और पर्यावरण संतुलन के लिए गौ-वंश का सुरक्षित होना अनिवार्य है।

प्रशासन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई आवाज

रैली के समापन पर प्रदर्शनकारियों ने फरसगांव तहसीलदार डॉ जय कुमार नाग को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि गौ-वंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए सख्त कानून बनाए जाएं। साथ ही छत्तीसगढ़ एवं प्रभावी प्रयास किए जाएं।

गौ सम्मान आह्वान अभियान की गूंज:

अभियान के सदस्यों ने बताया कि यह केवल एक ज्ञापन नहीं, बल्कि समस्त क्षेत्रवासियों की भावनाओं का प्रतीक है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि इन भावनाओं को उचित माध्यम से देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे माननीयों तक पहुंचाया जाए।इस अवसर पर स्थानीय गौ-सेवक दल, क्षेत्र के गणमान्य नागरिक और भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में संकल्प लिया कि जब तक गौ-वंश को उनका खोया हुआ सम्मान नहीं मिल जाता, यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। गौ-रक्षा केवल एक धर्म नहीं, बल्कि हमारे पर्यावरण और भविष्य को बचाने का एक संकल्प है।

देशव्यापी अभियान चलाकर गौ-माता को उचित सम्मान और सुरक्षा प्रदान की जाए। स्थानीय स्तर पर लावारिस गौ-वंश के लिए उचित चारे और आश्रय की व्यवस्था सुनिश्चित हो।

देवी-देवताओं के मिलन से महका भक्तिमय माहौल

जोड़ेकेरा में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब दिखा संस्कृति का अनूठा संगम

फरसगांव/बड़ेराजपुर/नवप्रदेश । कोंडागांव जिले के विकासखण्ड बड़ेराजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत जोड़ेकेरा-जामपारा में सोमवार 27 अप्रैल को आस्था, परंपरा और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। अवसर था चीखला माता एवं मावली माता वार्षिक मेले का, जहाँ हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की। मांदरी की थाप और पारंपरिक वेशभूषा में सजे ग्रामीणों ने इस आयोजन को एक उत्सव में बदल दिया।

देवी-देवताओं का भव्य आगमन और शाही मिलन

मेले का मुख्य आकर्षण क्षेत्रीय देवी-देवताओं का पारंपरिक मिलन रहा। बढ़वतर, जामपारा, जोड़ेकेरा, और गुडरीपारा सहित आसपास के दर्जनों गांवों से देवी-देवताओं के विग्रहों को गाजे-बाजे के साथ मेला स्थल लाया गया।

राउत नाचा ने मोहा मन, मांदरी की थाप पर थिरके कदम

इस वर्ष मेले में राउत नाचा विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। रंग-बिरंगी वेशभूषा और हाथ में सजी लाठियों के साथ यादव समाज के नर्तकों ने अपनी कला का प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं, पारंपरिक मांदरी बाजा की गूंज पर युवा, बुजुर्ग और महिलाएं जमकर थिरके, जो बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर रहा था।

पुरानी परंपरा और अटूट विश्वास:

स्थानीय ग्रामीणो ने पुरानी परंपरा और अटूट विश्वास को जताते हुए कहा कि यह मेला केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी पीढ़ियों की विरासत है। यहाँ हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं और देवी माँ का आशीर्वाद लेते हैं। मेले के दौरान गायता, पुजारी और पटेलों द्वारा विधिवत पूजा-अर्चना संपन्न कराई गई। पूजा के पश्चात सामूहिक रूप से प्रसाद वितरण किया गया, जिसे ग्रहण करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गई।

बस्तर ओपन शतरंज प्रतियोगिता में बुद्धि-रणनीति का शानदार संगम

■ जिलेभर के खिलाड़ियों ने दिखाया कौशल

जगदलपुर/नवप्रदेश। जिला शतरंज संघ बस्तर द्वारा 26 अप्रैल 2026 को आयोजित बस्तर ओपन शतरंज प्रतियोगिता ने खेलप्रेमियों और खिलाड़ियों के बीच नई ऊर्जा का संचार किया। जिलेभर से पहुंचे प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी रणनीतिक क्षमता और बौद्धिक कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ पुलिस उप महानिरीक्षक कमलोचन कश्यप ने दीप प्रज्वलित कर तथा शतरंज की गोटी चलाकर किया।

कार्यक्रम में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहायक संचालक सुशांत पाल, खंड शिक्षा अधिकारी अनिल दास, अशोक तिवारी एवं रोमा राव की उपस्थिति ने आयोजन को गरिमा प्रदान की। सभी अतिथियों ने जिला शतरंज संघ की सराहना करते हुए भविष्य में हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।प्रतियोगिता के डायरेक्टर शशांक श्रीधर ने जानकारी दी कि खिलाड़ियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पांच राउंड के मुकाबले आयोजित किए गए।सुव्यवस्थित संचालन और अनुशासित माहौल में प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें प्रतिभागियों ने उच्चस्तरीय खेल प्रदर्शन कर दर्शकों को प्रभावित किया।पुरस्कार वितरण समारोह में विधायक एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव तथा नगर पालिक निगम जगदलपुर के सभापति खेमसिंह देवांगन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विजेताओं को ट्रॉफी, नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए।

समाजसेवी संस्था ने मनोरोगी की ली सुध इलाज़ कराकर परिजनों से मिलाया

कांकेर /नवप्रदेश। समाजसेवी संस्था ‘जन सहयोग’ ने कुछ दिनों पूर्व जिस मनोरोगी का पता लगाकर उसके भोजन वस्त्र आदि का प्रबंध किया था, तब से यह भी पता लगाया जा रहा था कि वह कहां का रहने वाला है ? पुलिस तथा सोशल मीडिया की भी सहायता ली गई थी। सोशल मीडिया के जरिए मनोरोगी के राजनांदगांव मोतीपुर में रहने वाले भाई से बातचीत हुई और पता चला कि वह 10 माह से अपने परिवार से नहीं मिला है, इधर-उधर घूम रहा है। उसका नाम महादेव देवांगन है। यह पता लगते

ही जन सहयोग के अध्यक्ष अजय पप्पू मोटवानी ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया तथा महादेव देवांगन के परिजनों को कांकेर बुलाकर पुलिस के समक्ष ही उसके राजनांदगांव मोतीपुर जाने का प्रबंध किया। 10 माह बाद मुलाकात होने पर रिश्तेदारों की खुशी का ठिकाना नहीं था।

साप्ताहिक बाजार में सिंगल यूज पॉलीथीन के खिलाफ अभियान

■ 23 व्यापारियों पर लगा जुर्माना

फरसगांव/नवप्रदेश। नगर पंचायत फरसगांव को सिंगल यूज पॉलीथीन से मुक्त करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रशासन ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी कड़ी में सोमवार को नगर पंचायत की राजस्व टीम ने स्थानीय साप्ताहिक बाजार में दबिश देकर प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की।

बाजार में हड़कंप, 23 व्यापारियों से वसूला अर्थदंड

सोमवार को हुई इस आकस्मिक कार्रवाई से बाजार क्षेत्र में हड़कंप मच गया। राजस्व टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि शासन द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद कई व्यापारी धड़ल्ले से सिंगल यूज पॉलीथीन का उपयोग कर रहे थे। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 23 लोगों पर अर्थदंड लगाया, जिनसे कुल 1300 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।

लगभग 5 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त

जुर्माने के साथ-साथ टीम ने दुकानों और ठेलों की सघन तलाशी ली। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध रूप से रखी गई 4 किलो 700 ग्राम सिंगल यूज पॉलीथीन जब्त की गई। नगर पंचायत की ओर से व्यापारियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि यदि भविष्य में दोबारा प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग पाया गया, तो और भी कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

मोबाइल ऐप से स्वयं की जनगणना कर किरण देव ने दिया डिजिटल भागीदारी का संदेश

■ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक ने परिवार का विवरण स्वयं दर्ज कर पेश की मिसाल

जगदलपुर/नवप्रदेश। डिजिटल भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं जगदलपुर विधायक किरण देव ने स्वयं मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने परिवार की जनगणना प्रक्रिया पूर्ण की। इस अवसर पर उन्होंने तकनीक आधारित जनभागीदारी को समय की आवश्यकता बताते हुए नागरिकों से भी इसी माध्यम से जनगणना कार्य में सक्रिय सहयोग करने का आग्रह किया। इस दौरान निगम अध्यक्ष खेमसिंह देवांगन भी मोबाइल एप से जनगणना सबंधी जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि जनगणना केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश की विकास योजनाओं की आधारशिला है। सही और समयबद्ध आंकड़े शासन की नीतियों को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह इस राष्ट्रीय कार्य में जिम्मेदारीपूर्वक भागीदारी निभाए।

मोबाइल ऐप के जरिए स्वयं अपना जनगणना कार्य कर विधायक ने यह संदेश दिया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी प्रक्रियाओं को सरल,तेज और पारदर्शी बनाया जा सकता है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे जागरूक बनें।

वैशाख मेले में उमड़ा जनसैलाब, कुरंदी की आस्था में शामिल हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष

■ माता शीतला मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश और बस्तर की समृद्धि की कामना

जगदलपुर/नवप्रदेश। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कुरंदी में आयोजित ऐतिहासिक वार्षिक वैशाख मेला इस वर्ष भी आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक वैभव का भव्य केंद्र बना। माता शीतला मंदिर परिसर में आयोजित इस वार्षिक मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और ग्रामीणों की उपस्थिति ने आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान की। मेले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक किरण देव शामिल हुए और माता शीतला मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना कर छत्तीसगढ़ प्रदेश तथा बस्तर की सुख-समृद्धि की कामना की।

इस अवसर पर उन्होंने मेले में उपस्थित ग्रामीणों और जनमानस से सीधे संवाद किया तथा उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए। इससे आयोजन केवल धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा,बल्कि जनसंपर्क और समस्या समाधान का मंच भी बना।ग्रामवासियों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ तिलक लगाकर उनका आत्मीय स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में उत्साह और उल्लास का वातावरण देखने को मिला।

49 लाख से अधिक के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन

■ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने ग्रामीण विकास को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता

जगदलपुर/नवप्रदेश। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कुरंदी में सोमवार को विकास की नई इबारत लिखी गई, जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक किरण देव ने 49 लाख 10 हजार रुपए की लागत से विभिन्न निर्माण कार्यों का विधिवत भूमिपूजन किया। इस अवसर पर ग्रामीणों में उत्साह का माहौल देखने को मिला और क्षेत्र में विकास की नई उम्मीद जगी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किरण देव ने कहा कि जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में क्षेत्र में चौमुखी विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। जनता की मांग और जरूरतों के अनुरूप योजनाओं को धरातल पर उतारना सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास ही उनका लक्ष्य है और अंतिम व्यक्ति तक विकास की पहुंच सुनिश्चित करना उनका दायित्व है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिन मांगों को ग्रामीणों ने रखा है,उन्हें भी शीघ्र पूरा करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। उन्नयन कार्य पर 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। इन सभी कार्यों से ग्राम क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। कुरंदी और आसपास के क्षेत्रों में स्वीकृत विकास कार्य केवल निर्माण परियोजनाएं नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन स्तर सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

सातों तहसीलों में एकजुट हुए गौ सेवक,राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन

बस्तर से उठी बुलंद आवाज़, गौमाता को 'राष्ट्रमाता' घोषित करने की मांग तेज

■ 'गौ सम्मान आह्वान अभियान' के तहत बस्तर ने संवैधानिक दर्जे और सशक्त संरक्षण की मांग रखी

जगदलपुर/नवप्रदेश। बस्तर जिले में रविवार को 'गौ सम्मान आह्वान अभियान' के तहत व्यापक जनभागीदारी के साथ गौवंश को 'राष्ट्रमाता' घोषित करने की मांग जोरदार ढंग से उठाई गई। जिले की सातों तहसीलों जगदलपुर,तोकापाल,बस्तर, बकावंड,नानगुर,बास्तानार और भानपुरी में प्रबुद्ध नागरिकों, गौ सेवकों, संत समाज एवं सामाजिक संगठनों ने शोभायात्रा निकालकर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति,प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित किया गया।

अभियान के माध्यम से गौवंश को संवैधानिक और सांस्कृतिक सम्मान दिलाने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 और 51 (ए) की मूल भावना के अनुरूप देशी गौवंश को 'राष्ट्रमाता' का आधिकारिक दर्जा दिया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार से विधानसभा में विशेष संकल्प पारित कर गौमाता को 'राज्य माता' घोषित करने का आग्रह किया गया।

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि वर्तमान समय में गौवंश असुरक्षा,उपेक्षा और अव्यवस्था का सामना कर रहा है। सड़कों पर भटकते और प्लास्टिक खाने को विवश गौवंश की स्थिति को सामाजिक चेतना के लिए गंभीर चुनौती बताया गया। इस समस्या के समाधान के लिए एकीकृत केंद्रीय गौ सेवा अधिनियम, गौ तस्करी को गैर-जमानती अपराध घोषित करने तथा दोषियों की संपत्ति राजसात करने जैसे कठोर प्रावधानों की मांग रखी गई।

अभियान के दौरान प्राकृतिक कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गौ आधारित मॉडल को पुनर्जीवित करने पर भी बल दिया गया। ज्ञापन में स्कूली पाठ्यक्रमों में 'गौ विज्ञान' को शामिल करने, गौ उत्पादों के लिए पृथक विपणन तंत्र विकसित करने तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में नंदीशाला और जिला स्तर पर आदर्श गौ अभयारण्य स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया।

बस्तर की जनता ने इस अभियान को निःस्वार्थ,अहिंसक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का माध्यम बताते हुए विश्वास व्यक्त किया कि गौवंश संरक्षण की दिशा में ठोस निर्णय देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को नई मजबूती देंगे।

ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में गौ भक्त,संत समाज, विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सुशासन तिहार में मिले सभी आवेदनों का प्राथमिकता से समयबद्ध समाधान करने के निर्देश

बलरामपुर/नवप्रदेश। जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ ने सुशासन तिहार, राजस्व प्रकरण, स्वास्थ्य, आयुष्मान कार्ड, पीएम जनमन सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जिला पंचायत सीईओ ने सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत संचालित विशेष अभियान की समीक्षा करते हुए प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुशासन तिहार का आयोजन किया जाना है। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार शासन की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अभियान के तहत प्राप्त प्रत्येक आवेदन का गंभीरता से निराकरण करने को कहा। सीईओ श्रीमती तोमर ने कहा कि 1 मई से जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो इसके लिए सभी संबंधित विभाग आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ले। उन्होंने कहा कि शिविरों में प्राप्त आवेदनों का यथासंभव तत्काल निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को त्वरित राहत मिल सके। साथ ही कोई भी पात्र हितग्राही शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। जिला पंचायत सीईओ ने 9 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के दृष्टिगत संबंधित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के

निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करें, जिससे अधिक से अधिक प्रकरणों का समाधान लोक अदालत में हो सके। उन्होंने राजस्व प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा करते हुए निराकरण की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व पखवाड़ा में प्राप्त आवेदनों एवं उनके निराकरण की विस्तृत जानकारी लेते हुए कहा कि राजस्व पखवाड़ा के अंतर्गत प्राप्त आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें। ताकि आमजन को शीघ्र राहत मिल सके। उन्होंने भू-अर्जन से संबंधित लंबित प्रकरणों, जनचौपाल एवं जनदर्शन तथा समय-सीमा के प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करते हुए साप्ताहिक प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने एलपीजी की आपूर्ति, पेट्रोल की उपलब्धता, राशन के भंडारण एवं वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न हो तथा आम नागरिकों को नियमित रूप से सुविधाएं उपलब्ध होती रहें। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए जिला पंचायत सीईओ ने दूरस्थ अंचलों तक मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से पहुंचाई जा रही चिकित्सकीय सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करें, ताकि ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को समय पर परामर्श एवं उपचार उपलब्ध हो सके।

न्यूज गैलरी

विद्यार्थियों के लिए रोजगार मेला आयोजित

मुंगेली/नवप्रदेश। पीएम श्री एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बंधवा में 28 अप्रैल को राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली एवं टाटा मोटर्स द्वारा संचालित कौशल कार्यक्रम के अंतर्गत एकलव्य विद्यालयों से 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए एक दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। विद्यालय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकलव्य विद्यालयों के विद्यार्थियों को सुबह 9 बजे तक निर्धारित स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य है। इस रोजगार मेले का उद्देश्य कक्षा 12वीं उत्तीर्ण युवाओं को रोजगार एवं कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को आधार कार्ड, 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची, पासपोर्ट साइज फोटो सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य किया गया है। जिन छात्रों का 12वीं का परिणाम घोषित नहीं हुआ है, वे विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। विशेष बात यह है कि 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के वे छात्र, जो ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कर पाए हैं, वे मेले के दिन ही स्थल पर पंजीकरण करा सकते हैं। विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यार्थियों की सुरक्षा, आवागमन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। विद्यालय के प्राचार्य जितेन्द्र सिंह तंवर ने बताया कि यह विद्यालय और मुंगेली जिले के लिए गर्व का विषय है।

अग्निवीर अभ्यर्थियों के निःशुल्क प्रशिक्षण

मुंगेली/नवप्रदेश। जिले के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर सामने आया है। अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार लिखित परीक्षा की बेहतर तैयारी कराने हेतु निःशुल्क कोचिंग प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि अग्निवीर भर्ती हेतु ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई थी। अब पंजीकृत आवेदकों के लिए 4 मई से 4 जून तक निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं संचालित की जाएंगी। जिससे अभ्यर्थी लिखित परीक्षा की प्रभावी तैयारी कर सकें। इच्छुक एवं पंजीकृत आवेदक 30 अप्रैल तक रोजगार विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर कोचिंग हेतु अपना पंजीयन करा सकते हैं।

अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण 1 से

बलरामपुर/नवप्रदेश। जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी दी है कि अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन लिखित परीक्षा (सीईई) की तैयारी हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती 2027 के लिए जारी अधिसूचना के तहत 10 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। पंजीकृत अभ्यर्थियों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा 01 जून 2026 से 15 जून 2026 के मध्य आयोजित किया जाना संभावित है। इस परीक्षा की तैयारी को सुदृढ़ बनाने के लिए संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, बलरामपुर द्वारा 01 मई 2026 से 31 मई 2026 तक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक पंजीकृत अभ्यर्थी रोजगार विभाग के पोर्टल https://erojgar.cg.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही विस्तृत जानकारी के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, बलरामपुर के सूचना पटल का अवलोकन अथवा कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

जिपं सीईओ ने जनदर्शन में सुनी आमजनों की समस्याएं

बलरामपुर/नवप्रदेश। संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक पश्चात जनदर्शन में आमजनों ने अपनी समस्याओं को जिला पंचायत सीईओ के समक्ष रखा। जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर ने आमजनों से प्राप्त शिकायत एवं समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुनकर जनदर्शन में प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ निराकरण करने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का गुणवतापूर्ण एवं प्राथमिकता से निराकरण करना सुनिश्चित करें।

मांगे पूरी नहीं होने पर कृषि आदान व्यापारी खरीफ सीजन के पूर्व करेंगे अनिश्चितकालीन आन्दोलन

बलरामपुर/नवप्रदेश। राज्य में तकरीबन 5 लाख कृषि आदान व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले छत्तीसगढ़ एग्री इनपुट डीलर्स एसोसिएशन की 12 सूत्रीय मांगो को पिछले 10 वर्षों से केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा अनसुना किया जा रहा है। इस बात से आक्रोशित होकर सोमवार को कृषि आदान व्यापारियों ने एक दिन का सांकेतिक हड़ताल कर कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री को अनुरोध पत्र प्रेषित किया है। चेतावनी दी गई है कि यदि इन मांगों पर शीघ्र सुनवाई नहीं की गई तो आने वाले खरीफ सीजन के पूर्व अनिश्चितकालीन बंद किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि छ.ग. एग्रीइनपुट डीलर्स एसोसिएशन के खाद, बीज एवं कीटनाशक विक्रेताओं का एक रजिस्टर्ड संगठन है जो लगभग 5 लाख व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है। संगठन के सदस्यों द्वारा पिछले 10 सालों से बारह सूत्रीय समस्याओं का सामना किया जा रहा है। बावजूद इसके, केंद्र एवं राज्य सरकारों के सम्बंधित अधिकारी इसका निराकरण नहीं कर रहे हैं। इस बात से क्षुब्ध होकर जिले के कृषि आदान व्यापारियों ने सोमवार को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री को अनुरोध पत्र जेजा। व्यापारियों का कहना है कि उर्वरक निर्माता कंपनियों द्वारा सब्सिडी वाले खाद के साथ अनुपयोगी उत्पादों की जबरन लिंकिंग' को अपराध घोषित किया जाए और उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय की तर्ज पर पूरे देश में अनुदानित उर्वरक के साथ गैर-अनुदानित उत्पाद बेचने की बाध्यता पर रोक लगे। खाद की डिलीवरी डीलर के बिक्री केंद्र तक कंपनियों द्वारा सुनिश्चित की जाए। वर्तमान में यूरिया जैसे खाद की डिलीवरी रेल-हेड पर दी जा रही है, जिससे डीलरों को प्रति बैग 40 से 50 रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ रहा है। इसी प्रकार बढ़ती

लागत और महंगाई को देखते हुए उर्वरकों पर डीलर मार्जिन को बढ़ाकर कम से कम 8 प्रतिशत किया जाए। ग्रामीण खुदरा विक्रेताओं के लिए पोर्टल को वैकल्पिक बनाया जाए और इसकी अनिवार्यता केवल निर्माताओं एवं थोक विक्रेताओं तक सीमित रखी जाए। व्यापारियों के अनुसार अवैध बीजों की बिक्री पर प्रज्ञावी रोक लगे या अधिकृत डीलरों को विनियमित बिक्री की अनुमति दी जाए। खाद, बीज एवं कीटनाशक के सीलबंद पैकिंग में नमूना फेल होने पर विक्रेता को अपराधी नहीं, बल्कि केवल गवाह माना जाए। चूंकि विक्रेता जिला कृषि अधिकारी से प्राप्त लाइसेंस के आधार पर केवल सीलबंद माल बेचता है, इसलिए गुणवत्ता की पूर्ण जिम्मेदारी निर्माता कंपनी की होनी चाहिए। कंपनियों के लिए पुराने या एक्सपायर्ड स्टॉक को वापस लेना कानूनी रूप से अनिवार्य किया जाए। एसोसिएशन द्वारा सौंपे गए अनुरोध पत्र में नए बीज अधिनियम और कीटनाशक विधेयक 2025 में रिटेल डीलर को 'प्रथम पद्म बनाने के कठोर प्रावधान को शिथिल करने, किसानों द्वारा व्यापारियों के खिलाफ झूठी शिकायत पर कार्रवाई करने के पहले जिला स्तर पर जांच कमेटी बनाने, 21 दिन में बहाली छोटी-मोटी बातों पर उप संचालक कोष द्वारा लाइसेंस निलंबित किए जाने पर 21 दिन में स्वतः बहाली का प्रावधान करने, हर साल पीसी जोड़ने की अनिवार्यता समाप्त हो खाद एवं बीज के लाइसेंस की अवधि 5 वर्ष एवं कीटनाशक के लाइसेंस आजीवन है ऐसी स्थिति में हर साल कंपनी के प्रिंसिपल सर्टिफिकेट जोड़ने की अनिवार्यता को समाप्त करने, दोहरी लायसेंस प्रथा को बन्द करने और अनाज व उद्यानिकी के बीजों के लिए अलग-अलग लाइसेंस की प्रक्रिया को समाप्त करने जैसी मांगे शामिल हैं। एसोसिएशन के सदस्यों ने आगामी एक माह में इन समस्याओं के उचित निराकरण हेतु ठोस कदम उठाने का अनुरोध करते हुए चेतावनी दी है कि यदि इन मांगो को पूरा नहीं किया गया तो आगामी खरीफ सीजन के पूर्व अनिश्चितकालीन आन्दोलन करने को मजबूर होंगे। बंद करना होगे जिससे देश के कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रज्ञाव होने के साथ-साथ किसानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जिसकी संपूर्ण जवाबदारी राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार के अधिकारियों की होगी।

परीक्षा का नतीजा जीवन का फैसला नहीं : जयपुरिया

छात्रों को दिए हौसले और उम्मीद का संदेश

बम्हनीडीह/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं परीक्षा परिणाम 29 अप्रैल को जारी किए जाने की खबर से लाखों छात्र छात्राओं में उत्साह और घबराहट दोनों देखी जा रही है ऐसे समय जांजगीर चांपा जिला शिक्षा समिति अध्यक्ष एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष गगन जयपुरिया ने विद्यार्थियों के पक्ष में बड़ी और संवेदनशील बात कही है उन्होंने कहा कि परीक्षा में पास फेल होना जीवन का सामान्य हिस्सा है इसे आखिरी मंजिल या हार जीत का फैसला नहीं समझना चाहिए । गगन जयपुरिया ने छात्रों से अपील करते हुए कहा कि एक नंबर शीट

किसी बच्चे की पूरी काबिलियत तय नहीं करती कई बार मेहनती छात्र भी कम अंक ला देते हैं लेकिन वही आगे चलकर बड़ी सफलता हासिल करते हैं उन्होंने कहा कि परिणाम चाहे जैसा आए छात्र निराश न हों बल्कि आगे की तैयारी और मेहनत में लग जाएं ।

अभिभावकों बच्चों पर न डाले दबाव

जयपुरिया ने अभिभावकों से निवेदन किया कि बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालें क्योंकि कई छात्र तनाव में गलत कदम उठा लेते हैं जो बेहद दुखद है उन्होंने कहा कि हर बच्चे में कोई न कोई प्रतिभा होती है जरूरत सिर्फ उसे पहचानने और सही दिशा देने की है माता पिता अपने बच्चों के लिए जीवन भर संघर्ष करते हैं इसलिए बच्चों को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए असफलता सिर्फ एक पड़ाव है मंजिल नहीं उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिले के हर छात्र के उज्जवल भविष्य के लिए वे हमेशा साथ खड़े हैं ऐसे समय नेताओं और जनप्रतिनिधियों को बच्चों का मनोबल बढ़ाने आगे आना चाहिए ताकि कोई छात्र अकेला महसूस न करे ।

विद्यार्थियों का शील्ड व प्रमाण पत्र से किया सम्मान

परमेश्वरी पब्लिक स्कूल सक्ती का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित

सक्ती/नवप्रदेश। परमेश्वरी देवी शिक्षण समिति द्वारा संचालित परमेश्वरी पब्लिक स्कूल सक्ती का शैक्षणिक सत्र 2025-26 का प्रबंधन समिति सचिव कृष्णा कुमार देवांगन, कोषाध्यक्ष रेखा देवांगन एवं संस्था प्रमुख एम. विकास देवांगन की गरिमामय उपस्थिति में दिनांक 27 अप्रैल 2026 को कक्षा नर्सरी से दूसरी एवं दिनांक 28 अप्रैल 2026 को कक्षा-तीसरी से नवमीं की परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। जिसमें सभी छात्र-छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपने माता-पिता और स्कूल का नाम गौरवान्वित किया। कक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान आने वाले छात्र-छात्राओं को प्रबंधन समिति सचिव कृष्ण कुमार देवांगन, कोषाध्यक्ष रेखा देवांगन एवं संस्था प्रमुख एम. विकास देवांगन के द्वारा शील्ड एवं प्रमाण पत्र दे कर सम्मानित किया गया। प्री-प्रायमरी में कक्षा नर्सरी में चांदनी गबेल पिता गजाधर सिंह, कनिका केवट पिता धीरज केवट, सोनम देवांगन ने पहला स्थान, हिना देवांगन पिता राधे श्याम देवांगन ने दूसरा स्थान तथा सानिया जायसवाल पिता राधेश्याम जायसवाल तीसरा स्थान, कक्षा के जी 1 में देवेंद्र यादव पिता

श्याम कुमार यादव, हिमांशु चौहान पिता पदुम लाल चौहान ने पहला स्थान, मलय देवांगन पिता संतोष देवांगन, लोकेश नवनीत पिता राकेश नवनीत ने दूसरा स्थान एवं यशु साहू पिता शोभा लाल, शौर्य साहू ने तीसरा स्थान, कक्षा के जी 2 में श्रेया देवांगन पिता धमरुधर देवांगन, विनिशा जायसवाल पिता देवचरण जायसवाल ने पहला स्थान, नुशांत देवांगन पिता राकेश देवांगन, मिष्टी केवट पिता धनेश केवट ने दूसरा स्थान एवं रौनक यादव पिता दुर्गेश यादव, ऋषभ सिदार पिता कृष्ण कुमार सिदार ने प्रायमरी में कक्षा पहली में आराध्य कसेर पिता विकास कसेर, सिद्धांत कूर्रे पिता विकास कूर्रे, सृष्टि कसेर पिता निशांत कसेर एवं मौली देवांगन पिता राम कुमार देवांगन ने पहला स्थान, दीप्ति देवांगन पिता कमलेश देवांगन, शैलेंद्र जायसवाल पिता योगेश जायसवाल एवं योगिता देवांगन पिता घुराउ राम ने दूसरा स्थान एवं दीक्षा बरेठ पिता संजय बरेठ, तृषिता महंत पिता वीरेंद्र महंत एवं इशिता जायसवाल पिता महेश जायसवाल ने तीसरा स्थान, कक्षा दूसरी में काव्या पटेल पिता गजाधर पटेल, रुत राजपूत पिता संतोष राजपूत, तेजल यादव पिता रविंद्र यादव एवं पार्थ पटेल पिता राकेश पटेल ने पहला स्थान, दृष्टि देवांगन पिता शिव देवांगन, मानवी सिदार पिता जय सिदार ने दूसरा स्थान प्राप्त किया।

कार्यालय नगर पंचायत - लखनपुर, जिला - सरगुजा (छ.ग.)

Ph. 07774-261501 email - cmolakhanpur@gmail.com

क्रमांक / 548/ लो.नि./ न.पं./2026-27 लखनपुर, दिनांक-27/4/26

प्रथम ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना

नगर पंचायत लखनपुर में एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत निविदाकारों से निर्माण कार्यों हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है -

System Tender no	Estimated Amount (Lakh)	Earnest Money Deposit	Bid Submission Start Date & Time	Bid Due Date & Time	Physical Document Submission Date & Time	Bid Open Date & Time
189822	24.46	18300/-	27.04.2026 After 17.30 PM	18.05.2026 Before 17.30 PM	22.05.2026 Before 14.00 PM	22.05.2026 After 15.00 PM

टीप- 01. उपरोक्त कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल https://cgeprocurement.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।
02. विज्ञापन की प्रति https://cg.uad.gov.in में देखी जा सकती है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत लखनपुर
जिला-सरगुजा (छ.ग.)

लगातार कार्रवाई से बढ़ी प्रशासन की साख

तहसीलदार की सख्ती से अवैध रेत कारोबारियों में हड़कंप, रेत सहित ट्रैक्टर जब्त

बम्हनीडीह/नवप्रदेश। तहसील क्षेत्र बम्हनीडीह में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ राजस्व प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है नए तहसीलदार शशिभूषण सोनी के पदभार संभालने के बाद क्षेत्र में लगातार निगरानी बढ़ाई गई है, जिससे रेत कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप की स्थिति बताई जा रही है प्रशासनिक टीम द्वारा नियमित गश्त, आकस्मिक जांच और त्वरित कार्रवाई के चलते अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की कोशिश तेज हो गई है इसी क्रम में आज ग्राम पंचायत सोठी क्षेत्र से 03 घन मीटर रेत से भरा एक ट्रैक्टर जब्त किया गया, जिसे थाना बम्हनीडीह की अभिरक्षा में सुपुर्द कर नियमानुसार प्रकरण दर्ज करने की

प्रक्रिया शुरू की गई है लगातार कार्रवाई के बाद क्षेत्र में प्रशासन की सक्रियता चर्चा का विषय बनी हुई है ।

लगातार मैदान में उतर रहे तहसीलदार, खुद कर रहे निगरानी: बताया जा रहा है कि तहसीलदार शशिभूषण सोनी स्वयं राजस्व अमले के साथ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं सुबह से देर शाम तक सोंठी, पिपरदा, पूछेली, खपरीडीह, बम्हनीडीह, सोनाडीह, करनौद से बिरां तक अलग-अलग गांवों और नदी घाटों पर निगरानी रखी जा रही है ताकि अवैध उत्खनन, भंडारण और परिवहन पर तत्काल रोक लगाई जा सके अधिकारियों की मौजूदगी से कई स्थानों पर संदिग्ध गतिविधियां थमती नजर आ रही हैं आज की कार्रवाई में ग्राम पंचायत सोठी क्षेत्र से अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा एक ट्रैक्टर पकड़ा गया। जांच में वाहन में लगभग 03 घन मीटर रेत भरी मिली। इसके बाद वाहन को जब्त कर थाना बम्हनीडीह में सुपुर्द किया गया। राजस्व विभाग द्वारा संबंधित प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है ।

पहले भी हो चुकी कई कार्रवाइयां: स्थानीय लोगों के अनुसार बीते कुछ समय में राजस्व विभाग द्वारा कई बार कार्रवाई की जा चुकी है लगातार जब्ती, जांच और निगरानी से अवैध रेत कारोबार से जुड़े लोगों पर दबाव बढ़ा है प्रशासन के सख्त रुख के कारण कई स्थानों पर अवैध परिवहन की रफ्तार धीमी पड़ने की चर्चा है क्षेत्र के नागरिकों का कहना है कि लंबे समय बाद राजस्व प्रशासन की सक्रियता खुलकर दिखाई दे रही है लोगों को उम्मीद है कि यदि इसी तरह लगातार अभियान चलता रहा तो अवैध उत्खनन पर प्रभावी रोक लग सकेगी, राजस्व हानि रुकेगी और नदी-नालों का संरक्षण भी होगा ग्रामीणों ने निष्पक्ष और निरंतर कार्रवाई जारी रखने की मांग की है ।

तहसीलदार और नायब तहसीलदार की टीम चर्चा में: इस अभियान में तहसीलदार शशिभूषण सोनी के साथ नायब तहसीलदार संजय बरेठ की सक्रिय भूमिका भी चर्चा में है दोनों अधिकारियों के नेतृत्व में राजस्व अमला लगातार क्षेत्र में पहुंचकर निरीक्षण कर रहा है प्रशासनिक समन्वय और त्वरित कार्रवाई से लोगों में भरोसा मजबूत होता नजर आ रहा है ।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, बस्तर मण्डल, जगदलपुर
ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना
https://eproc.cgstate.gov.in

निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है -
निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि - 08/05/2026

स. क्र.	नि.आ.सू.क्र./ नि.आ.सू. दिनांक	सिस्टम निविदा क्रमांक निविदा का क्रम	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रु. लाख में)
1	14/2026-27 दिनांक 23/04/2026	188548 (द्वितीय आमंत्रण)	जिला-बीजापुर, ब्लाक-भैरमगढ़ के अन्तर्गत डिग्री कॉलेज भैरमगढ़ में अतिरिक्त कक्ष (भुरवा माहिया) का निर्माण कार्य, विद्युतिकरण सहित।	130.79
2	15/2026-27 दिनांक 23/04/2026	188549 (चतुर्थ आमंत्रण)	सुकमा, जिला-सुकमा में फास्ट ट्रेक कोर्ट / जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के प्रथम तल में 01 नग न्यायालय भवन निर्माण कार्य विद्युतिकरण सहित।	179.63
3	16/2026-27 दिनांक 23/04/2026	189521 (द्वितीय आमंत्रण)	जिला-बीजापुर, ब्लाक-भैरमगढ़ के मिरतुर, में ट्राइबल हॉस्टल भवन का निर्माण कार्य।	46.36
4	17/2026-27 दिनांक 23/04/2026	189522 (द्वितीय आमंत्रण)	जिला-बीजापुर, ब्लाक-भैरमगढ़ के फरसेगढ़, में ट्राइबल हॉस्टल भवन का निर्माण कार्य।	46.36
5	18/2026-27 दिनांक 23/04/2026	189523 (द्वितीय आमंत्रण)	जिला-बस्तर के जगदलपुर नर्सिंग कॉलेज में 01 नग "एक" ट्राईप एवं 01 नग "जी" ट्राईप स्टॉफ क्वार्टर का निर्माण कार्य।	35.07
6	19/2026-27 दिनांक 23/04/2026	189524 (द्वितीय आमंत्रण)	जिला-सुकमा के आकार भवन का रिनोवेशन कार्य।	35.15

निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया एवं निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के उपरोक्त वेबसाईट में देखे जा सकते है।

अधीक्षण अभियंता
जी- 262700387/9 लोक निर्माण विभाग बस्तर मंडल जगदलपुर

सुशासन तिहार से पहले 30 तक लंबित प्रकरणों को निपटाने कलेक्टर ने दिए निर्देश

मुंगेली/नवप्रदेश। कलेक्टर कुन्दन कुमार ने जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में आयोजित बैठक में विभागीय योजनाओं एवं गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विभागवार प्रगति की जानकारी लेते हुए लंबित उपलब्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने 01 मई से 10 जून तक आयोजित होने वाले सुशासन तिहार की तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हुए कहा कि जिले में विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर आमजनों की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी निराकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 24 शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनका समय प्रातः 09 बजे से दोपहर 01 बजे तक निर्धारित किया गया है। शिविरों के सुचारू संचालन के लिए अधिकारियों के दायित्व तय करते हुए माइक, टेंट, छाया, पेयजल सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर दिया गया।

बैठक में कलेक्टर ने संतृप्तिकरण शिविरों के संबंध में जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि 30 अप्रैल तक लंबित सभी आवेदनों का शत-प्रतिशत एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाएं, ताकि आम नागरिकों को त्वरित लाभ मिल सके। उन्होंने विभाग प्रमुखों को अपने-अपने क्लस्टर के शिविरों की पूरी जानकारी रखने तथा आवेदन पंजीयन एवं निराकरण के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध निराकरण पर जोर देते हुए सभी विभागों को लंबित प्रकरणों का शीघ्र समाधान

सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिक लंबित प्रकरण वाले विभागों को विशेष कार्ययोजना बनाकर तेजी से कार्य करने को कहा गया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूर्ण, प्रगतिरत आवासों की जानकारी ली और निर्माणाधीन आवासों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने ग्राम गैंजी, भथरी, अमलीकापा, पदमपुर, खुड़िया और मोहबंधा में हाईस्कूल निर्माण के लिए स्थल चिन्हांकन करने के निर्देश दिए। इसी तरह ग्राम कुकुसदा, दशरंगपुर, डाड़गांव और अमोरा में हायर सेकेण्डरी स्कूल निर्माण के लिए स्थल चिन्हांकन करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले में एलपीजी की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए गैस सप्लाई की नियमित मॉनिटरिंग तथा कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में रसोई गैस, पेट्रोल एवं डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाएं। गैस एजेंसियों, होटलों एवं अन्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण कर जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने आयुष्मान एवं वय वंदन कार्ड निर्माण में तेजी लाते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने 'सही दवा, शुद्ध आहार, यही छत्तीसगढ़ का आधार' थीम पर आम नागरिकों को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त औषधि उपलब्ध कराने विशेष अभियान संचालन के संबंध में जानकारी ली।

न्यूज गैलरी

जंगल में जुआ खेल रहे 5 आरोपी गिरफ्तार, 57 हजार नगद जब्त

मनेन्द्रगढ़/नवप्रदेश। जिले में जुआ और सट्टा जैसी अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस ने घुटरा-सलवा के जंगलों में दबिश देकर 5 जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा है, जिनके पास से नगदी और ताश की गड्डियां बरामद की गई हैं। मुखबिर से सटीक सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक के मार्गदर्शन में कोतवाली व साइबर सेल की एक विशेष टीम गठित की गई। जुआरियों को भनक न लगे, इसके लिए पुलिस टीम ग्रामीण वेशभूषा में मुख्य मार्ग से करीब 1 किलोमीटर अंदर जंगल में पहुंची। पुलिस को अचानक सामने देख जुआरियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में संतोष कुमार साण्डिल्य (सोनवर्षा, बरबसपुर), निवेश कुमार खलखो (जोबा पारा, हर्राई), भानु सिंह गोंड (खोंगापानी), विवेक मिश्रा (सेमरिया, पोड़ी), दिलीप कुमार (सेमरी, एमसीबी) सभी आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपियों के पास से 57,000 रुपये नगद, 4 ताश की गड्डियां और बिछाने के लिए इस्तेमाल किया गया तिरपाल जप्त किया है। आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 3(2) के तहत मामला दर्ज कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। निरीक्षक विवेक पाटले ने कहा कि जिले में अवैध गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

जिला बदर किए गए दो आदतन अपराधी 6 माह तक सीमाओं में प्रवेश वर्जित

मनेन्द्रगढ़/चिरमिरी/नवप्रदेश। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। जिला दण्डाधिकारी न्यायालय ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की विभिन्न धाराओं के तहत दो आदतन अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर का आदेश जारी किया है। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार चिरमिरी निवासी राजन सिंह और मनेन्द्रगढ़ निवासी शकील अहमद उर्फ मस्सा को आगामी 6 माह के लिए जिले की सीमाओं से निष्कासित कर दिया गया है। यह आदेश 27 अप्रैल 2026 से प्रभावी होकर 26 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगा। आदेश के मुताबिक, दोनों आरोपियों को न केवल एमसीबी जिले, बल्कि उससे लगे सीमावर्ती जिलों की सीमाओं में भी प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसमें छत्तीसगढ़ के कोरिया, कोरबा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही और पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश के अनूपपुर, शहडोल, सीधी एवं सिंगरौली जिले शामिल हैं। किसी भी विशेष परिस्थिति में प्रवेश के लिए इन्हें विधिसम्मत अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि निष्कासन अवधि के दौरान संबंधित व्यक्ति जिले की सीमा में पाए जाते हैं या आदेश का उल्लंघन करते हैं, तो उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में प्रशासन के इस निर्णय को एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। स्थानीय स्तर पर पुलिस और प्रशासन की इस सक्रियता की सराहना हो रही है।

देवाड़ांड-1 के लिए केशल बने अधिमानी बोलीदार, ई-लॉटरी से हुआ फैसला

मनेन्द्रगढ़/नवप्रदेश। जिले में खनिज संसाधनों के पारदर्शी प्रबंधन की दिशा में कलेक्टर कार्यालय की खनिज शाखा ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 'छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत नियम, 2025' के तहत देवाड़ांड-1 रेत खदान के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कर ली गई है। इस पूरी प्रक्रिया में आधुनिक तकनीकी प्रणाली और निष्पक्षता को प्राथमिकता दी गई।

74 बोलीदारों के बीच रही कड़ी प्रतिस्पर्धा

देवाड़ांड-1 रेत खदान के लिए कुल 74 इच्छुक बोलीदारों ने हिस्सा लिया। तकनीकी परीक्षण के बाद 73 बोलीदारों को पात्र और 1 को अपात्र घोषित किया गया। नीलामी के दौरान एक दिलचस्प स्थिति तब बनी जब सभी 73 पात्र प्रतिभागियों ने समान एवं न्यूनतम बोली प्रस्तुत की।

इलेक्ट्रॉनिक लॉटरी से हुआ चयन

समान बोली होने की विशेष परिस्थिति में, शासन के नियमों के तहत 27 अप्रैल को इलेक्ट्रॉनिक लॉटरी का सहारा लिया गया। पूरी तरह डिजिटल और मानवीय हस्तक्षेप रहित इस प्रक्रिया में श्री केशल राम साहू को अधिमानी बोलीदार के रूप में चुना गया।

राजस्व वृद्धि और अवैध उत्खनन पर लगेगी रोक

खनिज विभाग के अनुसार, इस पारदर्शी आवंटन से शासन के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और क्षेत्र में रेत की उपलब्धता सुगम होगी। खदान का विधिवत संचालन शुरू होने से अवैध उत्खनन पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा। साथ ही, परिवहन और श्रम के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। प्रशासन द्वारा अपनाई गई इस डिजिटल नीलामी प्रक्रिया को सुशासन और संस्थाधन प्रबंधन के क्षेत्र में एक बड़ी मिसाल माना जा रहा है।

महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने सरकार प्रतिबद्ध: मोहले

भाजपा महिला मोर्चा ने जन आक्रोश महिला सम्मेलन का किया आयोजन

मुंगेली/नवप्रदेश। सम्मेलन की शुरुआत भारतमाता, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर व दीप प्रज्वलन के साथ अतिथियों द्वारा की गई। स्वागत भाषण एवं सम्मेलन की संपूर्ण जानकारी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अंजना देवी दास ने दी। उन्होंने सम्मेलन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।

विधायक पुन्नूलाल मोहले ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही महिलाओं को सम्मान और आरक्षण देने के लिए लगातार प्रयास करती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल बार-बार विभिन्न बहानों से इस पहल को रोकते रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माताओं-बहनों को अधिकार देने के लिए संकल्पित हैं। परिसीमन और आरक्षण को लेकर कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम पर उन्होंने स्पष्ट किया कि 1971 के परिसीमन के आधार पर वर्तमान लोकसभा की सीटें निर्धारित है जिसमे अब विसंगति आ गई है अब जनसंख्या के अनुपात में सभी नागरिकों को सही प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है जिसके लिए लगातार काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सभी माताएँ और बहने कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के इस कृत्य को

सभी मातृशक्ति को बताएं ऐसा आह्वान किया। प्रदेश कार्यसमिति सदस्य शैलेष पाटक ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि वह महिलाओं के साथ भेदभाव करती रही है। उन्होंने कहा कि वर्षों तक महिला आरक्षण को लंबित रखा गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर महिलाओं को सम्मान और प्रतिनिधित्व देने का कार्य किया है। महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री और प्रभारी शीलू साहू लेने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान के लिए अनेक प्रकार के योजनाओं के माध्यम से कार्य कर रही है जैसे ओ डी एफ, प्रधानमंत्री आवास, महतारी वंदन योजना इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है जबकि कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के विरोध में कार्य कर रही है इस बात का जवाब हमको अगले चुनाव में देने की बात कहा। जिला पंचायत सदस्य रजनी मानिक सोनवानी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नारी शक्ति आज संकल्प लेती है और सभी मातृशक्ति बहनों से आह्वान करती है कि अब हम अपने अधिकार लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह अधिनियम महत्वपूर्ण है और इसके लिए व्यापक जनजागरण की आवश्यकता है। सम्मेलन में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध मातृशक्ति का अपमान है। महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदारी मिलनी चाहिए और पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने अधिनियम के समर्थन में नारे लगाए और जनजागरण अभियान चलाने का संकल्प लिया। सम्मेलन में मंच संचालन दुर्गा गेंदले ने तथा आभार प्रदर्शन अंजना जायसवाल ने किया। सम्मेलन में कैलाश सिंह ठाकुर जिला महामंत्री, वरिष्ठ नेता मानिक सोनवानी सुनील पाटक जिला उपाध्यक्ष, रामशरण यादव जिला मीडिया प्रभारी, फूलवा सिंह परिहार, यशोदा यादव, रेखा सिंह, अनीता साहू, सुनीता पाटले, अंजना बंजारा, लक्ष्मी ठाकुर, रमा गोयल, साधना साहू, संगीता बैरहा, मीनाक्षी क्षत्रिय, जमुना पांडे, पूर्णिया धुरु, शबाना जबीन, राधिका जायसवाल, उषा साहू, विमल गबेल, सुनीता पाटले, कन्या सिंह आदि महिला मोर्चा जिला तथा मंडल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

शाम होते ही धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बरसे बादल

मुंगेली/नवप्रदेश। भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को आखिरकार राहत की कुछ बूंदें नसीब हुईं। बीते कई दिनों से आसमान में मंडरा रहे काले बादलों ने सोमवार शाम अचानक रुख बदला और तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। इस दौरान शहर का तापमान, जो पिछले दिनों लगभग 43 डिग्री तक पहुंच गया था, उसमें गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। दोपहर तक जहां तेज धूप और उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा था, वहीं शाम होते-होते मौसम ने करवट ली। तेज हवाओं के साथ धूलभरी आंधी चली,

जिससे कई इलाकों में दृश्यता भी प्रभावित हुई। इसके बाद शुरू हुई बारिश ने वातावरण को ठंडा कर दिया। सड़कों पर जमा धूल मिट गई और मौसम सुहावना हो गया। लोग घरों से बाहर निकलकर ठंडी हवाओं का आनंद लेते नजर आए। हालांकि, इस बदलते मौसम के साथ ही बिजली विभाग की व्यवस्था भी चरमराती दिखाई दी। जैसे ही आंधी शुरू हुई, शहर के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई। कुछ स्थानों पर घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। खासकर गर्मी से राहत के बीच अचानक बिजली कटौती ने लोगों की नाराजगी भी नजर आई।

आगर नदी की सफाई को लेकर पार्षद ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

मुंगेली/नवप्रदेश। नगर पालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 19 के युवा पार्षद ने शहर की जीवनदायिनी आगर नदी की दयनीय स्थिति को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि यह नदी वर्षों से शहर के नागरिकों की जल आवश्यकताओं एवं पर्यावरणीय संतुलन का प्रमुख आधार रही है, किंतु वर्तमान में अत्यधिक गंदगी, कचरा एवं गाद (सिल्ट) जमा होने से इसका स्वरूप गंभीर रूप से प्रभावित हो चुका है। पार्षद रोशन सोनी ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि नदी के मध्य में बना मिट्टी एवं गाद का टापू जल प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर रहा है, जिससे पानी का ठहराव बढ़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है तथा भविष्य में जल संकट एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की आशंका भी गहराती जा रही है। ज्ञापन के माध्यम से पार्षद ने मांग की है कि आगर नदी की तत्काल वैज्ञानिक एवं व्यापक स्तर पर सफाई करवाई जाए, नदी के मध्य बने गादटापू को हटाकर जल प्रवाह को सुचारू किया जाए, तथा भविष्य में ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए स्थायी निगरानी एवं संरक्षण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यह कार्य न केवल शहर की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है, बल्कि मुंगेली की जनता के स्वास्थ्य और आने वाले समय के जल संकट को देखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पार्षद ने जिला प्रशासन से इस विषय पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की अपेक्षा व्यक्त की है।

स्वगणना कार्य पूरी सावधानी, पारदर्शिता व समय-सीमा के भीतर पूरा करें: कलेक्टर

मुंगेली/नवप्रदेश। कलेक्टर कुन्दन कुमार ने जिला कलेक्टोरेट परिसर में संचालित स्वगणना कार्य का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वगणना कार्य पूरी सावधानी, पारदर्शिता एवं समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। उन्होंने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को समय-सीमा में स्वगणना कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जनगणना कार्य शासन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसे पूरी गंभीरता एवं सुचारू रूप से सम्पन्न कराएं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा कार्य को त्रुटिरहित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती निष्ठा पांडे तिवारी, जिला पंचायत सीईओ सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

खाद पर लिंकिंग का विरोध, पीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

मुंगेली/नवप्रदेश। अखिल भारतीय खाद बीज एवं कीटनाशक दवा विक्रेता संघ के आव्हान पर जिले के समस्त खाद बीज एवं कीटनाशक संघ द्वारा भी अपनी प्रतिष्ठानों को बंद कर बंद का समर्थन देते हुए अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का ज्ञापन जिलाधीश कार्यालय में तथा कृषि विभाग के उपसंचालक अधिकारी को दिया गया।

ज्ञापन में खाद पर जबरन लिंकिंग करने के साथ ही अनुपयोगी उत्पाद बेचने की बाध्यता खत्म की जाए तथा बढ़ती लागत एवं महंगाई को देखते हुए उर्वरक पर डीलर की मार्जिन को बढ़ाकर 8: किया जावे एवं ग्रामीण खुदरा विक्रेताओं के लिए पोर्टल को वैकल्पिक बनाया जावे तथा अवैध बीजों की बिक्री पर प्रभावी रोक लगावी जावें, खाद बीज एवं कीटनाशक के सील बंद पैकिंग

में नमूना फेल होने पर विक्रेताओं को अपराधी न बनाकर उसे गवाह बनाया जावे तथा कालांतर में हो चुकी दवाईयां को वापस लेने के कानून को अनिवार्य किया जावें। इसके अतिरिक्त ग्राहकों द्वारा झूठी शिकायतें करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे तथा छोटी-मोटी बातों पर कृषि विभाग द्वारा 21 दिन में स्वतः बहाली का प्रावधान किया जावे एवं प्रत्येक वर्ष पीसी जोड़ने की अनिवार्यता समाप्त की जावें। इसके अतिरिक्त दोहरी लाइसेंस प्रथा बंद हो। ज्ञापन के अंत में कहा गया है कि इन्हीं समस्याओं के निराकरण के लिए उचित पहल करें। ताकि खरीफ फसल आने के पूर्व ही हम सब निर्बाध गति से अपने प्रतिष्ठान चला सके। ज्ञापन देने वालों में मुंगेली जिले के लोरमी, पथरिया, फाटरपुर, सेतगंगा, खाम्ही सहित जिले के समस्त खाद बीज एवं कीटनाशक विक्रेता थे।

पेज 1 का शेष...

श्रमिकों के सशक्तीकरण को मिली...

श्रमिकों को केवल आर्थिक सहायता देना ही नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना भी है। इस अवसर पर श्रम मंत्री श्री लखन देवांगन भी विशेष रूप से उपस्थित थे।

66.9 लाख केश और...

केश लेकर गई है। हालांकि, इस संबंध में ईडी की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कार्रवाई के दौरान भूपेंद्र चंद्राकर से लंबी पूछताछ की भी गई। ईडी इस मामले में भारतमाला परियोजना से जुड़े वित्तीय लेनदेन और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

आतंकवाद के गढ़ अब...

खत्म करना और किसी भी तरह के राजनीतिक अपवाद को समाप्त करना जरूरी है।

वैश्विक शांति में एससीओ की भूमिका अहम

राजनाथ सिंह ने कहा कि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित करना शंघाई सहयोग संगठन की प्रमुख जिम्मेदारी है। उन्होंने संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देने और बल प्रयोग से बचने की बात कही।

वैश्विक सहमति और नई विश्व व्यवस्था पर जोर

रक्षा मंत्री ने कहा कि आज की दुनिया में सह-अस्तित्व, सहजीवन और करुणा को अराजकता, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष से ऊपर रखना होगा। उन्होंने एक ऐसी विश्व व्यवस्था की जरूरत बताई, जहां हर व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार हो और मतभेद विवाद में न बदलें।

भारत की प्रतिबद्धता दोहराई

राजनाथ सिंह ने एससीओ के उद्देश्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि पारस्परिक सम्मान, समानता और सहयोग के आधार पर यह संगठन शांति और स्थिरता का मजबूत स्तंभ बन सकता है।

चौथिया से लौट रहे परिवार...

की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। इस दर्दनाक दुर्घटना में मोंगरा सोनी (45), देवेंद्र सोनी (22) और मासूम प्रियांश (ढाई वर्ष) ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

कार में कुल छह लोग सवार थे। हादसे में तीन अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद पूरे बुधवारी काशीनगर इलाके में मातम पसरा हुआ है। खुशियों से लौट रहा परिवार कुछ ही पलों में मातम में बदल गया, और पीछे रह गई सिर्फ चीखें, सन्नाटा और गहरा दुख।

दूसरे चरण का महासंग्राम...

मतुआ समुदाय और शरणार्थियों के वोट निर्णायक हैं। भाजपा सीएए के जरिए नागरिकता का दांव खेल रही है, तो टीएमसी इसे एनआरसी का डर बताकर काउंटर कर रही है।

भावनात्मक कार्ड: भाजपा ने आरजी कर अस्पताल की घटना को मुद्दा बनाते हुए पीड़िता की मां को पानीहाटी से उम्मीदवार बनाया है, जो चुनाव को भावनात्मक मोड़ दे सकता है।

सुरक्षा की चुनौती: भारत-बांग्लादेश सीमा और नदी क्षेत्रों से जुड़े जिलों (जैसे 24 परगना) में मतदान होना है, जो सुरक्षा बलों के लिए बड़ी परीक्षा है।

इंतजार खत्म, आज...

परिणाम न आने पर निराश होने की बजाय नए अवसरों पर ध्यान दें। मंडल से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बार करीब 5.66 लाख छात्र-छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा में पंजीयन कराया था। इनमें 10वीं के 3,20,535 और 12वीं के 2,45,785 विद्यार्थी शामिल हैं। इस साल भी हाईस्कूल परीक्षा में हायर सेकेंडरी के मुकाबले ज्यादा छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे।

गुबराल बांध निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने कसी कमर

अंतागढ़/नवप्रदेश। बरसों पुरानी अब मांग पुनः उठने लगी जिसे लेकर ग्रामीणों ने कमर कस ली और गांव स्तर बैठकों का दौर शुरू हो चुका जिसका आगाज आज ग्राम कामता से हो चुकी जिसमें क्षेत्र भर के किसान एकत्रित हुए जिसमे गांव प्रमुख सरपंच शामिल हुए । इस बैठक मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में बांध का निर्माण करना था जिसे लेकर रुपरेखा तैयार की रणनीति तैयारी की है जिसमे निर्णय किया गया है आगामी समय में एक समिति बना पदाधिकारीयो भी नियुक्त करेंगे और हर एक गांव में इस सम्बन्ध में बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक स्कूल प्रांगण में पेड़ की छांव में आयोजित की गई थी। बैठक में बांध निर्माण को स्वीकृति प्रदान करने शासन प्रशासन को ज्ञापन आदि माध्यमों से अपनी मांगो को रखना वही किसानों ने आगे कहा कि अभी चरण बद्ध तरीके से शासन प्रशासन के समक्ष मांग की जाएगी अगर हमारी मांगों को अनसुना किया जाएगा तो हम मजबूर हो जाएंगे और आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे।

दैनिक नव प्रदेश

न्यायधानी बिलासपुर

जमीन विवाद में तीन लोगों की हत्या मामले में पिता-पुत्र की सजा के खिलाफ अपील खारिज

बिलासपुर/नवप्रदेश। *हाई कोर्ट ने घायल गवाह के बयान को हत्या का पुख्ता साक्ष्य मानते हुए जमीन विवाद पर तीन लोगों की हत्या करने के आरोपी पिता-पुत्र की सजा के खिलाफ पेश अपील को खारिज करते हुए विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि की है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि एक 'संबंधित' गवाह, जो एक घायल गवाह भी है, जो क्राइम की जगह पर नैचुरली मौजूद हो सकता है, उसकी गवाही को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह पीड़ित से जुड़ा है और कोर्ट को उसके बयान की भरोसेमंदता, एक जैसापन और तालमेल का आकलन करना चाहिए।*

तुमगांव थाना क्षेत्र के ग्राम जोबा में 11.09.2020 को सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच आरोपी परसराम गायकवाड़ और बुज सेन गायकवाड़ ने जमीन बंटवारे के विवाद में ओसराम गायकवाड़ के घर मे घुसकर उसके और उसकी पत्नी जागृति गायकवाड़ की आंखों में मिर्च पाउडर फेंक दिया और उन पर खंजर से हमला कर दिया। हमला होने पर ओस राम जान बचाने अपने भाई के घर मे घुस गया। आरोपियों ने उसकी पत्नी जागृति, 16 वर्षीय पुत्री टीना गायकवाड़, 9 वर्षीय पुत्र मनीष गायकवाड़ की गला काट कर हत्या कर दी। एक कमरे का दरवाजा तोड़कर पुत्री गीतांजलि गायकवाड़, ओमान गायकवाड़ व अोस राम की बुजुर्ग माँ अनारबाई गायकवाड़ को गम्भीर रूप से

घायल कर दिया। सूचना पर तुमगांव पुलिस मौके में पहुँच आरोपियों को हिरासत में लिया व घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। विवेचना उपरांत न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 459 के तहत 10 वर्ष के लिए साधारण कारावास और 500 रुपये का जुर्माना और जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर 6 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास आईपीसी की धारा 302 के साथ 34 के तहत (तीन बार) आजीवन कारावास और 500 रुपये का जुर्माना। 1000/- और जुर्माना राशि के भुगतान के अभाव में, 01 वर्ष के लिए अतिरिक्त आरआई आईपीसी की धारा 307 , 34 के तहत (चार बार) 10 वर्ष के लिए साधारण कारावास और 500/- रुपये का जुर्माना और जुर्माना राशि के भुगतान के अभाव में, 06 माह के लिए अतिरिक्त सजा सुनाई है। सजा के खिलाफ आरोपियों ने हाई कोर्ट में अपील पेश की थी। अपील में आरोपियों ने मामले में स्वतंत्र गवाह नहीं होने व घायल गवाहों के पीड़ितों से सम्बंधित होने के कारण भरोसेमंद नहीं होने की बात कही गई थी। हाई कोर्ट ने इस तर्क को खारिज किया है।

सुपारी देकर हत्या करवाने वाली महिला को आजीवन कारावास

पेंड्रा/नवप्रदेश। जिले में करीब चौदह साल पहले हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। पेंड्रारोड स्थित द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की कोर्ट ने जमीन विवाद के चलते एक युवक की सुपारी देकर हत्या कराने वाली मुख्य आरोपी महिला मीराबाई को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने महिला पर 2000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में शासन की ओर से प्रभावी पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ठाकुर ने की। दरअसल पूरा मामला सितंबर 2012 का है, जब मरवाही थाना अंतर्गत ग्राम पंडरी निवासी मीराबाई का अपने पति श्रवण सिंह के साथ मृतक संजय सिंह का जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते मीराबाई ने संजय को रास्ते से हटाने की साजिश रची और तीन लोगों को हत्या के लिए 30,000 रुपये की सुपारी दी थी। योजना के अनुसार, मीराबाई ने आरोपियों को 29,000 रुपये नगद प्रदान कर हत्या के लिए उकसाया था। जिसके बाद 8 सितंबर 2012 को आरोपियों ने संजय सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को ग्राम ऐंठी के डबरी तालाब में फेंक दिया था। वहीं पुलिस जांच में यह बात सामने आई थी कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए सेवका सिंह, बबलू उर्फ जगनारायण और भोलु उर्फ भोला गोंड को सुपारी दी गई थी।

न्यूज गैलरी

मंत्री तोखन ने जनदर्शन में समस्याओं के शीघ्र निराकरण के दिए निर्देश

बिलासपुर/नवप्रदेश। आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने अपने संसदीय क्षेत्र बिलासपुर स्थित निज कार्यालय में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में भाग लेकर क्षेत्रवासियों से सीधे संवाद किया। इस अवसर पर श्री साहू ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए नागरिकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में सभी लोग पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें, धूप में अनावश्यक बाहर निकलने से बचें तथा अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने प्रशासन को भी निर्देशित किया कि गर्मी के मद्देनजर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, जिससे आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जनदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे नागरिकों ने विभिन्न जनहित से जुड़े विषयों को मंत्री के समक्ष रखा, जिन पर उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही।

डॉ. सीवी रमन विवि हास्टल से गायब छात्र नागपुर से बरामद

बिलासपुर/नवप्रदेश। ऑनलाइन गेमिंग में सॉलिस और कई लोगो से उधारी लेकर गेम में पैसें लगाने वाले छात्र ने डर से लापता होने का प्लान बनाया। इस संबंध में अपने पिताजी को बताने से डरता था और इसी डर से प्लानिंग कर हॉस्टल से भाग गया था। पुलिस के अनुसार गुम इंसान ''तलाश अभियान'' के तहत सभी गुम इंसानो की पता तलाश हेतु उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह द्वारा निर्देशित किया गया है। 7 मार्च को सूचक राजा मिश्रा पिता हरप्रसाद मिश्रा उम्र 42 साल निवासी फिरंगीपारा कोटा थाना कोटा के द्वारा थाना उपस्थित आकर गुम इंसान रिपोर्ट कराया था कि रोहित कुमार अमरेन्द्र कुंमार उम्र 20 वर्ष निवासी महावीर कॉलोनी संगम चौक गया (बिहार), डॉ.सीवी रमन युनिवर्सिटी कोटा के छात्रावास में रह कर बी. फार्मेसी चतुर्थ सेमेस्टर की पढाई कर रहा था जो 6 मार्च के छात्रावास से गायब हो गया था जिसकी छात्रावास परिसर व उसके सहपाठियों से पुछताछ कर पता तलाश किया गया पता नही चलने पर थाना कोटा में गुम इंसान क्रमांक 29/2026 कायम कर पता तलाश में लिया गया था।

टीएल बैठक में कलेक्टर ने की समीक्षा, प्रशासनिक तैयारियों को दिया अंतिम रूप

सुशासन तिहार और जनगणना को लेकर प्रशासन तैयार, 30 तक लंबित प्रकरण निपटाने के निर्देश

बिलासपुर/नवप्रदेश। *कलेक्टर संजय अग्रवाल ने टीएल बैठक लेकर आगामी 1 मई से शुरू हो रहे सुशासन तिहार और जनगणना कार्य की तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को 30 अप्रैल तक सभी लंबित मामलों के निराकरण के निर्देश देते हुए दोनों महत्वपूर्ण अभियानों को सफल बनाने के लिए पूरी मुस्तैदी से कार्य करने को कहा।*

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मंगलवार को आयोजित टीएल बैठक में जिले में शुरू होने जा रहे दो बड़े अभियानों—सुशासन तिहार और जनगणना—की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सुशासन तिहार प्रारंभ होने से पहले सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण कर लिया जाए, ताकि शिविरों में आमजन को त्वरित राहत मिल सके। कलेक्टर ने बताया कि जिले में सुशासन तिहार के दौरान कुल 73 शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 31 शिविर ग्रामीण क्षेत्रों और 42 शिविर शहरी क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों के संचालन की जिम्मेदारी जनपद पंचायत के सीईओ तथा शहरी क्षेत्रों में निगम आयुक्त एवं संबंधित सीएमओ को सौंपी गई है।

पात्रों को किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने निर्देश

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने शेष पात्र किसानों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिले में वर्तमान में 1.02 लाख किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जबकि लगभग 25 हजार और किसानों को इससे जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा, खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए खाद और बीज की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अग्रिस्टेक पोर्टल में पंजीकृत किसानों को ही खाद उपलब्ध कराया जाएगा और 1 मई से सॉफ्टवेयर शुरू होने पर वितरण प्रक्रिया प्रारंभ होगी। बैठक में आगामी 9 मई को आयोजित होने वाली लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।

पानी पर फोकस: 749 हैंडपंप सुधार 154 गांव में रिचार्ज प्लान

सुशासन तिहार एवं चालू गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जिला प्रशासन के सहयोग से जिले में विशेष संधारण अभियान चलाकर पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में पिछले एक माह के दौरान चलाए गए इस अभियान के तहत खराब पड़े 749 हैंडपंपों का सफलतापूर्वक सुधार किया गया। इससे ग्रामीणों को काफी राहत मिली है। अभियान के दौरान जल उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से 1335 मीटर राइजर पाइप बढ़ाए गए तथा 732 मीटर पाइपों का प्रतिस्थापन किया गया है। वर्तमान में जिले के 668 ग्रामों में कुल 9250 हैंडपंप स्थापित हैं, जिनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। गिरते भूजल स्तर को ध्यान में रखते हुए जिले में पेयजल परिरक्षण अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही, पंचायतों द्वारा कराए जाने वाले बोरिंग कार्यों में तकनीकी स्वीकृति के दौरान इंजेक्शन वेल को अनिवार्य किया गया है, जिससे भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा मिल सके। भूजल संवर्धन के तहत जिले के सभी चारों विकासखंडों में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 154 ग्रामों में इंजेक्शन वेल सहित स्रोत रिश्चरता के कार्य प्रस्तावित किए गए हैं, जो दीर्घकालीन जल उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होंगे। जिला प्रशासन द्वारा पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं भूजल स्तर के संरक्षण के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे आमजन को गर्मी के मौसम में पेयजल संकट का सामना न करना पड़े।

सर्पदंश पीड़ित मासूम को शिशु भवन अस्पताल से मिला नया जीवन

बिलासपुर/नवप्रदेश। सक्ती ग्राम जामपाली पोस्ट नदौरखुर्द निवासी पिता प्यारेलाल बंजारे माता सोनम बंजारे अपनी पुत्री दो वर्षीय वृतिका बंजारे को उसके परिजन लगभग टूट चुकी उम्मीदों के साथ श्री शिशु भवन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। बच्ची अचेत थी आंखें बंद, शरीर निस्पंद, और मुंह से झाग निकल रहा था। वह खुद से सांस भी नहीं ले पा रही थी। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी उससे दूर होती जा रही हो। माता-पिता की आंखों में डर था, बेबसी थी और कहीं न कहीं अपनी बच्ची को खो देने का भय साफ झलक रहा था। ऐसे नाजुक समय में डॉ. श्रीकांत गिरी और उनकी समर्पित टीम ने बिना एक पल गंवाए मोर्चा संभाला। तुरंत बच्ची को वेंटिलेटर पर लिया गया, श्वास नली में पाइप डालकर उसकी सांसों को थामने की कोशिश शुरू हुई। स्थिति इतनी गंभीर थी कि हर सेकंड किसी परीक्षा से कम नहीं था। परिजनों को भी यह नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या है लेकिन डॉक्टरों ने हार नहीं मानी। लक्षणों की गहराई से जांच कर उन्होंने अंदाजा लगाया कि यह मामला सर्पदंश का हो सकता है। उसी विश्वास और अनुभव के साथ उपचार शुरू किया गया। तीन दिन तीन लंबी रातें हर पल उम्मीद और चिंता के बीच झूलता रहा। डॉ. श्रीकांत गिरी और उनकी टीम ने दिन-रात एक कर दिए। उनकी मेहनत, लगन और सेवा भावना ने आखिरकार चमत्कार कर दिखाया। तीसरे दिन वर्तिका ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोलीं। वो पल सिर्फ एक मेडिकल सफलता नहीं था वो एक परिवार के लिए टूटी उम्मीदों का फिर से जिंदा होना था। इसके बाद बच्ची को वेंटिलेटर से हटाकर ऑक्सीजन सपोर्ट पर लाया गया, और फिर धीरे-धीरे उसने खुद बैठना शुरू कर दिया।

पुश्तैनी जमीन पर बाउंड्रीवाल निर्माण में बाधा पीड़ित परिवार ने लगाई न्याय की गुहार

बिलासपुर/नवप्रदेश। *शहर के सरकंडा क्षेत्र में पुश्तैनी निजी भूमि पर बाउंड्रीवाल निर्माण को लेकर खड़े किए जा रहे विवाद से परेशान एक परिवार ने अब खुलकर सामने आते हुए प्रेसवार्ता के माध्यम से शासन-प्रशासन से न्याय की मांग की है। परिवार का आरोप है कि उनकी वैध जमीन पर बेवजह आपत्ति जताकर न केवल निर्माण कार्य में बाधा डाली जा रही है, बल्कि भ्रामक शिकायतों और अफवाहों के जरिए उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा है।*

बिलासपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेसवार्ता में अजय सोमावार और किशोर सोमावार अपने परिजनों के साथ उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि सरकंडा स्थित मुक्तिधाम के पीछे कपिल नगर क्षेत्र में उनकी लगभग 60 डिसमिल पुश्तैनी भूमि वर्ष 1962 से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, जिसमें वर्तमान में 8 खातेदार हैं.. परिवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि समीप स्थित कोटवारी भूमि पर कब्जा जमाए बैठे मनू मानिकपुरी द्वारा उनकी निजी जमीन पर बाउंड्रीवाल निर्माण का लगातार विरोध किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न माध्यमों से झूठी शिकायतें कर प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अजय सोमावार ने कहा कि, इन निराधार आरोपों और फैलाए जा रहे भ्रम के कारण पूरा परिवार लंबे समय से मानसिक तनाव में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अपनी वैध निजी भूमि पर नियमानुसार बाउंड्रीवाल का निर्माण करना चाहते हैं और इसके लिए प्रशासन से अनुमति की अपेक्षा रखते हैं.. परिवार ने यह भी बताया कि इस मामले में नगर निगम और कलेक्टर कार्यालय में पूर्व में लिखित शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में उन्होंने मीडिया के माध्यम से प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि उन्हें न्याय मिल सके।

तालाब में मछली पालन का ग्रामीणों ने किया विरोध

मछुआरा समिति पर जल दोहन का आरोप, कलेक्टर से पट्टा निरस्त करने की मांग

बिलासपुर/नवप्रदेश। *जिले के मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम चौंहा में भीषण गर्मी के बीच जल संकट ने अब गंभीर विवाद का रूप ले लिया है। गांव के जीवनदायिनी माने जाने वाले बांधा तालाब को लेकर ग्रामीणों और गंगा मछुआरा समिति के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि समिति ने तालाब का पट्टा लेकर मछली पालन के नाम पर पानी का अंधाधुंध दोहन किया, जिससे आज पूरा गांव बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहा है।*

ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि वर्ष 2009-2010 में लगभग 2 करोड़ 65 लाख रुपये की लागत से इस तालाब का निर्माण किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के भूजल स्तर को बनाए रखना और गांव के कुओं व हैंडपंपों में सालभर पानी उपलब्ध कराना था। शुरुआती वर्षों में तालाब ने अपनी उपयोगिता भी साबित की, लेकिन अब वही तालाब गांव के लिए संकट का कारण बन गया है। आरोप है कि गंगा मछुआरा समिति ने पट्टा मिलने के बाद मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार पानी की निकासी की, जिससे तालाब का जलस्तर तेजी से गिर गया। हालात यह हैं कि तालाब अब सूखने की कगार पर पहुंच चुका है और इसका सीधा असर गांव के अन्य जलस्रोतों पर पड़ा है। कुएं और हैंडपंप, जो पहले सालभर चलते थे, अब जवाब देने लगे हैं। जलस्तर में आई इस गिरावट ने पूरे गांव को पेयजल संकट में धकेल दिया है। महिलाएं और बच्चे दूर-दराज से पानी लाने को मजबूर हैं, जिससे दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि मछली के लिए पानी बचाया जा रहा है, लेकिन इंसानों के पीने के लिए पानी खत्म हो रहा है।

खेल का विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका: श्रीवास्तव

बिलासपुर/नवप्रदेश। *आधारशिला विद्या मंदिर सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल नेशनल गेम्स में उत्साहपूर्वक भाग लेकर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। यह पांच दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता सैनिक स्कूल अंबिकापुर द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित एवं संचालित की गई, जिसमें ग्रुप 'एफ' के विभिन्न प्रतिष्ठित विद्यालयों की टीमों ने भाग लिया।*

इस प्रतियोगिता में सैनिक स्कूल कोरूकोंडो, सैनिक स्कूल संबलपुर, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर तथा एलायंस पब्लिक स्कूल बेमेतरा सहित अन्य विद्यालयों के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पूरे आयोजन के दौरान खिलाड़ियों ने अनुशासन, टीम भावना और खेल कौशल का उत्कृष्ट परिचय दिया। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में ब्रिगेडियर टी. एस. बावा उपस्थित रहे। उन्होंने प्रतियोगिता के समापन अवसर पर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेलों के महत्व, अनुशासन और समर्पण पर प्रेरणादायक विचार व्यक्त किए तथा इंट्रा ग्रुप 'एफ' फुटबॉल टूर्नामेंट की क्लोजिंग सेरेमनी की औपचारिक घोषणा की। सैनिक स्कूल अंबिकापुर द्वारा किए गए उत्कृष्ट आयोजन एवं सशक्त संचालन ने इस प्रतियोगिता को अत्यंत सफल बनाया। पूरे कार्यक्रम का संचालन सुव्यवस्थित, अनुशासित और प्रेरणादायक रहा।

MUNICIPAL COUNCIL SAKTI, DISTRICT- SAKTI (C.G.)

E-Procurement Tender Notice (2nd-Call)

Main Portal: https://eproc.cgstate.gov.in

UDD Portal: https://uad.cg.gov.in

NIT NO/74 /PWD/NPP/2026 **Sakti, Dated 28.04.2026**

Online bids In three envelop system are invited for the following construction works/ up to: 14.05.2026 at 17:30 PM hours. (IST) on wards.

S. No	System Tender No	Name Of Work	Probable Amount of contract (Lacs)
01	189877	वार्ड क्र. 07/08 दर्री तालाब में टो वाल निर्माण कार्य	13.98
02	189874	वार्ड क्र. 15 देवी लाल आहवान घर से पी. डब्ल्यू.डी. से मेन रोड तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य	10.31

The details can be viewed and downloaded online directly from the Government of Chhattisgarh e-proc Portal https://eproc.cgstate.gov.in on Sub Portal of Urban Administration and development Department. https://eproc.cgstate.gov.in from (Start Time) Date 28.04.2026 at 17.30 PM (IST) onwards.

For more details on the tender and biding process please visit the above mentioned portal.

CHIEF MUNICIPAL OFFICER
MUNICIPAL COUNCIL SAKTI (C.G.)

कार्यालय कार्यपालन अधिवंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग जशपुर, जिला - जशपुर (छत्तीसगढ़)

Phone: 9424242409 E-Mail ID: ee-res.jashpur@nic.in

निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक / 103/वलेलि / ग्रा.यां. से./2026-27 जशपुर, दिनांक 24/04/2026

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ में एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत "बी" एवं उच्च श्रेणी में पंजीकृत विद्युत ठेकेदारों से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु प्रतिशत दर पर ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है -

क्र.	ऑनलाईन निविदा क्रमांक	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रूपए लाख में)
1	2	3	4
1	189749	Zonal tender for Electrification work (Different Types of Works But each work not exceeding Cost. Of 10.00 lakh) at sub division **Bagicha,** Dist.- Jashpur (C.G.)	40.00
2	189751	----------//------- at sub division **Duldula,** Dist.- Jashpur (C.G.)	40.00
3	189752	----------//------- at sub division **Farsabahar,** Dist.- Jashpur (C.G.)	40.00
4	189753	----------//------- at sub division **Jashpur,** Dist.- Jashpur (C.G.)	40.00
5	189754	----------//------- at sub division **Kansabel,** Dist.- Jashpur (C.G.)	40.00
6	189755	----------//------- at sub division **Kunkuri,** Dist.- Jashpur (C.G.)	40.00
7	189758	----------//------- at sub division **Manora,** Dist.- Jashpur (C.G.)	40.00
8	189760	----------//------- at sub division **Pathalgaon,** Dist.- Jashpur (C.G.)	40.00
		Total	320.00

उपरोक्त निर्माण कार्य की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी दिनांक **27.04.2026** से कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर एवं विभागीय वेबसाईट **https://eproc.cgstate.gov.in/** से प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक निविदा हेतु निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि दिनांक **11.05.2026** अपराह्न 17:30 बजे तक एवं अमानत राशि सत्यनिष्ठा राशि एवं तकनीकी दस्तावेज स्पीड पोस्ट से दिनांक **13.05.2026** को अपराह्न 17:30 बजे तक पहुंचना अनिवार्य है।

कार्यपालन अभियंता,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
संभाग, जिला- जशपुर

जी- 262700406/5

Chhattisgarh
Business Made
Easy

छत्तीसगढ़
बेहतर कल के लिए औद्योगिक विकास
नए युग के उद्योग, बढ़ता निवेश और रोजगार - आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़

अब तक **₹7.83 लाख करोड़** के निवेश प्रस्ताव प्राप्त

1.5 लाख से अधिक संभावित रोजगार

50% परियोजनाएँ विशेष सेक्टर से संबंधित

उद्योगों में बढ़ता विविधीकरण

- नवा रायपुर में **भारत का पहला** एआई डेटा सेंटर पार्क
- मध्य भारत का **सबसे बड़ा फार्मा पार्क**
- नवा रायपुर में राज्य का पहला **₹18,000+ करोड़** का **सेमीकंडक्टर प्लांट**
- **भारत के अग्रणी पेट फूड ब्रांड** का प्रमुख उत्पादन केंद्र
- 70 वर्ष पुराने राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान द्वारा स्थापित एक प्रमुख **मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल**

#CGBusinessEasy

Invest Chhattisgarh

"छत्तीसगढ़ की पहचान अब केवल यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षित भविष्य की दिशा में बढ़ते कदम, कल्याणकारी परियोजनाएँ, नए रोजगार के अवसर और नए दौर की आवश्यकताओं के अनुरूप मजबूत होती अर्थव्यवस्था भी इसकी पहचान बन रही है।"
—विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

S - 47608/1

ईरान युद्ध के बीच पहली बार रुएलएनजी टैंकर ने पार किया होर्मुज

फरवरी के अंत में अमेरिका-ईरान जंग शुरू होने के बाद से बंद हुआ होर्मुज स्ट्रेट अब भी लगभग बंद ही है. इस बीच ईरान ने मित्र देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, के कुछ जहाजों को होर्मुज पार करने की इजाजत दी है. लेकिन अब भी सैकड़ों की संख्या में जहाज होर्मुज पार करने के इंतजार में पानी में खड़े हैं। होर्मुज से कुछ तेल और एलपीजी के टैंकर तो पार हुए हैं लेकिन अब तक एक भी एलएनजी (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) टैंकर होर्मुज पार नहीं कर पाया है. लेकिन अब खबर है कि एक एलएनजी टैंकर ने होर्मुज पार कर लिया है और वो अब भारत के पास दिख रहा है। जहाज ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि यूएई की एडीएनओसी की ओर से मैनेज किए जाने वाले एक एलएनजी टैंकर ने होर्मुज स्ट्रेट पार कर लिया है और फिलहाल भारत के पास दिखाई दे रहा है।

पुष्टि होती है, तो 28 फरवरी को ईरान युद्ध शुरू होने के बाद यह पहला भरा हुआ एलएनजी टैंकर होगा जिसने होर्मुज पार किया है। 1,36,357 घन मीटर क्षमता वाला यह टैंकर एडीएनओसी लॉजिस्टिक्स एंड सर्विसेज की ओर से ऑपरेट होता है. इसे आखिरी बार 30 मार्च को खाड़ी क्षेत्र में देखा गया था। ICIS LNG Edge, मरीनट्रैफिक और LSEG के आंकड़ों के अनुसार, यह अब भारत के पश्चिमी तट के पास दिखाई दिया है। इससे संकेत मिलता है कि जहाज ने होर्मुज पार करने के लिए एक तरीका अपनाया और अपना सिग्नल बंद कर लिया जिससे इसके बारे में पता लगाना कुछ समय के लिए मुश्किल हो गया था। अब जबकि इसने गायब रहते हुए होर्मुज पार कर लिया है, तब जाकर अपना सिग्नल ऑन किया जिससे इसके होर्मुज पार करने की जानकारी बाहर आई है।

ईरान-रूस रणनीतिक साझेदारी की गहराई दर्शाती हैः अराघची

तेहरान(वार्ता)। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रूस के साथ ईरान की रणनीतिक साझेदारी की बढ़ती गहराई को रेखांकित करते हुए कहा कि ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले के बाद क्षेत्रीय उथल-पुथल ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती को उजागर किया है। अराघची ने सेंट पीटर्सबर्ग में उच्चस्तरीय बैठकों के बाद कहा कि क्षेत्र बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है और ऐसे समय में रूस के साथ सर्वोच्च स्तर पर संवाद महत्वपूर्ण है।

कुख्यात ड्रग तस्कर को वापस लाने में मिली बड़ी सफलता

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह अमित शाह ने कहा कि नार्को सिंडिकेट के खिलाफमोदी सरकार की 'ज़ीरो टॉलरेंस' नीति के अनुरूप, एनसीबी ने आज तुर्की से कुख्यात ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को वापस लाने में एक बड़ी सफलता हासिल की है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार की नार्को सिंडिकेट के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एनसीबी ने आज तुर्की से कुख्यात ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को वापस लाने में एक बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के ड्रग कार्टेल को पूरी तरह से खत्म करने के मिशन के तहत, हमारी नार्कोटिक्सरोधी एजेंसियों ने वैश्विक एजेंसियों के एक मजबूत नेटवर्क के ज़रिए सीमाओं के पार भी अपनी पकड़ बना ली है। शाह ने कहा कि ड्रग सरगना कहीं भी छिप जाएं, अब उनके लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है।

पूर्वोत्तर का स्वर्ग सिक्किम, इसके विकास को बाधित करती रही कांग्रेस : पीएम

गंगटोक/ए.। अपनी सिक्किम यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने मंगलवार को कांग्रेस और विपक्षी दलों पर पूर्वोत्तर के इस राज्य के विकास में अड़चन पैदा करने का आरोप लगाया। सिक्किम की स्थापना 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सिक्किम एवं पूर्वोत्तर को भारत का 'अस्थलाक्ष्मी' बताया और केंद्र सरकार की 'एक्ट इस्ट एवं एक्ट फैक्ट' नीति पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

विकास परियोजनाओं की शुरुआत की

प्रधानमंत्री ने सिक्किम राज्य की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के समापन कार्यक्रम में भाग लेते हुए मंगलवार को 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। अधिकारियों ने बताया कि ये परियोजनाएं अवसंरचना, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बिजली, शहरी विकास, पर्यावरण, पर्यटन और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य सिक्किम में समग्र और समावेशी विकास को गति देना है। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह दौरा सिक्किम के राज्य बनने के 50 साल में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और यह हिमालयी राज्य के तेज और सतत विकास के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

'एक भारत श्रेष्ठ भारत' का प्रतीक है सिक्किम

पीएम ने आगे कहा कि सिक्किम के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बागडोगरा से एक्सप्रेसवे बनाने और गंगटोक में रिंग रोड का निर्माण करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है ताकि पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो सके। प्रधानमंत्री मोदी। पूर्वी भारत का स्वर्ग है सिक्किम, प्रकृति प्रेमी पर्यटकों को राज्य के 'ऑकिडेरियम' का दौरा करना चाहिए। सिक्किम ऐसे समय में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' का प्रतीक है, जब देश को धर्म और राजनीति के आधार पर बांटने के प्रयास किए जा रहे हैं। सिक्किम की सड़कों की सफाई और वायु गुणवत्ता यह दर्शाती है कि यहां के लोग प्रकृति संरक्षण के अगुआ हैं।

सिक्किम के विकास को बाधित करती रही कांग्रेस : पीएम

रैली में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि 'सिक्किम के लिए भाजपा की सरकार जो अब कर रही है उसे बहुत पहले कर लिया जाना चाहिए था लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने इस राज्य के विकास में लागातार बाधा खड़ी करती रहीं।' पीएम ने उदाहरण देते हुए कहा कि सिवोक-रागपो रेलवे लाइन की मंजूरी 2008-09 में मिली लेकिन बावजूद इसके जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। केंद्र में भाजपा की सरकार जब आई तो सिक्किम में विकास कार्यों ने गति पकड़ी। सिक्किम में पहली बार रेल पहुंचने वाली है। इससे पहले पीएम ने 4000 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

सत्ता में बैठे लोगों की प्रतिबद्धता के कारण हुआ राम मंदिर निर्माण

नई दिल्ली/ए.। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सत्ता में बैठे लोगों की प्रतिबद्धता और देश के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से संभव हुआ तथा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। आरएसएस की एक विज्ञप्ति के अनुसार वह रेशिमबाग स्थित डॉ. हेडगेवार स्मारक समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन व्यक्तियों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे, जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में मंदिर का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण भगवान राम की इच्छा से हुआ। भागवत ने इसकी तुलना भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने से करते हुए कहा कि ऐसे कार्य तभी संभव होते हैं, जब सभी का योगदान हो। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ली, तो लंदन के द गार्डियन अखबार ने लिखा कि इस दिन भारत ने वास्तव में ब्रिटिश शासन

को अलविदा कहा। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रतिबद्ध नेतृत्व के बिना राम मंदिर का निर्माण संभव था। भागवत ने यह भी कहा कि एक समय हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र कहना उपहास का विषय हुआ करता था। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। राम मंदिर बनने तक लोग इस ढांचे पर हंसते थे। आज वही लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुओं की भूमि है। उन्होंने कहा कि कई लोग आरएसएस से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने को कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जो बात पहले से ही सच है उसे घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भागवत ने जोर देकर कहा, कई लोग आरएसएस से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने को कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जो पहले से ही सत्य है उसे घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

नोएडा में 84 वर्षीय बुजुर्ग से 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर 85 लाख की ठगी

नोएडा/ए.। नोएडा के सेक्टर-51 स्थित केंद्रीय विहार में रहने वाले 84 वर्षीय बुजुर्ग के साथ साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। खुद को साइबर सेल और सीबीआई अधिकारी बताने वाले ठगों ने 'डिजिटल अरेस्ट' का डर दिखाकर उनसे करीब 85 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित धीरेंद्र की शिकायत के मुताबिक, उन्हें एक कॉल आया जिसमें कॉलर ने खुद को बेंगलुरु साइबर सेल का अधिकारी बताया। उसने दावा किया कि उनके आधार कार्ड का दुरुपयोग कर अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाला मोबाइल खरीदा गया है। इसके बाद कॉल को अन्य लोगों से जोड़ दिया गया, जिन्होंने खुद को पुलिस और

सीबीआई अधिकारी बताते हुए मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी दी। 7 से 22 अप्रैल के बीच ठगों ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए लगातार 'पूछताछ' की। उन्होंने खुद को सुप्रीम कोर्ट और जांच एजेंसियों से जुड़ा बताकर पीड़ित को मानसिक दबाव में रखा। गिरफ्तारी और संपत्ति जब्ती का डर दिखाते हुए उनसे बैंक खातों की जानकारी हासिल की गई और पैसे ट्रांसफर करवाए गए। ठगों के झांसे में आकर पीड़ित ने 13 अप्रैल को 55 लाख रुपये अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। ठगों ने इसे मनी ट्रेल वेरिफिकेशन का हिस्सा बताते हुए भरोसा दिलाया कि जांच पूरी होने के बाद पूरी रकम वापस कर दी जाएगी। 22 अप्रैल को ठगों ने एक फर्जी सीबीआई लेटर दिखाकर 1.24 करोड़ रुपये और जमा करने का दबाव बनाया, लेकिन इस बार पीड़ित ने मना कर दिया। इसके बाद ठगों ने संपर्क तोड़ दिया, जिससे पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। घटना के बाद पीड़ित ने 25 अप्रैल को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई और सेक्टर-36 स्थित साइबर क्राइम थाने में भी मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

जामिया मिलिया इस्लामिया में आरएसएस शताब्दी समारोह को रद्द करने की मांग

नई दिल्ली/ए.। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्विद्यालय में इंजीनियरिंग फैकेल्टी RSS के हो रहे प्रोग्राम को लेकर लेफ्ट छात्रों ने परिसर में प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि आरएसएस का प्रोग्राम जामिया के इंजीनियरिंग फैकेल्टी में हो रहा था। लेफ्ट विंग से जुड़े छात्रों ने ढपली बजाकर नारेबाजी की। हालांकि नारेबाजी को तुरंत प्रशासन ने बंद करवा दिया। फिलहाल शांति बनी हुई है। सामान्य तौर पर छात्रों का आना जाना जारी है। एक छात्र विवेक ने कहा कि RSS को यहां कार्यक्रम के लिए जगह मिली इसलिए प्रदर्शन हुआ। RSS को जगह मिली, लेकिन Aisa को जगह नहीं मिलती है इस बात की नाराजगी है।

एसएफआई इकाई ने विरोध किया

जामिया मिलिया इस्लामिया की SFI इकाई ने आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम की अनुमति रद्द करने की मांग की थी। एसएफआई का दावा है कि यह कार्यक्रम अल्पसंख्यक छात्रों की गरिमा और सुरक्षा पर सीधा हमला है। इकाई ने एक बयान में कहा, एसएफआई जेएमआई इकाई आरएसएस से संबद्ध संगठन 'युवा' को 28 अप्रैल को आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हमारे परिसर में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देने और सुविधा प्रदान करने के लिए प्रशासन की कड़ी निंदा करती है।

'सत्याग्रह' की बात करने के बाद राजघाट पहुंचे केजरीवाल-मनिष सिसोदिया

नई दिल्ली/ए.। आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने न्यायपालिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत की कार्यवाही का बहिष्कार करते हुए 'सत्याग्रह' का ऐलान किया है। इसी सिलसिले में मंगलवार दोपहर 12 बजे दोनों नेता राजघाट पहुंचे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को अलग-अलग पत्र लिखकर यह स्पष्ट कर दिया है कि वे अब इस मामले में न तो खुद

पेश होंगे और न ही उनका कोई वकील पैरवी करेगा। केजरीवाल ने पत्र में लिखा कि संबंधित अदालत से उन्हें 'न्याय मिलने की उम्मीद पूरी तरह टूट चुकी है', इसलिए वे अपनी अंतरात्मा की आवाज पर गांधीजी के दिखाए 'सत्याग्रह' के मार्ग पर चल रहे हैं। मंगलवार को सिसोदिया ने अपने पत्र में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके पास सत्याग्रह के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने अदालत की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कार्यवाही से दूरी बना ली है। अपनी रणनीति को धार देने के लिए केजरीवाल और सिसोदिया के साथ दिल्ली की वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी भी राजघाट पहुंचीं। नेताओं ने बापू की समाधि पर नमन किया और मौन धारण किया। इस बीच केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आज हम जो आजाद घूम रहे हैं तो उसका कारण केवल हमारी न्याय प्रणाली है। कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिस कारण हमें यह सत्याग्रह करना पड़ रहा है। हमने सभी बातें उस चिट्ठी में लिखी हैं जो कि हमने जज साहिबा को भेजी है। यह बेहद संवेदनशील मामला है।

श्रम कानून के साथ 1 मई से बदल रहे हैं गैस सिलेंडर बुकिंग से लेकर यूपीआई पेमेंट सहित कई नियम

नई दिल्ली/ए.। मई का महीना नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़े बदलावों की दस्तक दे रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार 1 मई से चार नए श्रम कानून लागू करने जा रही है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर, पीएफ योगदान और काम के घंटों में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा—माना जा रहा है कि आगे चलकर ये नियम पूरे देश में प्रभावी हो सकते हैं। इसके साथ ही, 1 मई 2026 से बैंकिंग सेवाओं, रसोई गैस की कीमतों और डिजिटल पेमेंट से जुड़े नियमों में भी महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। इन अपडेट्स के प्रति जागरूक रहकर आप न केवल वित्तीय नुकसान से बच सकते हैं, बल्कि अपनी भविष्य की प्लानिंग भी बेहतर ढंग से कर पाएंगे।

1 मई से आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन पहले से कहीं अधिक सुरक्षित होने वाले हैं। अब '2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन' (2FA) को और भी सख्ती से लागू किया जा रहा है। इसका मतलब है कि अब यूपीआई या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते समय आपको बार-बार ओटीपी, पिन या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। इसके अलावा, यदि आप ब्लू के जरिए, ब्लरूसे बिना कार्ड के पैसा निकालते हैं, तो यह आपकी प्री पोर्टफोलियो को अपने आप एडजस्ट करेंगे। ट्रांजैक्शन लिमिट में गिना जाएगा। लिमिट खत्म होने पर आपको प्रति ट्रांजैक्शन 17 से ?21 तक का अतिरिक्त चार्ज देना होगा।

2. सरकार अब काले धन पर नकेल कसने के लिए बड़े कैश ट्रांजैक्शन की निगरानी बढ़ा रही है। नए नियम के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से अधिक का नकद जमा या निकासी करता है, तो उसके लिए पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा। पहले यह ट्रैकिंग दैनिक आधार पर होती थी, लेकिन अब पूरे साल के रिकॉर्ड को आधार बनाया जाएगा।

3. म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए भी बड़ी खबर है। पुराने 'सॉल्यूशन-ओरिएंटेड' प्लान्स (जैसे रिटायरमेंट या चाइल्ड प्लान) को हटाकर अब 'लाइफ साइकिल फंड्स' लाए जा रहे हैं। ये फंड आपकी उम्र के हिसाब से अपने आप एडजस्ट करेंगे।

चीन से हारकर भारतीय महिला बैडमिंटन टीम उबेर कप से बाहर, अब पुरुष टीम से उम्मीदें

नई दिल्ली/ए.। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु मजबूत स्थिति में होने का फायदा नहीं उठा पाई जबकि अन्य खिलाड़ियों ने भी महत्वपूर्ण मौकों पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जिससे भारत उबेर कप में चीन से 0-5 से हारकर इस बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गया। भारतीय महिला टीम ने मेजबान डेनमार्क से 2-3 की हार के साथ शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद उसने यूक्रेन पर 4-1 से जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीद बनाए रखी थी। उबेर कप में 16 बार के चैंपियन चीन से भारत को पिछले तीनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। सिंधु ने भारत की तरफ से शुरुआत की जबकि उनति हुडा और तन्वी शर्मा की जगह अन्य दो एकल मुकाबलों के लिए ईशारानी बरुआ और दीविका सिहग को टीम में शामिल किया गया। सिंधु निर्णायक सेट में 18-12 से आगे थी लेकिन आखिर में वह विश्व की दूसरे नंबर की खिलाड़ी वांग झियी से 16-21, 21-19, 19-21 से हार गईं। इससे चीन ने सोमवार को रुए ए के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में 1-0 की बढ़त

हासिल कर ली। सिंधु ने बाद में कहा, "यह एक अच्छा मैच था। अगर मैं जीत हासिल करने में सफल रहती तो और भी अच्छा होता। मुझे मौके मिले, लेकिन ऐसा नहीं था कि कुछ अंक आसान थे। प्रत्येक अंक के लिए कड़ा मुकाबला हुआ। हम वास्तव में प्रत्येक अंक के लिए बहुत संघर्ष कर रहे थे।" प्रिया कोंजेंगबम और श्रुति मिश्रा पहले युगल मुकाबले में विश्व की नंबर एक जोड़ी लियू शेंग शू और टैन निंग के सामने नहीं टिक पाई और 11-21, 8-21 से हार गईं। इशारानी बरुआ ने तोक्यो ओलंपिक चैंपियन चेन युफेई के सामने कड़ी चुनौती पेश की लेकिन विश्व में 38वें नंबर की भारतीय खिलाड़ी ने पहले गेम में 20-19 पर एक आसान मौका गंवा दिया।

टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट में होने वाला था हमला! गिरफ्तार हुए शख्स की हुई पेशी

मुंबई। 2024 में ऑस्ट्रिया की राजधानी में टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट में जिहादी हमले की योजना बनाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। 21 साल के ऑस्ट्रियाई युवक को 2024 में सीआईए से मिली सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। युवक पर वियना के दक्षिण में स्थित एक अदालत में पेश किया गया, जहां उस पर आतंकवाद और अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। बेरान ए पर एक अन्य 21 साल के युवक अर्दा के के साथ मुकदमा चलाया गया, जिस पर उसके साथ इस्लामिक स्टेट के एक गुट का हिस्सा होने का आरोप है। उन पर मक्का, इस्तांबुल और दुबई में अन्य हमलों की योजना बनाने का आरोप है। इस आशंका और युवक की गिरफ्तारी के बाद वियना के अर्न्स्ट हैप्पल स्टेडियम में टेलर स्विफ्ट के तीनों हाउसफुल शो रद्द कर दिए गए थे। कुल मिलाकर 195,000 से अधिक लोगों के आने की

उम्मीद थी। हजारों निराश प्रशंसक वियना की सड़कों पर घूमते हुए, गीत गाते हुए और टेलर स्विफ्ट-थीम वाले फ्रेंडशिप ब्रेसलेट का आदान-प्रदान करते हुए नजर आए थे।

मुकदमे की सुनवाई से पहले बेरान ए की वकील अन्ना मेयर ने कहा कि वो आंशिक रूप से दोषी स्वीकार करेगा। वियना के आयोजकों ने उस पर एक आतंकवादी संगठन का सदस्य होने और टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट पर हमले की तैयारी और योजना बनाने का आरोप लगाया है। उस पर जिहादी समूह इस्लामिक स्टेट के प्रति वफादार होने और उसके लिए ऑनलाइन प्रचार करने साथ ही विस्फोटक बनाने और अवैध रूप से हथियार खरीदने का प्रयास करने का भी आरोप है।

विधानसभा में हर साल गूंजता है अवैध प्लाटिंग का मुद्दा

छत्तीसगढ़ विधानसभा में अवैध प्लाटिंग का मुद्दा हर साल गूंजता है, जिसमें मुख्य रूप से रायपुर, धमतरी और कांकेर जिलों में कृषि भूमि को बिना डायवर्सन के प्लॉटिंग कर बेचने का मामला सामने आता है। आरोप है कि 50,000 एकड़ से अधिक कृषि भूमि पर अवैध कब्जे और कॉलोनी बसाई जा रही हैं। विपक्ष ने अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही न होने को लेकर सदन से वॉकआउट किया था। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने लगातार कार्रवाई की बात कही थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। सबसे आपत्तिजनक बात तो यह है कि अवैध प्लाटिंग सोशल मीडिया के जरिए भी फल-फूल रहा है।

अवैध प्लाटिंग से होने वाली प्रमुख परेशानियां

- **गाढ़ी कमाई पर जोखिम:** अवैध प्लाटिंग या बिना सरकारी अनुमति वाली कॉलोनियों में जमीन खरीदना आपकी गाढ़ी कमाई को जोखिम में डाल सकता है।
- **नामांतरण में रुकावट:** अवैध प्लॉट की रजिस्ट्री होने के बावजूद नामांतरण नहीं हो पाता है, जिससे जमीन का मालिकाना हक सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होता।
- **अवैध निर्माण का डर:** संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कॉलोनियों में बने मकानों को सील या ध्वस्त किया जा सकता है।
- **बुनियादी सुविधाओं का अभाव:** ऐसी कॉलोनियों में पक्की सड़कें, सीवर, पेयजल, बिजली और पार्क जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती।
- **कानूनी उलझनें:** अवैध प्लाटिंग में शामिल होने पर आप भी कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकते हैं।
- **निवेश का जोखिम:** भूमाफिया या प्रॉपर्टी डीलर प्लॉट बेचकर गायब हो सकते हैं, जिससे खरीदार फंस जाते हैं।

नक्शा फेल, सिस्टम सेल, अवैध प्लाटिंग में खेल

रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के हर जिलों में अवैध प्लाटिंग का खेल अब खुला धंधा बन चुका है, जहां नियम-कायदों को खुलेआम ठेंगा दिखाकर जमीन के सौदागर मोटी कमाई कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी मूकदर्शक बना बैठा है। बिना अनुमति, बिना डायवर्सन और बिना बुनियादी सुविधाओं के प्लॉट बेचकर दलाल लोगों की जिंदगीभर की जमा पूंजी पर डाका डाल रहे हैं। आम नागरिक सस्ते प्लॉट के लालच में फंस जाते हैं, लेकिन बाद में बिजली, पानी, सड़क और बैंक लोन जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए दर-दर भटकते हैं। नियमों को ताक पर रखकर हो रही रजिस्ट्री इस पूरे खेल में मिलीभगत की ओर इशारा करती है। सवाल यह है कि आखिर कब तक लोगों की मेहनत की कमाई यूं ही लूटी जाती रहेगी और जिम्मेदार अफसर तमाशा देखते रहेंगे?

200 से 1500 रुपए वर्गफीट में प्लॉट

शासन-प्रशासन के सारे नियमों को ताक पर रखकर खेत-खलिहान की अवैध प्लॉट की खरीदी-बिक्री हो रही है। रोज कहीं ना कहीं अवैध कॉलोनी का नक्शा खींचा जा रहा है। नगर निगम रायपुर और बिरगांव सहित, मंदिरहसौद, आरंग और अभनपुर नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी बड़े स्तर पर अवैध प्लॉटिंग का खेल चल रहा है। नगर निगम, टाउन एंड कंट्री प्लान और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) को दरकिनार कर भूमाफिया प्लॉट बेच रहे हैं। अवैध निर्माण की वजह से शहर का सुनियोजित विकास नहीं हो पा रहा है। शहर का नक्शा तो बिगड़ ही रहा है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। चार साल में तकरीबन 50 हजार एकड़ भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की जा चुकी है और 200 से लेकर 1150 रुपए वर्गफीट में प्लॉट बेचे जा रहे हैं।

माफिया उड़ा रहे नियमों का मखौल, प्रशासन भी मौन

छत्तीसगढ़ में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग का मुख्य कार्य सुनियोजित शहरीकरण, मास्टर प्लान बनाना, अवैध कॉलोनियों पर नियंत्रण और भूमि उपयोग (लैंड यूज) को विनियमित करना है। यह विभाग नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत शहरों और गांवों के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करता है, जिससे अव्यवस्थित विकास को रोककर आधुनिक और टिकाऊ शहरों का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके। माफिया टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नियमों का माखौल उड़ा रहे हैं।

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की प्रमुख भूमिका और कार्य

- **मास्टर प्लान और विकास योजनाएं:** शहरों के सुव्यवस्थित विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उन्हें लागू करना, जैसे नवा रायपुर अटल नगर की योजना।
- **अवैध निर्माण पर रोक:** छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के तहत भूमि उपयोग का नियमन करना और अवैध प्लॉटिंग/कॉलोनियों को नियंत्रित करना।
- **लेआउट और बिल्डिंग प्लान की मंजूरी:** सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी विकासकर्ताओं के लिए लेआउट प्लान को मंजूरी देना और बिल्डिंग अनुमति प्रदान करना।
- **भूमि उपयोग में बदलाव:** कृषि भूमि को गैर-कृषि (आवासीय/व्यावसायिक) में परिवर्तित करने के लिए तकनीकी राय देना।
- **बुनियादी ढांचे का विकास:** सड़कों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए भूमि आरक्षित करना और नगर विकास योजनाओं में तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- **नई टाउनशिप का विकास:** नए औद्योगिक क्षेत्रों, आवासीय क्षेत्रों और टाउनशिप के लिए योजना बनाना (जैसे- रायपुर और नवा रायपुर को जोड़ने वाली कनेक्टिंग टाउनशिप)।
- **हाल ही में (2026),** छत्तीसगढ़ सरकार ने टाउन प्लानिंग की क्षमता बढ़ाने और अवैध प्लॉटिंग को रोकने के लिए नगर एवं ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक पारित किया है, जिसमें टाउन प्लानर्स की भर्ती के माध्यम से शहरी विकास को और अधिक पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है।

विधानसभा से पारित हुआ था नगर एवं ग्राम निवेश विधेयक-2026

रायपुर। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और सुव्यवस्थित विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी 19 मार्च 2026 को विधानसभा में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस संशोधन का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में अनियंत्रित विस्तार और अवैध प्लॉटिंग पर नियंत्रण स्थापित करते हुए योजनाबद्ध विकास को गति देना है। विधानसभा में बताया गया था कि राज्य गठन के बाद विभिन्न कारणों से प्रदेश के कई शहरों में अव्यवस्थित विकास और अवैध प्लॉटिंग की समस्या बढ़ी है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मध्यप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विभिन्न एजेंसियों की भागीदारी से नगर विकास योजनाओं के बेहतर परिणाम सामने आए हैं। विशेष रूप से अहमदाबाद में रिंग रोड जैसी प्रमुख परियोजनाएं योजनाबद्ध तरीके से विकसित की गई हैं। वित्त मंत्री चौधरी ने बताया कि संशोधन के तहत छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-38 में बदलाव किया गया है। इसके अनुसार अब नगर विकास योजनाएं तैयार करने के लिए अधिकृत एजेंसियों के दायरे का विस्तार किया जाएगा। विधानसभा में कहा गया था कि इस विधेयक का मूल उद्देश्य राज्य में सुनियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देना, अवैध प्लॉटिंग पर अंकुश लगाना है।

एससीआर प्लान से पहले जमीन पर हो रहा बड़ा खेल

रायपुर। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर नवा रायपुर, रायपुर व दुर्ग-भिलाई को आउटर से जोड़ने के लिए रेरट कैपिटल रीजन (एससीआर) के प्लान में अब जमीन का खेल शुरू हो चुका है। करीब 600 एकड़ क्षेत्रफल में जमीन अधिग्रहण का डर दिखाकर भूमाफिया किसानों से सौदा कर रहे हैं। इसकी वजह से अवैध प्लॉटिंग चरम पर है। नवा रायपुर से लेकर दुर्ग जिले के अमलेश्वर, दतरेरा, पाहंदा, झीट, सांकरा, मोतीपुर, पाटन रोड सहित खारून नदी किनारे, रायपुर से आरंग, अभनपुर, धरसीवा, खरोरा इलाके में भी तेजी से अवैध प्लॉटिंग हो रही है। दुर्ग-भिलाई से लगे ग्रामीण इलाकों के कृषि क्षेत्र में भूमाफिया सक्रिय हो चुके हैं। खेतों को छोटे-छोटे प्लॉट में काटकर बेचा जा रहा है। एससीआर का दायरा जहां प्रस्तावित है, वहां जमीनों की खरीदी-बिक्री सबसे ज्यादा जारी है। नवा रायपुर से लेकर दुर्ग-भिलाई आउटर तक जमीनों की कीमत प्रति एकड़ 3 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है।

शिकायत पर कार्रवाई भी हो रही

स्टेट कैपिटल रीजन का मास्टर प्लान अभी जारी नहीं हुआ है। यह प्रक्रियाधीन है। अवैध प्लॉटिंग रोकने के लिए नगरीय प्रशासन व स्थानीय निकायों को प्रशासन लेना चाहिए। शिकायत पर जिला प्रशासन कार्रवाई भी करता है।
– **देवेंद्र सिंह भारद्वाज,** विशेष सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग

'न नियम-न कानून: अवैध कॉलोनियों में डूब रही मेहनत की कमाई'

जयदेव सिंह. महासमुंद/नवप्रदेश। जिले में राजस्व विभाग, नगर पालिका और नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के बीच तालमेल की कमी या कथित मिलीभगत के चलते अवैध प्लाटिंग का खेल लगातार जारी है। मास्टर प्लान के दायरे में आने वाले पांचों ब्लॉकों के बावजूद आवासीय, व्यावसायिक या अन्य किसी भी प्रकार की भूमि से जुड़ी फाइलें नगर तथा ग्राम निवेश विभ ाग तक नहीं पहुंच रही हैं। इसका सीधा फायदा भू-माफिया और जमीन दलाल उठा रहे हैं, जबकि आम नागरिक अपनी जीवनभर की कमाई गंवाने को मजबूर हो रहे हैं।

क्या कहते हैं अधिकारी

संजू लाल सिंह, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश महासमुंद ने बताया कि 'जमीन के डायवर्सन की जानकारी विभाग को नहीं मिलती, जबकि निवेश क्षेत्र में यह जरूरी है। जानकारी के अभाव में लोग बिना जांच के जमीन खरीद लेते हैं।'

सुर्खियों में रमनटोला

- प्रशासन की मिलीभगत से 32 टुकड़ों में बंटी जमीन
- आम जनता ठगी का शिकार रमनटोला में 2019 से
- जिले में अवैध कॉलोनी निर्माण भी जारी
- बिना लेआउट स्वीकृति बेचे गए प्लॉट
- सड़क, पानी, नाली जैसी सुविधाओं से वंचित होंगे खरीदार।

रमनटोला बना अवैध कॉलोनी का केंद्र

केन्द्रीय विद्यालय के पास स्थित रमनटोला क्षेत्र में वर्ष 2019 से अवैध प्लाटिंग का खेल चल रहा है। यहां वेतना मालू (पति संजय मालू) के नाम दर्ज खसरा नंबर 1800 की जमीन को डायवर्सन कराकर छोटे-छोटे टुकड़ों में बेच दिया गया। बिना नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से लेआउट स्वीकृति लिए लगभग 32 लोगों को प्लॉट बेचे गए, जिससे एक बड़ी अवैध कॉलोनी अस्तित्व में आ गई।

मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहेंगे रहवासी

इस अवैध कॉलोनी में रहने वाले लोगों को सड़क, पानी, नाली, सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। क्योंकि कॉलोनी का विकास नगर पालिका या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की स्वीकृति के बिना किया गया है। ऐसे में कॉलोनाइजर की कोई जवाबदेही नहीं बनती और परेशानियों का सामना सीधे आम लोगों को करना पड़ेगा।

विभागों के बीच तालमेल का अभाव

नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के पास जमीन से जुड़ी पूरी जानकारी नहीं पहुंचती। वहीं नगर पालिका भी शिकायत मिलने के बाद ही कार्रवाई करती है। यही कारण है कि शहर के 30 वार्डों में अवैध कॉलोनियां तेजी से विकसित हो रही हैं। हाल ही में रायपुर रोड पर अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की गई, लेकिन रमनटोला में वर्षों से चल रहे इस खेल पर किसी की नजर नहीं पड़ी।

कैसे होता है अवैध प्लाटिंग का खेल

- अवैध प्लाटिंग की पूरी प्रक्रिया राजस्व विभाग से शुरू होती है।
- बड़े भू-भाग का डायवर्सन बिना पर्याप्त जांच के कर दिया जाता है।
- भूमि स्वामी द्वारा दिए गए लैंड यूज प्रमाण पत्र की पुष्टि नहीं की जाती।
- नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से समन्वय नहीं किया जाता। इसके बाद जमीन को छोटे-छोटे प्लॉट में काटकर ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता है।

2 से 10 एकड़ भूमि पर कॉलोनी बनाने के नए नियम लागू

महासमुंद। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में आवासीय विकास को बढ़ावा देने और छोटे स्तर पर कॉलोनी विकसित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 'छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम 2025' को 17 अक्टूबर 2025 से लागू कर दिया है। अब कृषि या आवासीय भूमि पर 2 से 10 एकड़ के बीच भी नियमानुसार कॉलोनी विकसित की जा सकती है।

क्या है नया प्रावधान

पहले मास्टर प्लान में दर्ज कृषि भूमि का सीधे आवासीय उपयोग में परिवर्तन संभव नहीं था, लेकिन अब नए नियम के तहत प्रस्तावित योजना के लिए स्वत: कृषि से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन माना जाएगा, बशर्ते निर्धारित शर्तों का पालन किया जाए।

स्थान से जुड़ी अनिवार्य शर्तें

- योजना स्थल के 1 किलोमीटर दायरे में 18 मीटर चौड़ी सड़क (प्रस्तावित या विद्यमान) होना जरूरी
- विकास योजना के अनुरूप क्षेत्र होना आवश्यक
- प्लॉट साइज और निर्माण नियम
- **प्लॉट का आकार:** 90 वर्गमीटर (968 वर्गफीट) से 150 वर्गमीटर (लगभग 1615 वर्गफीट) तक
- इससे बड़े प्लॉट की अनुमति नहीं
- **भवन की अधिकतम ऊंचाई:** 9 मीटर (रिटस्ट और पेंटहाउस छोड़कर)

आवश्यक सुविधाएं:

पानी, बिजली, जल निकासी (ड्रेनेज), सीवरेज व्यवस्था, आवेदन प्रक्रिया, कॉलोनी विकसित करने के इच्छुक व्यक्ति को नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन करना होगा

आवेदन पर संचालक द्वारा नियमों के अनुसार

- बिना शर्त अनुमति
- शर्तों सहित अनुमति या अनुमति से इंकार किया जा सकता है

कानूनी प्रावधान और धाराएं

प्राप्त आवेदनों पर निम्न धाराएं लागू होंगी: धारा 16, धारा 30, 30(क), धारा 31, धारा 32, धारा 33

इन्फ्रास्ट्रक्चर की अनिवार्य व्यवस्था

- **कॉलोनी तक पहुंच मार्ग:** कम से कम 25 फीट चौड़ा
- **कॉलोनी के अंदर सड़क:** कम से कम 20 फीट चौड़ी
- कुल भूमि का 5% हिस्सा सामुदायिक खुला स्थान के लिए आरक्षित
- यह क्षेत्र 250 वर्गमीटर (2690 वर्गफीट) से कम नहीं होना चाहिए

इनके अंतर्गत

- भू-उपयोग परिवर्तन
- अनुमति में संशोधन
- अपील और पुनरीक्षण
- अनुमति की वैधता
- अनुज्ञा अन्य जरूरी नियम
- कॉलोनाइजर को सभी अनुमतियों के बाद भू संपदा विनियमन एवं विकास अधिनियम 2016 का पालन करना अनिवार्य साथ ही छत्तीसगढ़ भू संपदा नियम 2017 भी लागू होंगे

एक नजर में पूरी जानकारी

- **नियम लागू:** 17 अक्टूबर 2025
- **भूमि सीमा:** 2 से 10 एकड़
- **प्लॉट साइज:** 90 से 150 वर्गमीटर
- **अधिकतम ऊंचाई:** 9 मीटर
- **मुख्य सड़क:** 25 फीट
- **आंतरिक सड़क:** 20 फीट
- **खुला क्षेत्र:** 5% (कम से कम 250 वर्गमीटर)

एक किमी में 18 मीटर सड़क जरूरी

आवेदन: नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय में ऑफलाइन
रेरा नियम लागू: अनिवार्य
नए नियमों से छोटे डेवलपर्स और जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। अब सीमित भूमि पर भी नियमानुसार कॉलोनी विकसित कर किफायती आवास उपलब्ध कराना आसान होगा।

अवैध प्लाटिंग का जाल: फंस रहे लोग, मालामाल हो रहे दलाल

सुशील शुक्ला

मुंगेली/नवप्रदेश। लगातार हो रही कार्यवाहियों के बाद भी नगर में चल रहे भूमाफियाओं का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कौडी के मूल्य में किसानों और जरूरतमंदों की जमीन लेकर लाखों कमाने वाले इन जमीन दलालों पर कानूनी शिकंजा कसना तो महज सपना बन गया है। ऊंची पहुंच और राजनीतिक रसूख के दम पर ये अपने काम को बखूबी अंजाम देते हैं। अवैध प्लाटिंग के जाल में लोग फंस रहे हैं और दलाल मालामाल हो रहे हैं।

मुंगेली में चल रहे भूमाफियाओं की करतूतों के चलते अब शहर की सरकारी जमीनें भी सुरक्षित नहीं रह गई है। कुछ समय पहले तक जहां किसानों की जमीनों को कम दामों में खरीद कर बेचते इन भूमाफियाओं के हौसले इतने बढ़ने लगे की इन लोगों ने शहर की सरकारी जमीनों को तक नहीं बक्शा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगर इन दलालों के खिलाफ कोई किसी प्रकार की आवाज उठाता है तो अपने पहुंच के चलते ये किसी भी मामले पर फंसाने से भी नहीं चुक रहे हैं। हर जरुरतमंदों और गरीबों का एक सपना होता हैं कि उनका स्वयं का एक अच्छा, सुविधानुसार मकान हो, स्वयं का मकान होने का सपना देखने वालों को भूमाफियाओं और जमीन दलालों ने लूटने के अलावा कुछ नहीं किया है। इन भूमाफियाओं और जमीन दलालों के द्वारा जमीन खरीदने वालों को कम कीमत पर प्लाट देने का लालच देकर उन्हें अंधेरे में रखा जा रहा है और ग्राहक भी जानकारी व नियम कायदे के अभाव में इन भूमाफियाओं के चंगुल में लगातार फंसता जा रहा है।

सरकारी कार्यालयों और आवासो के जमीन तलाशता प्रशासन-जिला बनने के लगभग 14 सालो बाद भी सरकारी आवासो और कार्यालयो के लिए जमीन की तलाश जारी है वर्तमान में जिले में लगभग 52 विभाग संचालित है जिसमें से ज्यादातर विभाग जिला कलेक्ट्रेट में लग रहे है, इसके अलावा लगभग 5 से 10 कार्यालय उधार की बिल्डिंग एवं किराये के भवनो में संचालित हो रहे है जिससे राजस्व की हानि हो रही है। जमीनो की कमी के चलते जहां आवास की उपलब्धता कम है वही अविभाजित बिलासपुर जिले के कई कार्यालय आज भी बिलासपुर से संचालित है।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक प्रधान संपादक यशवंत धोटे द्वारा, मिनल पब्लिकेशन एंड प्रोडक्शन प्रा.लि. शेड नंबर 74, सेक्टर-सी, उरला इंडस्ट्रीयल एरिया रायपुर, से मुद्रित कर तृतीय तल, सुपर मार्केट कॉम्प्लेक्स, राजा रघुराज सिंह स्टेडियम के सामने अग्रसेन चौक, बिलासपुर से प्रकाशित, RNI NO.CHHHIN/2015/62431, संपादक-चन्द्रशेखर* (पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के लिए उत्तरदायी), स्थानीय संपादक-विक्रम सिंह ठाकुर, समाचार संपादक-संदीप दीवान, फोन नंबर : 07752-468654, navpradeshbilaspur01@gmail.com